चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 18 जुलाई–24 जुलाई 2011 | मूल्य 5 रुपये

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला ऐतिहासिक है

पेज-3

मदद के नाम पर धोखा

पेज-4

जीवन में ख़ुशहाली कब आएगी

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

भाजपा में बहुत दम है..

प्रजातंत्र में विपक्ष की पूंजी विश्वसनीयता होती है. विपक्षी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा होना चाहिए, जिससे जनता को यह लगे कि यह वर्तमान सरकार से बेहतर सरकार दे सकती है. सरकार कितनी भी भ्रष्ट हो, अगर देश में तेज़तर्रार विपक्ष मौजूद रहे तो जनता का सरकारी तंत्र में भरोसा बना रहता है. विपक्ष का काम ही यही है कि वह पांच साल तक जनता के मुद्दों, उनकी परेशानियों और मुश्किलों केलिए लड़े. भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की इस ज़िम्मेदारी को ही नहीं समझ सकी. भाजपा अगर भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन और किसानों की ज़मीन को लेकर कोई व्यापक आंदोलन करती तो आज लोगों में निराशा नहीं होती. भारतीय जनता पार्टी की ग़लतियों की वजह से पूरा पॉलिटिकल क्लास ही सवालों के घेरे में आ गया. यह आम धारणा बन गई है कि सरकार भ्रष्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, यह आगे पढ़िए...

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

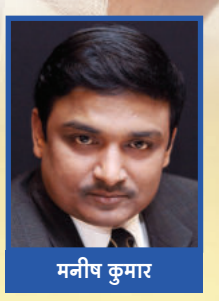

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विथ डिफरेंस के बजाय पार्टी इन डिलेमा बन गई है. दूसरे दलों से अलग होने का दंभ भरने वाली पार्टी अब असमंजस और विरोधाभास से ग्रसित हो चुकी है. वह भीषण गुटबाज़ी की चपेट में है, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से दूर होते जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में दूरियां बढ़ गई हैं. पार्टी के अंतर्द्वंद्व का हाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष का कोई बयान आता है तो पार्टी के दूसरे नेता नाराज़ हो जाते हैं. नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष में महीनों बातचीत ही नहीं होती. अध्यक्ष सबकी राय सुनने के चक्कर में कोई निर्णय नहीं कर पाते. कोई प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान दे देता है तो पूरी पार्टी उसके पीछे लग जाती है. कोई युवा नेता कोई आंदोलन करना चाहता है तो उसे बड़े नेता हाईजैक कर ले जाते हैं. हर नेता दूसरे नेता को ठिकाने लगाने में जुटा हुआ है. जिससे हिसाब चुकाना है, उसे पहले ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, फिर पीछे से उसे विफल करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं. देश के मुख्य विपक्षी दल का हाल ऐसा है कि उसके कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में बैठकर पार्टी को ही कोसते रहते हैं.

भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रभात झा ने एक चिट्ठी लिखी. सही लिखा. यह चिट्ठी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के नाम थी. इस चिट्ठी में प्रभात झा ने महंगाई को मौत के बराबर बताते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी. उन्होंने लिखा कि लगातार बढ़ती महंगाई में ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, लिहाज़ा उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और विरोध का यही तरीक़ा बचता है. प्रभात झा ने दलील दी कि कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ने 100 दिनों में महंगाई कम करने का भरोसा दिलाया था, मगर सत्ता हासिल करने के सात साल बाद भी महंगाई पर क़ाबू नहीं पाया जा सका, बल्कि महंगाई मौत का पर्याय बन चुकी है. देश के 115 करोड़ लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं. इतना ही नहीं, उनके लिए यह महंगाई समस्या बन चुकी है और इससे छुटकारा पाने के लिए वह इच्छा मृत्यु चाहते हैं. प्रभात झा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा अपनी पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली को भी चिट्ठी की कॉपी भेज दी. इस चिट्ठी से पॉलिटिकल सर्किल और मीडिया में हंगामा मच गया. अख़बारों में तरह–तरह की बातें लिखी गईं. किसी ने कहा नौटंकी है, किसी ने कहा ड्रामा है और किसी ने इसे महंगाई के मुद्दे पर पब्लिसिटी बटोरने के लिए नया शिगूफ़ा बताया. कांग्रेस पार्टी इस चिट्ठी का मज़ाक़ उड़ाए, मीडिया अपने तरीक़े से इसका विश्लेषण करे, यह तो समझ में आता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रभात झा को इस चिट्ठी को लेकर अपनी ही पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है.

दरअसल, इस चिट्ठी के पीछे एक कहानी है. जब पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए तो प्रभात झा भावुक हो गए. उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से बात की. उन्होंने यह इच्छा जताई कि वह राष्ट्रपति के नाम इस तरह की चिट्ठी लिखना चाहते हैं. नितिन गडकरी ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन चिट्ठी आते ही पार्टी के अंदर हंगामा मच गया. यह चिट्ठी पार्टी के उन नेताओं को चुभ गई, जो दिल्ली मुख्यालय में बैठकर पार्टी की रणनीति तय करते हैं. उन्हें लगा कि प्रभात झा ऐसा करके पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं. 9, अशोक रोड (भाजपा मुख्यालय) की परिपाटी के मुताबिक़ मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होने लग गई. नेताओं ने संवाददाताओं को यह बताना शुरू किया कि राजनीति करने का यह अच्छा तरीक़ा नहीं है. मीडिया ने इस चिट्ठी का मखौल उड़ा दिया. हालांकि इस बात का कौन जवाब दे कि चिट्ठी में लिखी गई बात सौ फ़ीसदी सच है. देश के 75 फ़ीसदी से ज़्यादा लोगों की आमदनी 40–50 रुपये प्रतिदिन है. उनकी आमदनी का लगभग पूरा हिस्सा ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भोजन पर ख़र्च होता है. ऐसे में जब खाने–पीने का सामान महंगा हो जाता है तो देश की यह आबादी क्या करे, कैसे ज़िंदा रहे. पार्टी को प्रभात झा की चिट्ठी का मज़ाक़ बनाने के बजाय उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने इस चिट्ठी को ही सेंसर कर दिया. संगठन में यह बात पहुंचा दी गई कि इस चिट्ठी का कहीं भी ज़िक्र नहीं होना चाहिए.

भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध से तो ग्रसित है ही, साथ ही पार्टी में एक परंपरा बनती जा रही है कि जो भी जनता के नज़दीक जाता है, जो जनता के दु:ख–दर्द को बांटने जाता है, जो जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है, जो जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश करता है, उसे पार्टी में दरकिनार कर दिया जाता है. जितने भी ज़मीनी नेता थे, वे दरकिनार कर दिए गए हैं. जो उभरना चाहते हैं, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है. प्रभात झा जबसे मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने हैं, तबसे वह लोगों के बीच घूम–घूमकर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री से ज़्यादा मीडिया कवरेज प्रभात झा को मिल रहा है. प्रभात झा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक ज़मीनी स्तर का राष्ट्रीय नेता मिल सकता है. शायद पार्टी को ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनकी चिट्ठी का मज़ाक़ उड़ा दिया गया. प्रभात झा की चिट्ठी को कोई ड्रामा तो कह सकता है, लेकिन यह कौन झुठला सकता है कि महंगाई ने देश की ग़रीब जनता को मौत के कगार पर खड़ा कर दिया है. इस घटना से पार्टी की मानसिकता समझ में आती है कि क्यों देश के ज्वलंत मुद्दों पर वह सिर्फ़ नाम के लिए विरोध प्रदर्शन करती है. पार्टी के रवैये से यह समझ में आता है कि वह किसानों के आंदोलन में खुलकर हिस्सा क्यों नहीं लेती, क्यों महंगाई पर जनता के साथ खड़ी नज़र नहीं आती, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं करती और काले धन के मुद्दे पर सिर्फ़ टीवी चैनलों पर बहस क्यों करती है? लगता तो यही है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी जनता से दूरी बनाने में विश्वास करने लगी है. दिल्ली में बैठे नेताओं के पास कार्यकर्ताओं के लिए वक़्त नहीं है और कार्यकर्ता आम जनता के सामने जाते नहीं, क्योंकि उनमें हौसला नहीं बचा है. पार्टी में दम नहीं रहा. इसका परिणाम यह है कि पार्टी ज़मीन से कट गई है.

यह देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे ख़तरनाक संकेत है. भारतीय जनता पार्टी चिंतित, भ्रमित, असंगठित, दिशाहीन और बिखरी नज़र आ रही है. नेताओं का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, लोकपाल जैसे मुद्दों पर नहीं है. आडवाणी के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शीतयुद्ध चल रहा है. इस युद्ध को चार महत्वपूर्ण घटनाओं से समझा जा सकता है.

पहला विवाद सुषमा स्वराज से जुड़ा है, जब उन्होंने सीवीसी पी जे थॉमस की नियुक्ति को लेकर बयान दिया था. दूसरा विवाद महाराष्ट्र के नेता गोपीनाथ मुंडे से जुड़ा है, जब उन्होंने पार्टी छोड़ने की धमकी दी. तीसरा मामला है राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाने का और चौथा उमा भारती की वापसी. कुछ समय पीछे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यह देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे ख़तरनाक संकेत है. भारतीय जनता पार्टी चिंतित, भ्रमित, असंगठित, दिशाहीन और बिखरी नज़र आ रही है. नेताओं का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, लोकपाल जैसे मुद्दों पर नहीं है. आडवाणी के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शीतयुद्ध चल रहा है.

आज देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई से त्रस्त है. देश एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जहां बदलाव अवश्यंभावी है. इतिहास बहुत ही क्रूर होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता. इस मंथन में जो तटस्थ रहेगा, वह इतिहास में उपहास का पात्र बनेगा. चुनाव जीतना तो दूर, उसके अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है.

अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह रवैया आश्चर्यजनक है, जबकि दोनों अधिकारी एजीएमयूटी कैडर के हैं और गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच इनका ट्रांसफर तो एक रुटीन मामला है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

काम के बोझ के मारे

प्रवर्तन निदेशालय की जांच की गति कुछ शिथिल होती दिख रही है. इसका कारण हाई प्रोफाइल मुकदमों से निपटने का दबाव अथवा काम की अधिकता हो सकता है. निदेशालय पर हसन अली मनी लांड्रिंग, 2–जी स्पेक्ट्रम, आईपीएल, कॉमनवेल्थ और हाल में चर्चा में आए 400 करोड़ के बैंक घोटाले की जांच का भार है. जानकारी के अनुसार, पिछले तीन महीने में कम से कम 10 अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है. 6 अधिकारियों ने तो गत माह संबंधित कागजात भी सौंप दिए. विश्लेषकों का मानना है कि उक्त बाबू, जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति चाह रहे हैं, उसका कारण यह नहीं है कि उन्हें निजी क्षेत्र में अच्छे अवसरों की तलाश है, बल्कि संवेदनशील मामलों की जांच और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाना उनके लिए कठिन हो रहा है. ऐसे में उन्हें लग रहा है कि वर्क लोड कम होने के आसार फ़िलहाल नहीं हैं, इसलिए रिटायरमेंट लेना ही बेहतर है. ऐसे में उन नियुक्तियों को बल मिल सकता है, जो लंबे समय से लंबित हैं. निदेशालय में 1400 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना जरूरी है.

मझधार में बाबू

दो बाबुओं के सामान्य तौर पर किए गए अंतरराज्यीय तबादलों से आखिर ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया. गृह मंत्रालय ने दो अधिकारियों वी के देव और पवन के सेन की पोस्टिंग 6 माह पूर्व गोवा कर दी थी, लेकिन वे अभी तक अपना नया कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने उन्हें रिलीव करने से इंकार कर दिया है. जानकारों का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह रवैया आश्चर्यजनक है, जबकि दोनों अधिकारी एजीएमयूटी कैडर के हैं और गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच इनका ट्रांसफर तो एक रुटीन मामला है. मज़े की बात यह है कि राज्य सरकार ने यह भी नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया है, जबकि गृह मंत्रालय उसे बार–बार रिमाइंडर भेजकर पूछ रहा है कि उसने तबादले के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्या कोई बता सकता है कि यह खेल कब तक चलता रहेगा?

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

शर्मा का प्रमोशन

शिकांत शर्मा को रक्षा मंत्रालय में सचिव बनाए जाने से वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद रिक्त हो गया है. 1978 बैच के आईएएस राकेश सिंह, जो इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को सचिव बनाया जाना तय है.

मीणा एएस बने

1980 बैच और मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रभु दयाल मीणा को भू–संसाधन विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. उन्हें चिन्मय बसु की जगह नियुक्त किया गया है.

सेबी में नए सदस्य

सेंट्रल बैंक के पूर्व सीएमडी एस श्रीधर और 1983 बैच के आईआरएस अधिकारी राजीव अग्रवाल को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाएगा. वे क्रमश: एम एस साहू और के एम अब्राहम का स्थान लेंगे.

दो नए जेएस

1985 बैच की आईए एंड एएस अधिकारी नमिता सखोन और जे एम मेनन के नाम शीघ्र ही सीएसएस के तहत संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद पर लाने के लिए बनी सूची में शामिल किए जा सकते हैं.

राकेश योजना आयोग पहुंचे

1988 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश सरवाल को योजना आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार नियुक्त किया गया है. यह पद संयुक्त सचिव के समकक्ष है. सरवाल पूर्व में आयुष विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे.

भाजपा में बहुत दम है..

पृष्ठ एक का शेष

चलते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई. आडवाणी जी का सपना चकनाचूर हो गया, तब आरएसएस ने कहा कि पार्टी को सर्जरी की ज़रूरत है. इसलिए उसने नितिन गडकरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया. यह सोचकर बनाया कि पार्टी में विचारधारा को पुन: स्थापित किया जाएगा, गडकरी पार्टी संगठन को मज़बूत करेंगे और पार्टी की अंतर्कलह को ख़त्म करेंगे. नितिन गडकरी को अध्यक्ष बने अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन पार्टी में कोई बदलाव नहीं आया. एक ही मुद्दे पर अलग–अलग सदनों में भाजपा का अलग–अलग स्टैंड होता है. यह इसलिए, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज में अब तक तालमेल नहीं बैठ पाया है. नितिन गडकरी दोनों में सुलह कराने में कामयाब नहीं रहे.

सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बीच काफ़ी समय से शीतयुद्ध चल रहा है. दोनों आडवाणी का उत्तराधिकारी बनने की अभिलाषा रखते हैं. अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी की दोस्ती है. यही वजह है कि बिहार चुनाव के दौरान एक बार सुषमा स्वराज ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में ही चलता है. सुषमा के बयान पर मोदी नाराज़ थे. इस बात को लेकर मोदी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी शिक़ायत की थी. इस विवाद पर न तो आडवाणी कुछ बोले और न नितिन गडकरी. अब स्थिति बदल गई है. नितिन गडकरी अब अरुण जेटली की बात सुनते हैं. इसी वजह से सुषमा स्वराज के ख़ेमे को अब सिर्फ़ आडवाणी जी ही सुनते हैं. सुषमा स्वराज ने सीवीसी पी जे थॉमस की नियुक्ति को लेकर यह बयान दिया था कि जब सरकार ने ग़लती मान ली है तो यह मामला अब ख़त्म हो गया है. अगले ही दिन नितिन गडकरी ने मीडिया को बताया कि वह इस मामले को जनता में लेकर जाएंगे और यह मामला ख़त्म नहीं हुआ है. वैसे गडकरी या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर जनता में नहीं गए, लेकिन यह संदेश ज़रूर दे दिया गया कि सुषमा स्वराज की बातों की अहमियत पार्टी में नहीं है. गडकरी और सुषमा स्वराज के रिश्ते में खटास है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं कि सुषमा स्वराज, अनंत कुमार एवं गोपीनाथ मुंडे का एक अलग कैंप है और नितिन गडकरी, अरुण जेटली एवं उमा भारती का दूसरा खेमा है. इसलिए गोपीनाथ मुंडे का मामला उठा था. उनकी शिकायत यह थी कि उनकी बातों को पार्टी में कोई नहीं सुनता है. सुषमा स्वराज की

कमज़ोरी यह है कि उन्हें आरएसएस का समर्थन नहीं है. उन्हें आडवाणी जी के अनुरोध पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था. गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के नेता है, पार्टी के एकमात्र बड़े ओबीसी लीडर हैं. वह स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बहनोई भी हैं. प्रमोद महाजन के निधन के बाद पार्टी में उनकी हैसियत में कमी आई है. नितिन गडकरी का कद गोपीनाथ मुंडे से छोटा था, लेकिन अब वह पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं. नितिन गडकरी का महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देना स्वाभाविक है. दोनों में शीतयुद्ध चल रहा है. इससे उमा भारती की वापसी का राज समझ में आता है. उमा भारती की वापसी का विरोध शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा सुषमा स्वराज कर रही थीं. अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने उमा भारती की वापसी के ज़रिए एक ही तीर से कई निशाने साधे. सुषमा स्वराज और गोपीनाथ मुंडे को साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि पार्टी को उमा भारती के रूप में एक महिला और एक ओबीसी लीडर मिल गया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ख़ुश कर दिया गया, क्योंकि वह कई महीने से उमा भारती को वापस लेने का दबाव बना रहा था.

उमा भारती की वापसी से जेटली कैंप ने उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन फैला दिया. आडवाणी का उत्तराधिकारी बनने के एक और दावेदार हैं राजनाथ सिंह. बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह के स्वर मिल रहे थे. राजनाथ सिंह इस कोशिश में थे कि कलराज मिश्र को उत्तर प्रदेश में आगे रखा जाए. इसके पीछे राजनाथ सिंह की यह मंशा हो सकती है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए राज्यों के चुनाव का ज़िम्मा कलराज मिश्र को देने में कोई आपत्ति नहीं है. अरुण जेटली ने पहले उमा भारती को उत्तर प्रदेश में लगा दिया. कई राज्यस्तरीय नेता नाराज़ हुए, फिर राजनाथ सिंह को चुनाव प्रभारी बना दिया गया. कलराज मिश्र नाराज़ हो गए. उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन

है. अजीबोगरीब स्थिति है. अब उत्तर प्रदेश में तीन–तीन दिग्गज मौजूद हैं तो इगो क्लैश होना स्वाभाविक है. वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को पता है कि उत्तर प्रदेश में मनमुताबिक़ नतीजे आने वाले नहीं हैं. यही अरुण जेटली की रणनीति है कि चुनाव नतीजे आने के बाद राजनाथ सिंह पर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और वह आडवाणी का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे. सुषमा स्वराज और बाकी लोग तो पहले से ही साइड लाइन कर दिए गए हैं.

किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं के बीच प्रतियोगिता होना अच्छी बात है. यह प्रतियोगिता सकारात्मक हो तो पार्टी के लिए बेहतर है. इससे दल मज़बूत होता है, लेकिन इसके लिए भी एक समय होता है. आज देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई से त्रस्त है. देश एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जहां बदलाव अवश्यंभावी है. इतिहास बहुत ही क्रूर होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता. इस मंथन में जो तटस्थ रहेगा, वह इतिहास में उपहास का पात्र बनेगा. भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि इस दौर में वह अपनी विश्वसनीयता खो रही है. अगर वह तटस्थ रही तो चुनाव जीतना तो दूर, उसके अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है. कार्यकर्ता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई बड़ा फ़ैसला होगा और पार्टी देश में बदलाव के लिए कोई बड़ा आंदोलन करेगी. राजनीति को जो भी समझते हैं, उन्हें पता है कि यह जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का वक़्त है. किसान, मज़दूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक और युवा सभी आंदोलित हैं. भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि यह वक़्त आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि जनता के साथ क़दम से क़दम मिलाकर मैदान में उतरने का है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 19
दिल्ली, 18 जुलाई –24 जुलाई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

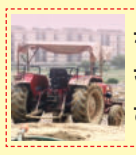

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया, जब इस देश में भूमि अधिग्रहण क़ानून को लेकर काफ़ी गहमागहमी का माहौल है.

अदालत, अधिग्रहण और आम आदमी

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला ऐतिहासिक है

न कार्यपालिका, न विधायिका, बस उम्मीद थी तो सिर्फ़ न्यायपालिका से और उम्मीद टूटी भी नहीं. एक फ़ैसले से लाखों लोगों के सपने फिर से जिंदा हो गए. अब कंक्रीट के जंगल के बजाय उनके खेतों में फिर से फ़सलें लहलहाएंगी. ज़मीन और किसान का अटूट रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा. इस एक फ़ैसले से यह उम्मीद भी जगी कि सवा सौ साल पुराने और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले क़ानून के दिन शायद अब लदने वाले हैं.

- **सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में 156 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण को रद्द किया**
- **कहा, जनहित के नाम पर किसानों की ज़मीन बिल्डरों को दी जा रही है**
- **इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के ज़मीन अधिग्रहण को रद्द किया**
- **सवा सौ साल पुराना है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894**

शशि शेखर

ज़मीन वह संपत्ति है, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बस हस्तांतरित करती है यानी कोई इसका मालिक नहीं होता. हां, केयर टेकर कह सकते हैं. ज़मीन और किसान के बीच कुछ ऐसा ही संबंध था. लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण और निजीकरण की आंधी आने के साथ ही ज़मीन और किसान के इस सनातन संबंध को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जाने लगा, जो सरकार, ब्यूरोक्रेसी और उद्योगपतियों की साठगांठ का नतीजा था. कभी सेज के नाम पर, कभी औद्योगिक विकास के नाम पर, टाउनशिप के नाम पर, यहां तक कि सड़क (एक्सप्रेस–वे) बनाने के नाम पर सरकार ने किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने का काम किया. सस्ती दरों पर ज़मीन लेकर सरकार पूंजीपतियों को उसे बेचने लगी यानी सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर बन गई. ज़मीन की दलाली होने लगी. हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर ज़मीन ख़रीद कर वह बिल्डरों, उद्योगपतियों को दस हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचने लगी. पूंजीपति इस ज़मीन से अरबों–खरबों की कमाई करने लगे और इस काम में सरकार की सहायता के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला क़ानून यानी भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 तो था ही.

लेकिन शुक्र मनाइए कि इस देश में एक संस्था ऐसी है, जिसे इस देश के किसानों, आम जनता की चिंता है. धन्यवाद कहिए इस देश की सर्वोच्च अदालत को, जिसके ऐतिहासिक फ़ैसले से न सिर्फ़ फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशियां आई हैं, बल्कि यह उम्मीद भी जगी है कि ज़मीन और किसान के बीच के रिश्ते को तोड़ने वाले काले क़ानून से भी निकट भविष्य में मुक्ति मिल सकेगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 156 हेक्टेयर ज़मीन के अधिग्रहण के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ–साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों को भूमि आवंटन के मामले में क़ानून की अनदेखी की. सरकार के मुताबिक़ अधिग्रहण जल्दी करना जरूरी था, लेकिन अदालत ने इस दलील को मानने से इंकार कर दिया. अदालत का कहना था कि ज़मीन के मालिकों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था.

ज़मीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने क्या–क्या हथकंडे अपनाए होंगे, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी से ही लग जाता है, जिसमें उसने कहा कि सरकार ज़मीन छीनने में लगी है और जिसकी वजह से किसानों की कई पीढ़ियों का जीवन प्रभावित हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि जनहित और औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन ली जा रही है, लेकिन यह ज़मीन बिल्डरों को दी जा रही है और इसका आम आदमी की ज़रूरतों से कोई लेना–देना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना सरकारी अनुमति के ही बिल्डरों के साथ डील करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका और अथॉरिटी को ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में अधिग्रहीत की गई 157 हेक्टेयर ज़मीन किसानों को वापस लौटाने का आदेश दिया. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही इस अधिग्रहण को अवैध घोषित कर दिया था. इसके बाद कई बिल्डरों सहित ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखा. बहरहाल, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर चल रही राजनीति,

इस देश के तीन मुख्य स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच फर्क को समझने की जरूरत है. इनकी कार्यशैली, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है. राजनीति से जुड़े लोग जहां भूमि अधिग्रहण कानून के बहाने सत्ता हासिल करना चाहते हैं, विधायिका सवा सौ साल पुराने काले कानून को अब तक ढोती आ रही है, वहीं न्यायपालिका ने अपने एक आदेश से यह संदेश दे दिया कि आज देश की जनता की सच्ची हिमायती वही है.

पदयात्रा, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अगले ही दिन एक और ज़मीन अधिग्रहण को रद्द करने का फैसला आ गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील में हुए 20 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण को निरस्त कर दिया. यह अधिग्रहण सात साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके किया गया था, लेकिन अब तक उक्त ज़मीन पर एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकी थी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 को लागू करके भूमि का अधिग्रहण किया गया था और ज़मीन मालिकों को आपत्ति दर्ज कराने का मौक़ा भी नहीं दिया गया.

ज़ाहिर है, अदालत के इस आदेश के बाद वैसे किसान भी, जिनकी ज़मीन का अधिग्रहण अवैध ढंग से हुआ है, अदालत से न्याय मांग सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला किसी नजीर से कम नहीं है. इस फ़ैसले से कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति ए के पटनायक ने भूमि अधिग्रहण के मसले पर कहा था कि सरकार प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है. भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अब देश को और नंदीग्राम नहीं चाहिए. सरकारें किसानों की कृषि योग्य ज़मीनें बिल्डरों को देती रहें और हम आंखें मूंदे बैठे रहें, अब ऐसा नहीं होगा. आप एक पक्ष से खेती लायक ज़मीन लेकर दूसरे को दे देते हैं, यह ख़त्म होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा. इस पीठ ने सरकार से पूछा था कि अधिग्रहीत ज़मीन पर बनने वाले मकान किसके फ़ायदे के लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी क़ीमत क्या है?

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया, जब इस देश में भूमि अधिग्रहण क़ानून को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी तो बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पदयात्रा पर थे. वह भूमि अधिग्रहण की समस्या को समझने की बात कर रहे थे. उन्होंने किसानों से मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन बिल लाने का वायदा भी किया. वहीं विपक्ष के लिए यह एक राजनीतिक स्टंट था. लेकिन यहीं पर राजनीति (एक संस्था के तौर पर) और न्यायपालिका के बीच या कहें कि इस देश के तीन मुख्य स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच फ़र्क़ को समझने की ज़रूरत है. इनकी कार्यशैली, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को समझने की ज़रूरत है. राजनीति से जुड़े लोग जहां भूमि अधिग्रहण क़ानून के बहाने सत्ता हासिल करना चाहते हैं, विधायिका सवा सौ साल पुराने काले क़ानून को अब तक ढोती आ रही है, वहीं न्यायपालिका ने अपने एक आदेश से यह संदेश दे दिया कि आज देश की जनता की सच्ची हिमायती वही है.

राहुल गांधी और विपक्ष को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों यूपीए–1 के शासनकाल में संशोधित भूमि अधिग्रहण क़ानून संसद से पास नहीं हुआ, क्यों यह संशोधन लोकसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया? ख़ैर, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आशा की जा सकती है कि सरकार इस बार भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के लिए संसद में फिर से एक बिल लाएगी और इस बार यूपीए सरकार को प्रस्तावित संशोधनों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में ही करने होंगे.

shashishekhar@chauthiduniya.com

हैरानी इस बात है कि यह छात्रवृत्ति योजना लागू हुए तीन साल हो चुके हैं, बावजूद इसके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं.

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

मदद के नाम पर धोखा

डॉ. क़मर तबरेज़

भारत में मूल शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे देश में क़ानून तो बना दिए जाते हैं, पर उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता. परिणामस्वरूप क़ानून होते हुए भी आम नागरिक उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाते. शिक्षा का भी कुछ यही हाल है. यूपीए सरकार ने 4 अगस्त, 2009 को संसद में शिक्षा अधिकार विधेयक पारित किया था, जिसके बाद भारतीय संविधान की धारा 21-ए के तहत देश के 6-14 साल की उम्र के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करने को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था. यह क़ानून देश में एक अप्रैल, 2010 से लागू हो चुका है, लेकिन हालत यह है कि बच्चे हैं तो क्लास रूम नहीं, क्लास रूम हैं तो अध्यापक नहीं, अध्यापक हैं तो बच्चों के बैठने के लिए मेज़-कुर्सियां नहीं. मानो सारा काम राम भरोसे चल रहा है. कई जगह तो यह हाल है कि जिन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें ख़ुद नहीं मालूम कि क्या पढ़ाना है. बिहार सरकार ने शिक्षा मित्र के नाम से सैकड़ों अध्यापकों की नियुक्ति की थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिक्षामित्रों को यह तक नहीं मालूम कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है या फिर सेब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं. अगर यह मालूम भी है कि सेब को अंग्रेज़ी में एप्पल कहते हैं तो उसकी सही स्पेलिंग नहीं आती. ऐसे में हम ख़ुद देश के बच्चों के भविष्य का भलीभांति अनुमान लगा सकते हैं कि वह उज्ज्वल होगा या अंधकारमय.

यह तो रही आम शिक्षा की हालत या दूसरे शब्दों में शिक्षा के मौलिक अधिकार की ज़मीनी हक़ीक़त. अब आइए देखते हैं भारत के मुस्लिम बच्चों की हालत क्या है. हम सभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पूरी तरह वाक़िफ़ हैं कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने यूपीए सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें उन्होंने ख़ासकर मुसलमानों के बारे में बताया था कि भारतीय मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दलितों से भी पिछड़े हैं अर्थात सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समुदाय के विकास की ओर विशेष ध्यान दे. उन्होंने अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष पेश किए थे, जिनमें से एक यह था कि देश के अंदर जहां-जहां मुसलमानों की बाहुल्यता है, वहां शिक्षा की व्यवस्था की जाए, स्कूल स्थापित किए जाएं, हॉस्टल बनवाए जाएं और शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए ग़रीब मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए. इस प्रस्ताव पर अमल करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2008-09 के दौरान देश के अंदर शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को 5,95,000 छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने की एक योजना की घोषणा की थी, ताकि वे अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकें. अल्पसंख्यक मंत्रालय ने योजना के तहत तीन श्रेणियों में छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी, प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट कम मींस छात्रवृत्ति. प्री-मैट्रिक श्रेणी में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को रखा गया था, जबकि पोस्ट मैट्रिक श्रेणी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा पाने वाले छात्रों को. वहीं मैरिट कम मींस छात्रवृत्ति में टेक्निकल, प्रोफेशनल और वोकेशनल शिक्षा पाने वाले छात्रों को शामिल किया गया.

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सरकार ने प्रवेश शुल्क के रूप में 500 रुपये और ट्यूशन फीस के तौर पर 350 रुपये वार्षिक भुगतान करने की घोषणा की थी. इसके अलावा छठी से दसवीं कक्षा तक के उन बच्चों, जो हॉस्टल में रहते हैं, को हर माह 600 रुपये, जबकि पहली से दसवीं कक्षा तक के डे-स्कॉलर को 100 रुपये महीने रखरखाव भत्ते के रूप में देने की घोषणा की गई थी. इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11वीं से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा पाने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी. इसके तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों की प्रवेश/ट्यूशन फीस के रूप में 7000 रुपये, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर टेक्निकल/वोकेशनल कोर्स के लिए 10000 रुपये और स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 3000 रुपये वार्षिक देने का वायदा किया गया था. हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को 235 से 550 रुपये और डे-स्कॉलर को 140 से 330 रुपये प्रतिमाह रखरखाव भत्ता देने की घोषणा हुई थी. आश्चर्यजनक बात यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक श्रेणी में इस समय 17.5 लाख छात्रवृत्तियां पेश की जा रही हैं, जबकि 6-14 वर्ष के मुस्लिम बच्चों की संख्या लगभग 1.73 करोड़ है, जिनमें से 1.08 करोड़ ग़रीबी रेखा से नीचे हैं. ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली 17.5 लाख छात्रवृत्तियों से कितने मुस्लिम बच्चों का भला होगा, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं. क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह ख़ुद अपने क़ानून के तहत (जिसमें 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की बात कही गई और शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है) ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 1.08 करोड़ मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का बंदोबस्त करे, लेकिन सरकार की नज़र इन आंकड़ों पर नहीं जाती, उसे तो केवल ढिंढोरा पीटना आता है.

हैरानी इस बात है कि यह छात्रवृत्ति योजना लागू हुए तीन साल हो चुके हैं, बावजूद इसके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं. आम मुस्लिम बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि भारत सरकार ने उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है. अगर किसी को इसके बारे में मालूम भी है तो यह नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए. परेशानी यह है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान ख़ुर्शीद समझते हैं कि मुस्लिम बच्चों की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और वह प्रतिदिन अंग्रेज़ी अख़बार पढ़ते हैं. शायद इसीलिए उन्होंने जब इस छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की तो इसका विज्ञापन सबसे पहले प्रमुख अंग्रेज़ी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया. विज्ञापन द्वारा बताया गया कि आप यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ख़ुर्शीद यह भूल गए कि अगर मुसलमान इतना पढ़ा-लिखा होता, अंग्रेज़ी में माहिर होता और कंप्यूटर-इंटरनेट की दुनिया से वाक़िफ़ होता तो भला उसे छात्रवृत्ति की क्या ज़रूरत? सलमान ख़ुर्शीद को मुसलमानों को लुभाने से पहले सोचना चाहिए था कि यह छात्रवृत्ति उन बच्चों तक कैसे पहुंचेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां न कोई अख़बार पहुंचता है और न बिजली की व्यवस्था है. अगर कहीं बिजली है भी तो केवल 2-3 घंटे के लिए. ऐसी जगहों पर भला बच्चे इंटरनेट के बारे में क्या जानेंगे, उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि कंप्यूटर किस बला का नाम है. सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह काम कम करती है, ढिंढोरे ज़्यादा पीटती है. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, अगर उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए तो हम इसके परिणाम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार क़ानून बनाकर अपनी पीठ ख़ुद थपथपा लेती है. केंद्र से राज्यों को पैसा भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन यह पैसा राज्य सरकारों द्वारा इसके हक़दारों तक नहीं पहुंचाया जाता. सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वह छानबीन कर सके कि उसने फ़लां-फ़लां मदों में जिन राज्यों को पैसे दिए थे, क्या वे पात्रों तक पहुंच गए और अगर नहीं पहुंचे तो कारण क्या हैं? कौन लोग हैं, जो इसमें रुकावट बने हुए हैं. ऐसे अफ़सरों-कर्मचारियों की जांच करके उन्हें दंडित करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए.

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सरकार ने प्रवेश शुल्क के रूप में 500 रुपये वार्षिक और ट्यूशन क्लास से दसवीं तक 350 रुपये वार्षिक भुगतान करने की घोषणा की थी. इसके अलावा छठी से दसवीं कक्षा तक के उन बच्चों, जो हॉस्टल में रहते हैं, को हर माह 600 रुपये, जबकि पहली से दसवीं कक्षा तक के डे-स्कॉलर को 100 रुपये महीने रखरखाव भत्ते के रूप में देने की घोषणा की गई थी.

आज सलमान ख़ुर्शीद से लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए जो पैसे केंद्र सरकार की ओर से जारी कराए थे, वे उन तक क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन ख़ुर्शीद अपनी जुबान ही नहीं खोलते और गोलमोल जवाब देकर मौन धारण कर लेते हैं. ख़बर है कि यह छात्रवृत्ति कुछ हद तक, वह भी बहुत कम मात्रा में उन राज्यों के बच्चों तक पहुंचती है, जहां कांग्रेस की सरकार है. सलमान ख़ुर्शीद ख़ुद अपने गृहराज्य उत्तर प्रदेश में इन पैसों को उसके हक़दार छात्रों तक पहुंचाने में असफल रहे हैं. चौथी दुनिया उनसे सवाल करना चाहता है कि वह देश के किसी एक हिस्से का नाम बता दें, जहां सभी हक़दार बच्चों के बीच यह छात्रवृत्ति पूरी ईमानदारी के साथ वितरित की गई हो. मुसलमानों की मजबूरी यह है कि देश के कई नेता उनका हमदर्द होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रहनुमा नहीं है, जो उनकी समस्याओं को सही मायनों में हल करा सके. कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम रहनुमा हैं, वे मुसलमानों के कल्याण पर ध्यान देने के बजाय पार्टी नेतृत्व को ख़ुश करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं. सभी राजनीतिक पार्टियों पर शक करना भी सही नहीं क़रार दिया जा सकता और न हम सभी को संकीर्ण और पक्षपाती कह सकते हैं. यूपीए सरकार ने मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई क़दम उठाए हैं. अब यह मुस्लिम रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वे सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू कराने में अपनी मुस्तैदी दिखाएं.

अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने आवेदन फॉर्म इतना जटिल बना दिया है कि पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए उसे सही तरह भर पाना लगभग असंभव है. विभाग द्वारा प्रकाशित फॉर्म छह पन्नों का है जो पूरी तरह अंग्रेज़ी में है. शर्त यह है कि हर छात्र इस फॉर्म को अपनी हैंड राइटिंग में भरे. ज़रा सोचिए, पहली कक्षा का छात्र इस फॉर्म को कैसे भर सकता है, इसके लिए तो उसे एक क़ाबिल वकील की आवश्यकता होगी. यह छात्रवृत्ति के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के साथ मज़ाक़ नहीं तो और क्या है. होना यह चाहिए था कि अंग्रेज़ी के साथ-साथ ये फॉर्म हिंदी और उर्दू में भी होते और इतने आसान कि किसी भी कक्षा के छात्र को इसे भरने में कोई परेशानी न होती. इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा ख़ुद फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए. दूसरी परेशानी यह है कि उम्मीदवार को इसके साथ आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और माता-पिता की कुल आय का विवरण भी जमा करना है. इन सभी प्रमाणपत्रों को स्कूल के प्रिंसिपल से नहीं, बल्कि किसी गजटेड आफ़िसर से अटेस्ट कराना है. आय प्रमाणपत्र और बच्चे की जाति के बारे में शपथपत्र बनवाते समय अभिभावकों को काफ़ी पैसे खर्च़ करने पड़ते हैं. इस पर भी उन्हें इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं है कि बच्चे का चयन छात्रवृत्ति के लिए हो भी जाएगा या नहीं. मानो कि फॉर्म भरने में आपने जितने पैसे लगाए, चयन न होने पर वे पैसे बेकार गए और अगर आपके बच्चे का चयन हो भी गया तो सरकार की ओर से जो पैसे मिलेंगे, उनमें से स्वयं ख़र्च की गई राशि निकाल लें तो आपके पास शायद उसका आधा भी नहीं बचेगा. कई जगह देखा गया है कि एक हज़ार उम्मीदवारों में से केवल 10 या 20 को ही छात्रवृत्ति मिल सकी है. सरकार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवंटित नहीं कर रही, बल्कि उसने अल्पसंख्यकों से पैसा कमाने का एक बेहतर तरीक़ा निकाला है, क्योंकि शपथपत्र बनवाने में लगने वाली राशि अंत में सरकार के पास ही जाती है.

अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर इन छात्रवृत्तियों के संबंध में दिए गए आंकड़े कहते हैं कि 31 मार्च, 2011 तक मंत्रालय को मिली सूचनाओं के अनुसार 2010-11 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश के मुस्लिम छात्रों के बीच कुल 200 छात्रवृत्तियां वितरित की जानी थीं, लेकिन बीते मार्च माह तक एक भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी. असम में 87000 छात्रवृत्तियों का वितरण होना था, लेकिन अभी तक केवल 37237 छात्रवृत्तियां ही वितरित की जा सकी हैं. गुजरात में 48500 छात्रों में से अभी तक किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी. हिमाचल प्रदेश में 1300 में से केवल 845, झारखंड में 39400 में से 73, नागालैंड में 400 में से 99, त्रिपुरा में 2700 में से 1611, दादर और नगर हवेली में 100 में से 64 छात्रवृत्तियां अब तक वितरित की गई हैं. जबकि मणिपुर, सिक्किम, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में अब तक ऐसा कोई भाग्यशाली मुस्लिम छात्र नहीं है, जिसे यह छात्रवृत्ति मिली हो. यही हाल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का है. अगर सरकार एक साल गुज़र जाने के बाद भी छात्रवृत्तियां वितरित नहीं कर पाती तो इसमें बच्चों का क्या दोष? सरकार यह योजना पूरी तरह लागू करने के लिए गंभीर नहीं है. जब चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो वह मुसलमानों के बीच आंकड़े लेकर अवश्य पहुंच जाएगी और इतने झूठ बोलेगी, इतने वायदे करेगी कि मुसलमान मजबूर होकर एक बार फिर इसे ही वोट देने पर आमादा हो जाएगा. आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के साथ यही खिलवाड़ करती आई हैं. अब वक़्त आ गया है कि मुसलमान अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से जवाब मांगें और अधिकारों के प्रति जागरूक हों.

tabrez@chauthiduniya.com

मरांडी और सोरेन दोनों संथाल आदिवासी हैं. राज्य के आदिवासियों में संथालों की आबादी सर्वाधिक है.

बिहार

युवाओं की सेना सज गई

जिस सूबे में लोकतंत्र जन्मा हो, वहां नए-नए राजनीतिक प्रयोग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. पिछले दिनों बिहार एक बार फिर नए राजनीतिक प्रयोग का गवाह बना. अलग-अलग दलों के युवा नेताओं ने छात्रों व युवाओं के हक़ की लड़ाई के लिए हाथ मिलाकर नई मुहिम का शंखनाद कर दिया है.

सरोज सिंह

राजनीतिक प्रयोग की धरती बिहार में पिछले दिनों एक नया प्रयोग हुआ. भले ही इस प्रयोग को अभी ज़मीनी चुनौतियों से गुज़रना है, पर इस अनूठी पहल ने यह साफ़ कर दिया कि सूबे का युवा नेतृत्व अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है और वह युवाओं को उनका हक़ दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है. युवा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह और युवा जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष उदय सम्राट की पहल पर कई पार्टियों के युवा नेताओं की गोलबंदी ने प्रदेश में राजनीति की एक नई धारा बहा दी है. यह पहली बार हुआ कि युवाओं के सवाल पर एक ग़ैर राजनीतिक मंच अस्तित्व में आ रहा है. इन नेताओं के अलावा इस मंच में शिरकत करने वालों में राजद के प्रदेश महासचिव राजीव सिंह, युवा राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष फ़ैज़ अहमद मेहर, युवा सपा के प्रदेश अध्यक्ष तारकेश्वर पासवान, छात्र लोजपा के प्रदेश प्रभारी उपेंद्र यादव, युवा जदयू के प्रदेश सचिव रंजन ओझा, छात्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, इंडियन डेंटल ऐसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉ. विदिप्त सुवर्ण, डीयू के छात्र नेता अम्मार रज़ा आदि प्रमुख थे. अलग-अलग दलों के ये युवा नेता एक साथ क्यों आए, उनका मक़सद क्या है और क्या ये अपने मक़सद में सफल होंगे. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी है. विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईमानदारी के साथ ये सारे नेता युवाओं के सवाल पूरे बिहार में घूम घूमकर उठाते हैं तो तय है कि सूबे का युवा वोटर इस मंच से ज़रूर जुड़ेगा. इसके अलावा यह मंच बड़ी राजनीतिक पार्टियों के ऐजेंडे में युवाओं के सवालों को शामिल कराने का भी दबाव बना सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि काम संगठित होकर हो तथा विवादरहित हो. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एक साथ बैठकर मंच बना लेना और एक साथ मिलकर किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाना अलग-अलग बातें हैं. दिक्क़त इसलिए भी ज़्यादा है कि सभी नेता अलग-अलग दलों के हैं और अलग-अलग हैसियत के हैं. इसलिए इनमें विवाद की आशंका ज़्यादा है. इसकी झलक बैठक के दूसरे ही दिन मिल गई जब ललन यादव के हवाले से ख़बर आने लगी कि सारे युवा नेता कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन जल्द ही इस ख़बर का खंडन करते हुए ललन को छोड़कर बाक़ी सारे नेता एक बार फिर बैठे और नौजवान एकता मंच के गठन का ऐलान कर दिया. नौजवान एकता मंच के शिल्पकार रोहित सिंह मानते हैं कि सभी विवाद व आशंकाओं का निपटारा करके ही सारे युवा नेता एक साथ आए हैं. ललन को छोड़कर सारे युवा नेता एक साथ हैं. नौजवान एकता मंच के गठन के पीछे युवाओं की उपेक्षा है और इसी मुद्दे पर हमलोग साथ आए हैं. जहां तक इस मंच की सफलता का सवाल है तो मैं यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि दुनिया भर में युवाओं ने जहां चाहा वहां का इतिहास बदल डाला. हमलोग एक नेक इरादे से साथ आए हैं और युवाओं के हक़ की लड़ाई लड़ेंगे. पार्टी और मंच की दोहरी ज़िम्मेदारी पर रोहित कहते हैं कि युवाओं का सवाल पार्टी फोरम से भी उठाएंगे और मंच से भी. चूंकि पार्टी बहुत सारे मुद्दों को लेकर चलती है इसलिए मंच का फोकस केवल युवा मामलों को ही रखा गया है. नए मंच से हमलोग युवाओं के मसलों पर पूरा फोकस करेंगे, ताकि युवाओं को सड़कों पर नौकरी व अन्य मामलों में भटकना न पड़े. बिहार में लंबे अरसे से यूथ कमीशन की मांग की जा रही है, पर नीतीश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. हम युवा साथी यह चाहते हैं कि सरकार युवाओं की उपेक्षा न कर पाए.

बताया जा रहा है कि ये सारे युवा नेता शहीद चंद्रशेखर की धरती सीवान से युवा जनजागरण यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं. यह यात्रा पूरे बिहार की होगी और युवाओं पर केंद्रित होगी. युवाओं को यह बताया जाएगा कि यह मंच पूरी तरह ग़ैर राजनीतिक है और आपकी समस्या ही इसका केंद्र बिंदु है.

उदय सम्राट की मानें तो हमारी गोलबंदी युवाओं के हक़ के लिए है. 27 सालों से बिहार में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ. क्या यह मज़बूत लोकतंत्र की निशानी है. सभी दलों में युवाओं के मामले हाशिये पर हैं. यही वजह है कि हमलोग एक मंच पर आए हैं. युवा राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष फ़ैज़ अहमद मेहर ने कहा कि यह मंच अपनी पूरी ताक़त के साथ नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुका है और जातीय भावना से ऊपर उठकर युवाओं की लड़ाई लड़ेगा.

बताया जा रहा है कि ये सारे युवा नेता शहीद चंद्रशेखर की धरती सीवान से युवा जनजागरण यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं. यह यात्रा पूरे बिहार की होगी और युवाओं पर केंद्रित होगी. युवाओं को यह बताया जाएगा कि यह मंच पूरी तरह ग़ैर राजनीतिक है और आपकी समस्या ही इसका केंद्र बिंदु है. सूत्र बताते हैं कि यह मंच चाहता है कि बिहार के सभी ज़िलों में युवाओं का एक मज़बूत संगठन तैयार किया जाए. संख्या के लिहाज़ से भी इसे काफ़ी वज़नदार बनाया जाए. फ़िलहाल ये युवा नेता अपने-अपने ज़िलों में यात्रा निकालकर अपनी ताक़त बढ़ाने का प्रयास करेंगे. दशहरा के बाद पटना में प्रदेश स्तर का सम्मेलन कर यह सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताक़त का अहसास कराएगा. माना जा रहा है कि सूबे में नए वोटरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है. इन युवा वोटरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यह मंच अपनी पूरी ताक़त लगाएगा. मंच यह भी कोशिश करेगा कि अपने-अपने दलों में युवा नेतृत्व का प्रभाव बढ़ाया जाए, ताकि नीति निर्धारण में उनकी पूछ बढ़ सके. बिहार ऐसे भी छात्र आंदोलन की जननी रहा है. जेपी ने छात्रों और युवाओं की ताक़त पर ही इतना बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन ये नेता जेपी नहीं हैं, पहले तो उन्हें युवाओं के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी. उन्हें छात्रों व युवाओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे उनके नाम पर केवल राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि उनकी समस्याओं के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे. इस मंच के नेताओं को यह भी साफ़ करना होगा कि वे छात्रों व युवाओं को बीच मझधार में छोड़कर भागेंगे नहीं. अगर गोलबंद हुए नेता ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर बिहार की धरती पर शुरू हुआ यह अनूठा प्रयोग अपनी मंज़िल पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

भाजपा को गहरा झटका

जमशेदपुर संसदीय उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं. मुख्यमंत्री बनने की वजह से अर्जुन मुंडा ने यह सीट ख़ाली की थी. चुनाव के नतीजे बाबूलाल मरांडी के हक़ में हैं और भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है. इस सीट की जीत की अहमियत को समझते हुए ही भाजपा के आला नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी को चुनाव में उतारा था. गोस्वामी के लिए सरकार और संगठन ने ताक़त लगाई, लेकिन मुश्किल से दूसरे नंबर पर आ पाए. बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा ने एक लाख 43 हज़ार मतों के अंतर से बाज़ी मार ली. झारखंड विकास मोर्चा के डॉ. अजय कुमार ने दो लाख 55 हज़ार मत पाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अब लोक सभा में झारखंड विकास मोर्चा के सदस्यों की संख्या दो हो गई है. भाजपा इस पराजय की पड़ताल की बात कह रही है. वास्तव में 17 मार्च, 2003 को भाजपा द्वारा लिए गए एक फ़ैसले के कारण बाबूलाल मरांडी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं. उस समय दिल्ली में भाजपा नेताओं ने झारखंड में जैसे तैसे सरकार को चला लेने की साज़िश को अंजाम दिया. भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने पांच निर्दलीयों की मदद से सरकार चलाने की बाध्यता को ख़त्म करने पर आमादा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की छुट्टी कर दी. साथ ही पार्टी विद डिफरेंस की नीति को तिलांजली देकर पार्टी इन पावर की नीति अपनाई गई. वेंकैया नायडू तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. राजनाथ सिंह दिल्ली से बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदख़ल करने का आदेश लेकर रांची आए थे. आडवाणी के चहेते मरांडी आदेश पढ़कर भौचक्के रह गए थे, क्योंकि पिछली ही रात मरांडी की बात आडवाणी से हुई थी. आडवाणी के साथ मरांडी की एक तरह से सहमति बन गई थी कि निर्दलीयों के ब्लैकमेलिंग में फंसने की बजाय विधान सभा भंग करने का रास्ता चुना जाए. आडवाणी को मरांडी ने भरोसा दिलाया था कि विधान सभा भंग करने से राज्य में भाजपा को नैतिक बल मिलेगा. नैतिकता के आधार पर लड़े जाने वाली चुनाव में पार्टी को पर्याप्त बहुमत मिल जाएगा, लेकिन जो हुआ वह सामने है.

घोषित तौर पर भ्रष्ट मंत्रियों की ज़िद के आगे झुकने के बजाय सरकार को छोड़ जनता के बीच जाकर चुनाव पर दृढ़ मरांडी ने दलील दी कि निर्दलीयों से छुटकारा नहीं लिया गया तो झारखंड की राजनीति के लिए आने वाला वक़्त बुरा होगा. इशारा महज़ 81 सदस्यों की विधान सभा में किसी एक दल को बहुमत पाने में आने वाली दिक्क़तों की तरफ़ था. शुरू में ही इलाज नहीं होने से यह समस्या दस सालों से जस की तस बनी हुई है. नवंबर 2000 में सरकार बनने के बाद से कहने को भाजपा विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन विडंबना यह है कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए उसे हर बार राजनीतिक जोड़तोड़ का सहारा लेना पड़ा. उस समय केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी. संगठन में आडवाणी की तूती बोलती थी. केंद्र में सत्तारुढ़ पार्टी की सरकार राज्य में भी बनी रहे इसके लिए राजनाथ सिंह संवादिया बनकर रांची आए. राजनाथ सिंह ने मरांडी को आदेश दिया कि वह अधीनस्थ मंत्री अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता तैयार करें और उनकी ताजपोशी कर दें. आहत मरांडी ने अनुशासन के नाम पर मन मसोसकर इसे मान लिया. मुंडा को मरांडी ही झामुमो से भाजपा में लाए थे. अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया. निर्दलीय भी मान गए. मुख्यमंत्री बनने से पहले तक मुंडा ने न तो दिल्ली के केशव कुंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर देखा था और न ही संघ के केंद्रीय नेताओं से उनका कोई वास्ता पड़ा था. फिर भी मुंडा के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही सारा खेल समझ में आ गया. नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने एहसान का निपटारा करने के लिए संदेश लेकर रांची आए राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री के विशेष विमान से वाराणसी तक पहुंचवाया.

अब बाक़ी दलों की हालत को भी समझते हैं. कांग्रेस बरसों तक अलग झारखंड की मांग को दबाती रही. इसका ख़ामियाज़ा उसे झारखंड बनने के दस साल बाद भी भुगतना पड़ रहा है. ठोस सांगठनिक आधार तैयार नहीं है. भाजपा से लोहा लेने के लिए कांग्रेस राज्य में मरांडी का पिछलग्गू बनकर चलने में ही ख़ुद का भला समझती है. दरसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के उदय के बाद से ही कांग्रेस राज्य की राजनीति में इतिहास के काल के गाल में समा गई थी. जमशेदपुर उपचुनाव में ज़मानत ज़ब्त कराने वाली कांग्रेस ने मरांडी का सहारा लेकर उबरने की कोशिश की थी और अलग उम्मीदवार उतारा था. यह कोशिश कांग्रेस पर भारी पड़ी है. आने वाला वक़्त बताएगा कि कोशिश से कांग्रेस क्या सबक़ लेती है. अलग राज्य बनाने की राजनीति में शामिल होकर भाजपा ने कोई तीस साल पहले झारखंड में कांग्रेस के स्पेस को हड़पा था. तब से असली लड़ाई झामुमो और भाजपा के बीच रही. भाजपा से मरांडी की विदाई के साथ ही झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का भाजपा से बैर ख़त्म सा हो गया. मरांडी से असली चुनौती आदिवासियों के मानस पटल पर बसे झामुमो को है.

मरांडी और सोरेन दोनों संथाल आदिवासी हैं. राज्य के आदिवासियों में संथालों की आबादी सर्वाधिक है. मरांडी के कांग्रेस के क़रीब जाते ही बुज़ुर्ग हो चले सोरेन छिटककर भाजपा की तरफ़ चले गए और आज की तारीख़ में बेटे हेमंत सोरेन को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाकर विरासत के हस्तांतरण का नज़ारा भांप रहे हैं. हाल के वर्षों में आदिवासियों के बीच चर्च और संघ के लिए जारी संघर्ष को किनारे करके उग्र वामपंथ ने नक्सलवाद के नाम पर जगह ज़रूर बना ली है, पर झारखंड में वामपंथी राजनीतिक दलों के लिए शुरू से ही कोई जगह नहीं रही है. इसकी बड़ी वजह अलग राज्य की लड़ाई में वामपंथी राजनीतिक दलों की भूमिका का गौण रहना है. पड़ोस के पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हुई ममता बनर्जी का अगर राज्य के बंगाली मतदाताओं पर कोई असर होता तो वह जमशेदपुर उपचुनाव में ज़रूर दिखता. ममता ने झामुमो से नाराज़ पूर्व सांसद सुमन महतो को तृणमूल कांग्रेस का टिकट देकर राजनीति का पासा चला था, लेकिन मिष्टी दोई के जमशेदपुर में क़ायम बेहतरीन बाज़ार से सुमन महतो की ज़ब्त हुई ज़मानत ने बता दिया है कि फ़िलहाल झारखंड में बंगाल के नेताओं की गोटी नहीं चलने वाली है. साफ़ है कि जमशेदपुर में मरांडी की झाविमो की जीत के निहितार्थ व्यापक हैं. इससे आने वाली राजनीति का प्रभावित होना तय है. टूटे मनोबल को जोड़ने के लिए भाजपा का आरोप है कि जमशेदपुर की जीत नक्सलियों से मरांडी के नापाक गठजोड़ का नतीजा है. नक्सलवाद के राज्यव्यापी असर को देखकर कहा जा सकता है कि मरांडी को इस आरोप का लाभ आगे भी मिलता रहे. जमशेदपुर संसदीय सीट पर नक्सलियों की सक्रियता का काला इतिहास रहा है. 2007 में नक्सलियों ने जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो की हत्या कर दी थी. उपचुनाव का प्रचार शुरू करते वक़्त ही मरांडी ने पुत्र अनूप मरांडी सहित 16 ग्रामीणों की नृशंस हत्या करने वाले नक्सलियों की फांसी की सज़ा माफ़ करने की मार्मिक अपील की थी. बाद में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी की नक्सल नेता के साथ सहयोग पर बातचीत की हंगामेदार सीडी को भुनाने की कोशिश हुई.

जमशेदपुर में साझा उम्मीदवार खड़ा करने की बजाय सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अलग-अलग उम्मीदवार खड़ा करके ज़मीन पर अपनी ताक़त आंक ली है. मरांडी के राजनीतिक चातुर्य के आगे बाक़ी दल बौने नज़र आ रहे हैं. बाबू लाल मरांडी ने असली दांव अर्जुन मुंडा को विधायक बनाने के तीन महीने पहले हुए खरसवां विधानसभा उपचुनाव के दौरान ही लगाया था. उसका मारक नतीजा जमशेदपुर संसदीय उपचुनाव में दिखा है. मुख्यमंत्री मुंडा खरसवां के रहने वाले हैं. मुख्यमंत्री के घर में घुसकर मरांडी ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट कर दिखाया था. जमशेदपुर में जीत के लिए मरांडी ने दोहरी नीति अपनाई. शहरी मतदाताओं के बीच लोकप्रिय पूर्व आईपीएस अफ़सर अजय कुमार ने जहां शहरी मतदाताओं के दरवाज़ों पर दस्तक देकर झाविमो के लिए समर्थन जुटाया तो मरांडी गांव-गांव घूमकर खरसवां की अपील को दोहराते रहे. मुख्यमंत्री के गांव खरसवां जाकर मतदाताओं से कहते रहे कि विधान सभा चुनाव में नहीं सुने कोई बात नहीं, संसदीय चुनाव में सुन लो. जमशेदपुर का नतीजा बताता है कि भाजपा के ख़िलाफ़ मरांडी की बाज़ीगरी ने शहर और गांव दोनों में पलीता लगाया है.

आलोक कुमार
feedback@chauthiduniya.com

वर्तमान में अगर बीड़ी उद्योग के स्वरूप की बात की जाए तो भारत में क़रीब 300 बड़े कारख़ाने बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं और कई हज़ार अन्य छोटे कारख़ाने हैं.

बीड़ी मज़दूर

जीवन में ख़ुशहाली कब आएगी

वर्तमान में अगर बीड़ी उद्योग के स्वरूप की बात की जाए तो भारत में क़रीब 300 बड़े कारख़ाने बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं और कई हज़ार अन्य छोटे कारख़ाने हैं. यह उद्योग क़रीब 44 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोज़गार देता है और क़रीब 40 लाख लोग बीड़ी से संबंधित अन्य कामों में लगे हुए हैं.

राजेश एस कुमार

किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है. अगर वह किसी विकासशील देश की बात हो तो वहां के लघु उद्योग ही उसके आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं. भारत भी एक विकासशील देश है. ज़ाहिर है, भारत के विकास की कहानी के पीछे भी इन्हीं उद्योगों का योगदान है, लेकिन अब भारत धीरे-धीरे विकासशील देशों की कतार में काफ़ी आगे आ चुका है. यहां बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा लगा रही हैं. अरबपतियों की लिस्ट में भारत ठीकठाक पायदान पर अपनी जगह बना रहा है. हम कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक क्रांति अपनी सफलता के चर्मोत्कर्ष पर है, लेकिन इस सबके बीच शायद हम उन उद्योगों और उनमें काम करने वाले लोगों को भूल गए हैं, जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में न सिर्फ़ महती भूमिका निभाई, बल्कि आज भी जब भारत पर आर्थिक संकट मंडराता है तो इन्हीं उद्योगों की बदौलत देश का आर्थिक तंत्र टिक पाता है.

यही हाल अस्तित्व के संकट से जूझ रहे बीड़ी उद्योग का है. एक दौर था, जब भारतीय बाज़ार में सिगरेट कंपनियां इस क़दर नहीं छाई हुई थीं, उस वक़्त भारत का बीड़ी कारोबार ज़ोरों पर था. उस वक़्त सिगरेट बहुत ख़ास तबक़ा ही पिया करता था. उस दौरान बीड़ी के कारोबार से जुड़े व्यवसायी और उत्पादन प्रक्रिया में शमिल मज़दूर अपने-अपने रोज़गार से ख़ुश थे. समय बदला, सिगरेट की खपत बढ़ गई और बीड़ी कारोबारियों का मुनाफ़ा कम होने लगा. लेकिन जैसा कहते हैं कि व्यापारी तो अपना नफ़ा कहीं न कहीं से निकाल ही लेता है, सो बीड़ी व्यापारी भी उन राज्यों की तरफ़ अपना व्यापार बढ़ाने लगे, जहां बीड़ी की खपत ज़्यादा होती है. इन इलाक़ों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नाम लिया जा सकता है. इस क़दम से बीड़ी का उत्पादन बढ़ गया और व्यापारी भी मुनाफ़े में आ गए, लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी मार जिन पर पड़ी, वे थे बीड़ी मज़दूर. वे कहीं के नहीं रहे. वे दैनिक मज़दूर की तरह दिहाड़ी पर ही सिमट कर रह गए. वर्तमान में अगर बीड़ी उद्योग के स्वरूप की बात की जाए तो भारत में क़रीब 300 बड़े कारख़ाने बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं और कई हज़ार अन्य छोटे कारख़ाने हैं. यह उद्योग क़रीब 44 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोज़गार देता है और क़रीब 40 लाख लोग बीड़ी से संबंधित अन्य कामों में लगे हुए हैं. अब अगर आप सोच रहे हों कि इस धंधे से जुड़े मज़दूरों का मेहनताना क्या है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकारों द्वारा बीड़ी लपेटने के काम में लगे लोगों के लिए जो मज़दूरी निर्धारित की गई है, वह प्रति 1000 बीड़ी लपेटने पर उत्तर प्रदेश में 29 रुपये और गुजरात में 66.8 रुपये है. अब आप सोच सकते हैं कि इतनी दिहाड़ी में कोई अपने के लिए रोटी का इंतज़ाम कैसे करता होगा, परिवार का पेट पालने की बात तो बहुत दूर है. ऐसा नहीं है कि इस व्यापार में मुनाफ़ा नहीं है. असल में मुनाफ़ा तो बहुत है, लेकिन मज़दूरों का शोषण जानबूझ कर किया जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत के बीड़ी उद्योग ने वर्ष 1999 में क़रीब 16.5 अरब उत्पाद कर और 20 अरब विदेशी विनिमय राजस्व भारत सरकार के लिए एकत्रित किया. इन आंकड़ों से इतना तो समझा जा सकता है कि सरकार और इससे जुड़े व्यवसायी इन मज़दूरों के विकास के प्रति कितने उदासीन हैं. इनकी तुलना अगर सिगरेट कंपनियों के मज़दूरों से की जाए तो देखेंगे कि उनके लिए न सिर्फ़ अच्छे मेहनताने का इंतज़ाम है, बल्कि कारख़ाने में उनको स्वास्थ्य संबंधी कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं. लेकिन बीड़ी मज़दूरों के लिए न तो कोई कारख़ाना होता है और न उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम. इसलिए वे बेचारे अपने घरों में ही बैठकर बीड़ी बनाते हैं और न्यूनतम दिहाड़ी में मालिकों को सप्लाई करते हैं. असली मुनाफ़ा मालिक खाता है.

यह तो रही मेहनताने की बात और ज़रा बीड़ी मज़दूरों के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों और स्वास्थ्य के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं पर नज़र डालते हैं. इस बात से तो सभी वाक़िफ़ हैं कि बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. यह हानि सिर्फ़ पीने वालों को ही नहीं, बल्कि उन्हें भी होती है, जो इसके निर्माण कार्य से जुड़े होते हैं. इन मज़दूरों को टीबी, अस्थमा, फेफड़े के रोग और चर्म रोग होने का ख़तरा बना रहता है. जो महिलाएं अपने शिशुओं को काम पर ले जाती हैं, उन शिशुओं को नन्हीं सी उम्र में ही तंबाकू की धूल और धुंआ झेलना पड़ता है. जो बाल मज़दूर इस काम में लगे हैं, उन्हें श्वास और चर्म रोग होना आम बात है. बीड़ी लपेटने के दौरान मज़दूर किसी भी तरह के दस्ताने और मास्क आदि का प्रयोग नहीं करते, जिससे उनके शरीर में तंबाकू आदि के कण प्रवेश कर जाते हैं. शोध बताते हैं कि जो लोग बीड़ी के पत्ते की कटाई के काम में लगे हुए हैं, उनके पेशाब में निकोटिन की मात्रा पाई गई है. 45 साल की उम्र आते-आते बीड़ी मज़दूरों के हाथों की उंगलियों की ऊपरी सतह की खालें मर जाती हैं और वे काम करना बंद कर देती हैं. इस परिस्थिति में वे लोग जो बीड़ी बनाने का काम नहीं कर पाते, भीख मांगना शुरू कर देते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि इन मज़दूरों के स्वास्थ्य से संबंधित उक्त सारी जानकारियां सरकारी सर्वे में ही सामने आती हैं और इसके बावजूद सरकार सिर्फ़ कारख़ाना मालिकों के हितों का ही ध्यान रखती है.

कहने के लिए सरकार बीड़ी मज़दूर कल्याणकारी फंड के तहत उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, बीमा योजना, घर का किराया आदि प्रदान करने की बात करती है. इसके अलावा काम के दौरान बीड़ी मज़दूर को यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन ये सारी सुविधाएं कितने मज़दूरों को मिलती हैं, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है. पिछले दिनों सरकार ने चिकित्सा स्मार्ट कार्ड के ज़रिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ बीड़ी मज़दूरों को भी देने की मंज़ूरी दे दी है. इस योजना के तहत बीड़ी मज़दूरों के परिवारों को तीस हज़ार रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी. इससे अधिक की राशि कल्याण आयुक्त द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार पैनल में रखे गए अस्पतालों को सीधे दी जाएगी. अब इस योजना का लाभ पाकर कितने बीड़ी मज़दूरों का जीवन संवरता है, देखने वाली बात होगी. इस तरह ये मज़दूर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इस क़दर पिछड़ जाते हैं कि फिर इनका पूरा परिवार सज़ा के तौर पर इसी व्यसाय का ग़ुलाम बनकर रह जाता है. दरअसल इस तरह धंधे में ज़्यादातर वही लोग काम करते हैं, जो समाज के उस तबक़े से संबंधित हैं, जहां न तो शिक्षा है और न रोज़गार के अवसर. नतीजतन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बीड़ी के धुएं में उड़ जाते हैं.

ऐसा नहीं है कि लोग इस व्यवसाय से छुटकारा नहीं पा सकते. ये लोग चाहें तो जबलपुर के अंसार नगर के बीड़ी मज़दूरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं. कुछ साल पहले इस इलाक़े के कुछ युवाओं ने ठान लिया कि वे बीड़ी नहीं बनाएंगे. उन्होंने एम्ब्रोडरी और सिलाई की ट्रेनिंग ली और घर पर ही काम शुरू किया. आज 30 लाख की आबादी वाले इस इलाक़े में आधे से अधिक घरों में यह काम हो रहा है. इन लोगों को चाहिए कि ये संगठित होकर सरकार से अपने हक़ की मांग करें और सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करें या फिर अंसार नगर के मज़दूरों की तरह बीड़ी के इस जाल से आज़ाद होकर एक नई शुरुआत करें.

rajeshy@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... गांधीवादी नेता

सरकार को वास्तविकता की जानकारी नहीं

झारखंड में असंगठित मज़दूरों की संख्या लाखों में है. इसमें बीड़ी मज़दूरों का एक बड़ा तबक़ा शामिल है. इनका दुर्भाग्य यह है कि इनकी वास्तविक संख्या राज्य सरकार के पास नहीं है. राज्य सरकार बीड़ी उद्योग से जुड़े मज़दूरों की हालत से नावाक़िफ़ है. इन परिस्थितियों में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी मज़दूरों के लिए बनाई गईं योजनाएं कितनी उपयोगी होंगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में पाकुड़ ज़िले में मात्र 2589 मज़दूर हैं, पर वास्तविकता यह है कि इस ज़िले में बीड़ी मज़दूरों की संख्या 25 हज़ार से भी अधिक है. हैरत की बात तो यह है कि पाकुड़ स्थित भारत सरकार के श्रमिक औषधालय में भी मज़दूरों की सही संख्या दर्ज नहीं है. इस औषधालय में निबंधित मज़दूरों की संख्या 4457 है. इसका मतलब यह है कि पाकुड़ ज़िले के मज़दूरों की वास्तविक संख्या न तो राज्य सरकार के पास है और न पाकुड़ स्थित श्रम औषधालय में. कमोबेश यही स्थिति चतरा ज़िले की है. राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, देवघर में बीड़ी मज़दूरों की संख्या 4897, साहबगंज में 251, दुमका में 892, गोड्डा में 867, हज़ारीबाग में 600, पूर्वी सिंहभूम में 6500 और पलामू में 384 है. इनमें से कोई भी आंकड़ा वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है. वास्तविकता यह है कि अकेले साहबगंज, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में ही लाखों की संख्या में बीड़ी मज़दूर काम करते हैं. इन आंकड़ों से बीड़ी मज़दूरों की उपेक्षा का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है. सरकार के अलावा बीड़ी बनाने वाली कंपनियों के पास भी बीड़ी मज़दूरों की वास्तविक संख्या नहीं है. सच पूछा जाए तो बीड़ी कंपनियां जानबूझ कर मज़दूरों की वास्तविक संख्या ज़ाहिर नहीं करना चाहती हैं. वे नहीं चाहतीं कि मज़दूरों का संगठन मज़बूत हो और वह उनके लिए परेशानी का सबब बने. दरअसल, झारखंड में बीड़ी उद्योग चलाने वाली लगभग सभी कंपनियां बाहर की हैं. ये कंपनियां बिचौलियों और दलालों के माध्यम से झारखंड में बीड़ी का कारोबार चलाती हैं. इसके कारण कंपनियों का मज़दूरों से सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं होता. कंपनियां यह चाहती भी नहीं हैं. यही वजह है कि मज़दूरों को मिलने वाला लाभ इस धंधे में लगे बिचौलिए और दलाल गटक लेते हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड राज्य गठन के 11 साल बाद भी बीड़ी मज़दूरों की समस्या किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं बनी. बीड़ी मज़दूरों की तमाम समस्याओं की जड़ उनका असंगठित होना है.

आलोका
feedback@chauthiduniya.com

सूखे और क़र्ज़ में डूबे बुंदेलखंड के किसानों की तबाही भले ही दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें अपने पुराने ढर्रे पर हैं.

बुंदेलखंड

पैकेज के बावजूद बदहाली बरक़रार

सुरेंद्र अग्निहोत्री

देश के बीमारू राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश के सात ज़िलों में फैला बुंदेलखंड आज भी जल, ज़मीन और जीने के लिए तड़पते लोगों का केंद्र बना हुआ है. रोज़ी-रोटी और पानी की विकट समस्या से त्रस्त लोग पलायन के लिए मजबूर हैं. प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का आठवां हिस्सा ख़ुद में समेटे यह समूचा अंचल भूमि के उपयोग-वितरण, सिंचाई, उत्पादन, सूखा, बाढ़ और आजीविका जैसे तमाम मामलों में बहुत पीछे है. झांसी और चित्रकूट मंडलों में विभाजित बुंदेलखंड में प्रदेश की कुल आबादी की लगभग पांच प्रतिशत जनसंख्या है. औसत से कम बरसात के कारण प्रत्येक दो-तीन वर्ष बाद बुंदेलखंड सूखे की चपेट में आ जाता है. कभी ख़रीफ़ तो कभी रबी और कभी दोनों फ़सलें चौपट हो जाती हैं. लगभग सोलह प्रतिशत ज़मीन बंजर अथवा ग़ैर कृषि कार्यों से संबद्ध है. बेसिक एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या नगण्य है और जो हैं, उनकी हालत बदतर है. विकास के तमाम कार्यों के बावजूद ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या लगभग चालीस प्रतिशत है. चित्रकूट मंडल में हालात और भी बदतर हैं. यहां लोग चार दशकों से पट्टे की ज़मीन पर क़ब्ज़े के लिए भटकते नज़र आते हैं. महिलाओं और ग़रीबों की हालत ग़ुलामों जैसी है. अनेक तरह की खनिज संपदाओं पर दबंगों का अवैध क़ब्ज़ा है. एक ही ज़मीन को वन विभाग और राजस्व विभाग अपनी बताते हुए आदिवासियों को खदेड़ देते हैं.

ललितपुर का दर्द बहुत गहरा है. बांधों और उद्योगों के नाम पर ज़मीन की लूट, वनों एवं पहाड़ों का विनाश, नदी तटों की कटान, स्टोन क्रेसर, ग्रेनाइट आदि कार्यों का अनियमित विस्तार, वनीकरण के नाम पर यूकेलिप्टस एवं विलायती बबूल का रोपण, जड़ी-बूटियों और अन्य वन उपजों के क्षरण, प्राकृतिक असंतुलन और निष्प्रभावी प्रशासन तंत्र जैसी तमाम समस्याओं से घिरी यह धरती वेदना के अथाह सागर में डूबी है. चित्रकूट मंडल के पाठा क्षेत्र में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है. जबकि इसके भूगर्भ में 12 किलोमीटर चौड़ी और 110 किलोमीटर लंबी नदी बहती है, जहां से तीस से चालीस हज़ार गैलन प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकाला जा सकता है. यह सब एक भगीरथ प्रयास से ही संभव है. यदि कोई भगीरथ ऐसा ठान ले तो हर साल बुंदेलखंड में साठ से सत्तर करोड़ रुपये का बजट केवल पानी के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी. सूखे से बेहाल बुंदेलखंड में किसानों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री मायावती ने यहां की हालत को देखते हुए बुंदेलखंड पैकेज के कार्य मानसून के पहले पूरा कराने का निर्णय करके मानवीय संवेदना का परिचय भले ही दिया हो, लेकिन व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन के बिना ऐसा संभव नहीं लगता. जल संकट के चलते हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं. गंगा, यमुना, गोमती और बेतवा की भूमि उत्तर प्रदेश भीषण जल संकट के मुहाने पर खड़ा है. गंगा और यमुना प्रदूषण के चलते गंदे नाले में तब्दील होने को विवश हैं. बुंदेलखंड समाज सेवा संस्थान के वासुदेव कहते हैं कि असीमित संसाधनों पर सीमित लोगों ने अवैध और अनैतिक अधिकार जमा रखा है. समाजसेवी गोपाल भाई कहते हैं कि लोकमत मारा-मारा भटक रहा है. यदि जिलाधिकारी ने कह दिया, लिख दिया कि भूख से कोई नहीं मर रहा, कहीं कोई अकाल या सूखा नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री के लिए यही अंतिम सत्य बन जाता है.

पानी की कमी के चलते कृषि कार्यों और पशुपालन में काफ़ी दिक्क़तें आ रही हैं. खेत सूखे पड़े हैं, ग़रीबों का गांवों से पलायन जारी है, तालाबों में पानी नहीं है, किसानों की ज़मीनें बिक रही हैं, नीलाम हो रही हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की हवाई घोषणाओं के बीच बुंदेलखंड में पिछले पांच महीनों के दौरान 519 किसान काल का ग्रास बन चुके हैं. किसानों की मौत पर केंद्र और राज्य से जवाब तलब कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जता दिया है कि बुंदेलखंड में सब कुछ ठीक नहीं है. न्यायालय ने किसानों से कृषि ऋण वसूली के मामले में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे उसे बुंदेलखंड में लागू कल्याण योजनाओं, पीडीएस एवं सिंचाई सुविधाओं के बाबत उठाए गए क़दमों की जानकारी से अवगत कराएं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफ़ी के संबंध में उठाए गए क़दमों की जानकारी भी मांगी गई है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रत्येक किसान की मौत के बारे में अस्पतालों, ब्लॉकों एवं पुलिस थानों से ब्योरा एकत्रित कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने मुख्य सचिव से कहा कि वह सभी बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋण के ब्योरे के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करें. न्यायालय ने राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सहकारी बैंकों, खादी ग्रामोद्योग एवं विकास बोर्ड से कहा है कि वे ऋण वसूली के दौरान किसानों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करें.

हाईकोर्ट ने यह आदेश अख़बारों में छपी ख़बरों के आधार पर दिया है, जिनके अनुसार बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट एवं जालौन ज़िलों में वर्ष 2009 में 568, वर्ष 2010 में 583 और वर्ष 2011 के पांच महीनों में 519 किसानों ने सूखे और ग़रीबी से आज़िज़ आकर आत्महत्या कर ली. किसानों पर इस समय 4370.32 करोड़ रुपये का ऋण बक़ाया है. केंद्र सरकार ने सात सौ करोड़ रुपये की सहायता दी है. ऋण अदायगी न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं. सिर्फ़ किसान ही नहीं, अपितु बेरोज़गार युवा भी आत्महत्या को मुक्ति का मार्ग समझ बैठे हैं. प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत ऋण लेकर शुरू किए गए उद्योग पूरी तरह चौपट हो गए हैं. बसपा सरकार के वरिष्ठतम मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी, दद्दू प्रसाद, बादशाह सिंह, रतन लाल अहिरवार, हरिओम एवं बाबू सिंह कुशवाहा जैसे क़द्दावर लोगों की मौजूदगी के बावजूद बुंदेलखंड में भुखमरी के हालात कई सवाल खड़े करते हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने सूखा प्रभावित बुंदेलखंड का दौरा करने के बाद किसानों और लघु उद्योग संचालित करने वाले युवाओं के सभी क़र्ज़ तत्काल माफ़ किए जाने की वकालत की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं कि बुंदेलखंड की भलाई के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मौजूदा बसपा और पूर्ववर्ती सपा सरकार तो वहां भूख एवं क़र्ज़ से मौत होने की बात स्वीकार ही नहीं करती. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर प्रसाद निषाद का कहना है कि जन समस्याओं के समाधान की ओर बसपा सरकार और उसके मंत्रियों का ध्यान कम है. मंत्री अपना भविष्य बनाने में जुटे हुए हैं. जिस बसपाई के पास कभी टूटी साइकिल नहीं होती थी, वह आज अरबों रुपये का मालिक कैसे बन गया. गरौठा से सपा विधायक दीप नारायन सिंह यादव कहते हैं कि किसानों की क़र्ज़ा माफ़ी, पानी का बंदोबस्त और रोज़गार के साधन मुहैया कराने के साथ-साथ युवाओं के लघु उद्योगों में विशेष छूट दी जाए.

सूखे और क़र्ज़ में डूबे बुंदेलखंड के किसानों की तबाही भले ही दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें अपने पुराने ढर्रे पर हैं. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी सक्रिय हुए तो बुंदेलखंड को केंद्र ने पैकेज तो दे दिया, लेकिन अब इस धन के ख़र्च पर ही सवाल उठने लगे हैं. बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के राजा बुंदेला कहते हैं कि कमीशनबाज़ी के चक्कर में बजट वापस हो जाता है. ऐसे में बुंदेलखंड को बचाने के लिए एकमात्र उपाय बुंदेलखंड राज्य का गठन है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य कहते हैं कि जब हम यहां हो रहे घोटालों की शिकायत करते हैं तो उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव का मानना है कि बुंदेलखंड में पैकेज के तहत चलने वाले पुनर्वास अभियान को संचालित करने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों को शामिल करके कार्यक्रम क्रियान्वयन देखरेख समिति का गठन हो, जिसे भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार हो. दिल्ली में अभी हाल में हुई एक बैठक में केंद्रीय योजना राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने भी कहा कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के मद में बुंदेलखंड को दिए गए 800 करोड़ रुपये में से उत्तर प्रदेश सरकार बीते 31 मार्च तक महज़ 73 करोड़ रुपये (लगभग नौ प्रतिशत) का ही उपयोग प्रमाणपत्र दे पाई है. बैठक में शामिल बांदा के सपा सांसद आर के पटेल ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज को अधिकारियों ने खाने-कमाने का धंधा बना लिया है. सूखे से बचाव के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी. पुराने बांधों की मरम्मत में करोड़ों रुपये डकार लिए गए. लिहाज़ा जो भी धन ख़र्च हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. सपा सांसद घनश्याम अनुरागी ने भी पैकेज के धन में बंदरबांट होने की बात कही. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं झांसी के सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज के धन को ख़र्च करने के मामले में प्रदेश सरकार लापरवाही बरत रही है. दरअसल प्रदेश सरकार का बुंदेलखंड पर कोई फोकस नहीं है. उसे डर है कि कहीं वहां के विकास का श्रेय कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को न मिल जाए. जैन ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के क़र्ज़ के एकमुश्त समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए. हमीरपुर के बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं में भी धन मिलना था. कई मंत्रालयों ने अतिरिक्त धन देने में असमर्थता जता दी है. लिहाज़ा 3508 करोड़ रुपये का पैकेज 1598 करोड़ रुपये पर सिमट गया है. मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बुंदेलखंड के किसानों को ऋण माफ़ी देने के लिए विशेष योजना लागू किए जाने की मांग की है. मायावती ने कहा कि विशेष योजना में किसानों को इस वर्ष 31 मार्च तक दिए गए ऋण भी शामिल किए जाएं.

अकेले बांदा जनपद में पिछले आठ सालों के दौरान बदहाली और भुखमरी से तक़रीबन ढाई हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं. वर्ष 2002 में 310, 2003 में 240, 2004 में 280, 2005 में 285, 2006 में 278, 2007 में 215, 2008 में 314, 2009 में 278 और 2010 में 143 लोगों ने क़र्ज़, ग़रीबी, बदहाली और उनसे उपजे विभिन्न कारणों से मौत का वरण किया. बुंदेलखंड के जालौन जनपद में 2007 तक के बक़ाएदारों के लिए क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा करके केंद्र सरकार मानो अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो गई है. दूसरी ओर बुंदेलखंड में सूखे का प्रकोप अभी तक नहीं टला है, जिससे इस अंचल के किसानों का क़र्ज़ के दलदल में धंसना जारी है. वर्तमान में 5,123 किसान डिफाल्टर की श्रेणी में हैं, जिनके ऊपर 45 करोड़ 35 लाख रुपये की बक़ाएदारी है. 1986 किसानों के विरुद्ध 14 करोड़ 36 लाख रुपये के बक़ाए की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है. ज़मीन नीलाम होने के भय से बुंदेलखंड के स्वाभिमानी किसान ख़ुदकुशी के लिए मजबूर हो जाते हैं. कांग्रेस के झांसी जिलाध्यक्ष सुधांशु त्रिपाठी कहते हैं कि बुंदेलखंड में धन की लूट न हो, इसके लिए निगरानी ज़रूरी है. डॉ. आशीष पटैरिया कहते हैं कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले केंद्र सरकार यहां के 13 ज़िलों में पहले से मौजूद तालाबों और चेकडैमों आदि का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करा ले, ताकि इनके नाम पर पैकेज का पैसा डकारा न जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

हरी ओम उपाध्याय

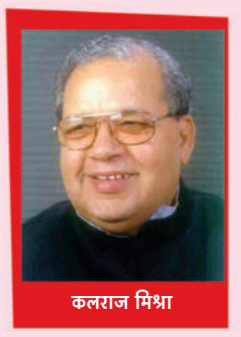

कलराज मिश्र

बिहारी लाल

दद्दू प्रसाद

राजा बुंदेला

बाबू सिंह कुशवाहा

विशंभर प्रसाद निषाद

जून से 27 अगस्त तक वर्षा की स्थिति (मिमी में)

ज़िला	सामान्य वर्षा	2008	2009	2010
झांसी	612.4	1039.7	263.1	370.3
ललितपुर	612.4	463.6	281.0	525.0
जालौन	532.2	591.5	213.7	441.4
हमीरपुर	587	952.5	306.7	262.3
महोबा	587	341.4	192.9	295.6
बांदा	642.4	925.4	248.3	370
चित्रकूट	642.4	313.6	226.6	241.5

चौथी दुनिया

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कई बार सही बात कही है. बड़े-बड़े उद्योग लगाइए, जो लाखों रोज़गार सृजित करेंगे.

महिलाएं जननी होती हैं. मां के रूप में वे जीवन की सृष्टि करती हैं और उसका पोषण करती हैं. उनके गर्भ में मानव जीवन अस्तित्व में आता है.

चौथी दुनिया

महावीर प्रसाद आर मोरारका

जिसकी लाठी उसकी भैंस

तीसरी योजना है कि जिसके पास ताक़त हो, वह ले ले. जो संभाल सके, वह रखे. यदि यह कार्यान्वित हुई तो विश्व में कहीं भी शांति या सुरक्षा का नामोनिशान ही नहीं रहेगा. अगर सब ताक़त में या चालाकी में समान हों तो संघर्ष और भी भयानक होंगे, परिणामस्वरूप कोई कुछ भी हथिया न सकेगा. बालक-वृद्ध कम ताक़त वाले हैं, युवा व्यक्ति अधिक ताक़त वाले हैं. अपनी मनोवृत्तियों में भले या बदमाश कई तरह के लोग होते हैं. दस्यु या डाकू भी लूटखसोट कर आख़िर में शांति की इच्छा रखते थे. लुटेरे आपस में लूट का बंटवारा करने के बाद जीवन शांति से बिताना चाहते हैं. पर अगर बल के आधार पर हथियाने का क्रम चालू हो तो आपसे ज़्यादा बल वाला, जब भी मौक़ा मिलेगा, आपको कमज़ोर देखेगा, तब आपको धर दबोचेगा. परिणाम होगा आपको हर घड़ी सतर्क रहना होगा, लिहाज़ा शांतिमय जीवन कदापि न हो सकेगा. लूटखसोट, डाकूपना क़ानूनन अवैध है, इसलिए इनको छोड़िए. पर दैनिक व्यापार में तो आपका मोदी, पंसारी या बजाज आपसे मुंह मांगे दाम ले सकता है.

जब वस्तुओं की कमी हो, तब दुगुने-चौगुने दाम वसूल कर लेगा. यह भी एक प्रकार की लूट ही तो है. आप जिस मकान में रह रहे हैं, उसका मकान मालिक अनाप-शनाप भाड़ा मांगने लगेगा और वसूल करेगा, चाहे उस मकान की क़ीमत नगण्य ही हो और चाहे आपकी दे सकने की सामर्थ्य भी न हो. इस तरह की सभ्य लूट को रोकने के लिए फिर नए-नए क़ानून बने. लड़ाई के ज़माने में जब वस्तुओं की बहुत कमी थी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत नफ़ाख़ोरी या कालाबाज़ार क़ानूनन दंडित अपराध घोषित कर दिए गए थे. आज भी कई वस्तुओं पर दाम निर्धारित हैं और उनसे ज़्यादा लेना अपराध है. मकान किराए को मनमाना न बढ़ा सकने के विरुद्ध रेंट कंट्रोल एक्ट है. ताक़त या चालाकी के बल पर चलने वाली यह योजना कभी कारगर नहीं हो सकती. कारण स्पष्ट है, अराजकता हो जाएगी और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला नई समस्याएं ही खड़ी करेगा. अत: यह मार्ग भी त्याज्य है. वित्त-वितरण का कोई सुगम तरीक़ा ढूंढना है.

पूंजीवाद

चौथी योजना है, कुछ के पास धन संग्रह रहे, बाक़ी सर्वसाधारण को उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त ही मिले. इसका नामकरण पूंजीवादी प्रथा किया जा सकता है. बहुत कुछ अंशों में कहा जा सकता है कि यह योजना या प्रथा इस वक़्त है. जनता में से, मान लीजिए, हर दस व्यक्तियों में से या हर 50 व्यक्तियों में से एक को प्रधान नियुक्त कर लिया गया. उसे गिरोह की संपूर्ण कमाई रखने का अधिकार दे दिया गया. बाक़ी 9 या 49 व्यक्ति दिन-रात परिश्रम करके उपार्जन करते रहें और उनका नेता वह एक व्यक्ति नेतृत्व या हुकूमत करता रहे. अब प्रश्न यह है कि वह एक आदमी कौन हो, उसका निर्णय कैसे हो? चुनाव भी हो सकता है, शायद वर्तमान में होता भी है. पर आज से 40-50 वर्ष पहले तक जो रूढ़ियां, परंपराएं थीं, उनके अनुसार वह व्यक्ति, नेता, ठाकुर, चौधरी या राजा अपनी ताक़त या बुद्धि के बल पर मुखिया बन बैठता था. बाद में उसके लड़के, पोते पारिवारिक उत्तराधिकार के रूप में वह नेतृत्व क़ायम रखते थे, कई अंशों में आज भी यह प्रथा क़ायम है.

इस तरह के वितरण का उस समय अत्यंत उपयोग रहा होगा, जब मानव की सभ्यता बहुत ही प्रारंभिक अवस्था की थी. उस नेता का कर्तव्य होता था कि वह विज्ञान, कला, साहित्य विद्या, अध्ययन, व्यापार आदि को प्रोत्साहन दे. समाज के लाभ के लिए जो पूंजी उसने अपने आश्रितों या प्रजा से इकट्ठी की है, उसे वह उचित तरीक़े से ख़र्च करे. आज भी इस प्रथा को जीवित रखने के लिए यह ज़ोरदार दलील है कि समस्त धनिकों का धन यदि ग़रीबों में बांट दिया जाए तो ग़रीबों की ग़रीबी में तो बहुत ही कम फ़र्क़ पड़ेगा, क्योंकि वे संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धनिक सब धनहीन हो जाएंगे. परिणामस्वरूप पूंजी का ह्रास होगा और देश के लिए कोई भी उपयोगी संस्था, उद्योग या व्यवसाय उत्पन्न ही नहीं होंगे. भारत में 12 वर्ष पहले तक जबकि यहां विदेशी साम्राज्य था, इसी पूंजीवादी प्रथा को अत्यंत प्रोत्साहन मिला. कारण स्पष्ट है, थोड़े से व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों पर शासन करें तो यह ज़रूरी हो जाता है कि उन बहुत से व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति जो अपनी

पसंद के हों, वे उनका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएं. भारत पर हुकूमत चलाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा ही किया. राजा-महाराजा, ज़मींदार, जागीरदार, सेठ, साहूकार, उद्योगपति, धनकुबेर, बैंकर, वे इसी तरह से आम जनता या प्रजा का शोषण करके ही तो बन पाए हैं. अगर ऐसा है तो यह प्रथा किसी भी मायने में अच्छी क्यों है? प्रश्न उचित है. भारत को छोड़ दीजिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि बहुत आगे बढ़े हुए सभ्य देशों में भी यह सब है. जहां पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता है, वहां भी तो यह प्रथा थोड़े से फ़र्क़ से विद्यमान है. बात यही है कि अगर हर आदमी के पास 100-100 रुपये हों तो इससे कुछ नहीं हो पाता. बस वे अपना महीने का ख़र्च भर चला पाते हैं. पर मान लीजिए, 49 आदमियों के पास 100 रुपये के बदले में कुल 80-80 रुपये ही हों और पचासवें के पास 1000 हों और उसे वह किसी लाभ के काम में लगाकर 100 रुपये से कुछ स्थायी कोष बनाकर कुछ व्यवसाय किया जाए तो उन सभी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा लाभ है, जबकि महीने में 100 रुपये के बदले 80 रुपये मिलने में उनको कष्ट कम है.

यह पचासवां आदमी कौन हो? यह प्रश्न फिर भी रह जाता है. पाश्चात्य देशों में इसका भी एक प्रकार से वैधानिक निर्वाचन ही होता है. यह प्रथा बड़ी ही सुंदर थी. यह नेता नीति पर रहे तो शायद यह प्रथा अब भी अति उत्तम मानी जाएगी, पर मानव स्वभाव है, यह विचलित हुए बिना रह नहीं सकता. जब एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, उसे नेता, ठाकुर, राजा या कुछ भी कहें, उसमें प्रमाद आ ही जाता है. उसी प्रमाद के वशीभूत होकर जो व्यय कार्य उसे जनहित के लिए करने चाहिए, वे न करके अपनी अय्याशी या शौक़ों को पूरा करने में ख़र्च कर देता है. जो सेना उसे देश की सुरक्षा के लिए नियुक्त करनी चाहिए या प्रजा को लुटेरों, गुंडों या चोरों से बचाने के लिए रखनी चाहिए, वह सिर्फ़ अपनी ज़ालिमाना हुकूमत को क़ायम रखने के लिए ही काम में आनी शुरू हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों को देखकर जनता धीरे-धीरे इस प्रणाली के ही ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है. इसी कारण जन सभ्य देशों में यह प्रथा धीरे-धीरे अप्रिय हो रही है. अप्रिय होने का प्रधान कारण यह है कि पूंजीवादी पार्टियों की सरकार अच्छे से अच्छे विचार रखते हुए भी शासन अच्छी तरह से कर नहीं पाती. परिणामस्वरूप वे अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए हर प्रकार के उचित-अनुचित मार्गों का अनुसरण करने लगते हैं. स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियों के अंदर भ्रष्टाचार फैल जाता है. हर सरकारी नौकर कुछ भी करने का पुरस्कार चाहने लग जाता है. आप अपने अधिकार का वेतन भी बिना दक्षिणा चुकाए नहीं प्राप्त कर सकते.

उनका दृष्टिकोण यही है कि अगर सबके पास बराबर धन रहेगा तो देश के पास स्थायी बचत की कोई संपत्ति ही न रहेगी. इसलिए हर प्रयत्न से ये मज़दूरों को मज़दूरी कम देते हैं, ग़रीब वर्ग की ग़रीबी बढ़ाते रहते हैं. अमीरों और धनिकों के धन-कोष में वृद्धि करते रहते हैं. उनका कहना है कि पूंजी एकत्रित होगी तो उस संगठन से देश शक्तिशाली होगा और उसकी कमाई बढ़ेगी.

पर लोग महसूस करने लगे हैं कि उनका यह तर्क खोखला है. एकमात्र तर्क, जिससे पूंजीवादी प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें शायद कुछ तथ्य भी है, यह कि पूंजी निर्माण इस प्रथा के बिना संभव ही नहीं. चाहे जितनी आर्थिक योजनाएं बना ली जाएं, पूंजी के बिना सब स्कीमें फेल होंगी. उनकी दलील है कि आप भले ही पूंजीपति बदल लें, पर पूंजीवाद नहीं बदल सकते. अगर देश का उत्थान होगा तो पूंजीवादी प्रथा से ही होगा. राजा-महाराजा, ज़मींदार-जागीरदार इत्यादि जो आज से पहले के पूंजीपति थे, उनके बदले में आज आप सरकारी अफ़सरों को, उनके रिश्तेदारों को या अन्य कई व्यक्तियों को उसी तरह से कुछ कम-बेश रूप में देखेंगे. पूंजीवाद अवश्यंभावी है, क्या यह प्रश्न तय नहीं है? भारत की समाजवादी व्यवस्था, वर्तमान सरकार की समाजवादी व्यवस्था को कई व्यक्ति यही कहते हैं कि यह तो पूंजीवाद का ही दूसरा स्वरूप है. सारांश यह है कि इस योजना के वित्त-वितरण में भी संतोष तो नहीं हुआ.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

विकास दर धीरे-धीरे गिरने लगी है

वेन जियाबाओ पिछले दिनों लंदन गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस बात के लिए फटकारा कि उन्हें अपने अतिथि के सामने मानवाधिकार पर भाषण नहीं देना चाहिए, लेकिन तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पास जियाबाओ की बात सुनने के अलावा कोई विशेष चारा नहीं था, क्योंकि वह चीन से व्यापार और निवेश को इच्छुक थे. चीन ने ब्रिटेन को एक हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम बेचा है. जो कंपनी यूके में यह ट्रेन बनाती है, वह इसका उत्पादन बंद करने वाली है. चीन निर्मित यह ट्रेन वाक़ई ख़ूबसूरत है. रेल बनाने वाले प्राचीन देश ने उत्पादन बंद दिया है और मध्य क्षेत्र ने इसका अधिग्रहण कर लिया है.

आख़िरकार क्यों हाई स्पीड ट्रेन चीन बना सकता है और भारत नहीं बना सकता? भारतीय रेल प्रणाली गंदगी, भीड़भाड़, मंद गति और ख़तरनाक प्लेटफार्मों का पर्याय क्यों बन गई है? जब मैं 50 के दशक में भारतीय रेल से यात्रा किया करता था तो इसका भविष्य उज्ज्वल दिखता था, लेकिन हाल-फ़िलहाल का मेरा अनुभव डरावना रहा है. जहां तक मेरा अनुमान है, यह अंतर दोनों देशों के राजनीतिक शासन की अलग-अलग विशेषताओं के कारण है. हालांकि दोनों ही देशों में रेल विभाग सरकार के पास है, लेकिन भारत में यह मंत्रालय सरकार अपने सहयोगी दल को ईनाम के तौर पर देती है, ताकि ये मंत्री जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं, वहां अपने आधार को मज़बूत करने में इसका इस्तेमाल कर सकें. रेल भाड़ा कम रखना सस्ती लोकप्रियता का साधन बन गया है, लेकिन ये लोग यह समझने की कोशिश नहीं करते कि यात्री अच्छी सुविधा के लिए थोड़ा ज़्यादा भाड़ा देने से परहेज़ नहीं करेंगे. भारत एशिया में सबसे प्राचीन रेल प्रणाली वाला देश है, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत रेलवे के क्षेत्र में विस्तार के अलावा इससे जुड़ी अन्य सभी गतिविधियों में नेतृत्व खो चुका है.

1950 के दशक में हमने इस वायदे के साथ महालानोविस मॉडल अपनाया था कि भारत मशीनें बनाने के लिए मशीन बनाएगा, ताकि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकें और इस क्षेत्र में सबसे आगे खड़े हों. तो फिर भारत में तेज़ गति की रेलें बनाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? भारतीय रेल के कोच का डिजायन इतना घटिया क्यों होता है? खाने के विकल्प सीमित होते हैं और खाना अस्वास्थ्यकर होता है. टॉयलेट्स के बारे में तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है. एक बार फिर उत्तर वही है कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की गुणवत्ता बिगड़ गई है. जब भारत ने पहली कार बनाई तो हमने एंबेसडर मॉडल अपनाया और आज भी नौकरशाहों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. बेशक मारुति को भारत में स्थापित किया गया, लेकिन यह केवल युवराज संजय गांधी को अपने पसंदीदा खिलौनों के साथ व्यस्त रखने के लिए था. आज भी भारत निर्मित कारों की स्थिति दारुण ही होती, यदि निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जाती.

जब आप भारतीय उद्योगपतियों से बात करते हैं और ख़ासकर जब वे बाहर हों तो सामान्यतय: वे भारत के चमत्कारिक विकास की

बात करेंगे. यहां इस बात की काफ़ी संतुष्टि है कि विकास दर 8.5 फ़ीसदी है, जो 9 फ़ीसदी से थोड़ी ही कम है. लेकिन मेरा अनुमान है कि यह 7 से 7.5 फ़ीसदी के बीच ही होगी. यूपीए-2 ने पहले दो साल में कोई सुधार नहीं किया और ऐसा लगता है कि यह लोकपाल की उलझन और घोटालों के दलदल से फ़िलहाल 2012 के अंत तक निकल भी नहीं पाएगा. तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस उलझी रहेगी और सुधार की बात धरी की धरी रह जाएगी. ऐसी बात नहीं है कि कोई यह नहीं जानता कि क्या किया जाना है.

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कई बार सही बात कही है. बड़े-बड़े उद्योग लगाइए, जो लाखों रोज़गार सृजित करेंगे. आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आ रहे ह्रास पर क़ाबू पाइए, भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों को निपटाइए, जनजातियों और अन्य लोगों के संपत्ति के अधिकार को स्थापित कीजिए और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थाओं की मांग को विदेशी संस्थाओं को अनुमति देकर समाप्त कीजिए. लाखों लोगों को शिक्षित कीजिए, यही सब भारत की जनता को लाभ दिलाएंगे. बाल कुपोषण को समाप्त कीजिए. हम लोगों ने कितने समय में जाना है कि ये सारी बातें भी एजेंडे में थीं. 21वीं सदी के पहले कुछ वर्षों में आसानी से मिली 8-9 फ़ीसदी की उच्च वृद्धि दर ने भारतीय नेताओं को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन तब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की सवारी कर रहा था. जब बूम समाप्त हुआ तो विकास दर धीरे-धीरे गिरने लगी और फिर कभी दोबारा 9 प्रतिशत और इसके ऊपर नहीं पहुंची. 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की विकास दर तो सूखे के साल से बाहर निकलने (रिकवरी) की वजह से हासिल हुई थी. जल्दी कीजिए, इससे पहले कि विकास की यह धीमी फिसलन व्यवस्था को धराशायी न कर दे, परिवर्तन कीजिए.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

जस्टिस पी सथाशिवम और चौथी दुनिया को बधाई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति ए के पटनायक द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रकरण पर की गई टिप्पणी निस्संदेह जनहितकारी है. चौथी दुनिया तो शुरू से ही लिखता-कहता रहा है कि किसानों एवं आम देशवासियों की दिक्क़तों को गहनता से समझा जाए और उनका स्थायी समाधान हो. यह अजब संयोग है कि जस्टिस पी सथाशिवम चौथी दुनिया अख़बार के लेखकों में शामिल रहे हैं और उनकी एवं चौथी दुनिया की विचारधारा में ख़ासा साम्य दिखता है. जो बातें अब तक चौथी दुनिया अपने विभिन्न आलेखों में कहता आया है, वही चिंता न्यायमूर्तिद्वय पी सथाशिवम एवं ए के पटनायक ने अपने ताज़ा फ़ैसले में ज़ाहिर की है. इसके लिए जस्टिस पी सथाशिवम और चौथी दुनिया को बधाई.

त्रिलोक कुमार झा, ई-मेल से.

पारसियों-यहूदियों की बदतर हालत

चौथी दुनिया के 13-19 जून के अंक में प्रकाशित विभिन्न आलेख काफी पसंद आए. मुख्य आलेख मुस्लिम समाज का दर्द मुसलमानों की बदहाली को प्रस्तुत करता है. यह साफ़ है कि सभी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किंतु मुस्लिम समाज से भी अधिक दुर्दशा पारसी एवं यहूदी संप्रदाय की है, जो दुनिया में अल्पसंख्यक हैं. संसार में यहूदियों का एकमात्र देश इज़रायल है, जबकि पारसियों का एक भी देश नहीं है. ईरान में रहने वाले काफ़ी पारसियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और बहुत से लोग भारत आ गए. पारसियों का रहन-सहन एवं भाषा-व्यवहार मुस्लिमों से काफ़ी मिलता-जुलता है. आपसे अनुरोध है कि पारसियों और यहूदियों की समस्याओं पर भी लेख प्रकाशित करें.

***यतींद्र प्रताप साही**, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

शिक्षा का आधुनिकीकरण और बौद्धिकता

आधुनिक दौर में शिक्षा का भी आधुनिकीकरण हो गया है. आज शिक्षा का मतलब सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है. बच्चे 70 से 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं, परंतु बौद्धिकता की कसौटी पर परखा जाए तो वे औसत से भी कम साबित होते हैं. उन्हें सिर्फ़ उतना ही ज्ञान होता है, जितना उन्होंने किताबों से सीखा है. आज की शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक स्तर सीमित हो गया है. वे न्यूटन के गति के नियम को तो समझ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में पीछे जा रहे हैं. लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे कंप्यूटर की तरह तेज़ हों, मगर वे यह भूल जाते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है. बच्चे भी मशीन की तरह कार्य करने लगे हैं. उनमें भावनाएं समाप्त हो रही हैं. मौजूदा शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान और कला वर्ग के बीच खाई पैदा कर दी है. प्राचीन भारत में शिक्षा का ध्येय बौद्धिक स्तर बढ़ाना था. देश में अनेक महान दार्शनिक, गणितज्ञ, चिकित्सक और राजनीतिज्ञ हुए हैं. आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, यह आपको और समाज को तय करना है.

-अभिनव खरे, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

एमएफ हुसैन का जाना

मौत शाश्वत है. जो इस धरा पर आया है, उसका एक न एक दिन जाना तय है, लेकिन कुछेक लोगों का जाना समाज को देर तक कचोटता रहता है. मक़बूल फिदा हुसैन के जाने से कुछ ऐसा ही लगा. लगातार विवादों, मुक़दमों एवं आलोचनाओं को लांघते हुए अपने कैनवास के सामने डटे रहना कला के प्रति उनकी असीम जिजीविषा को ही दर्शाता है. अपनी कृतियों को उन्मादियों द्वारा तोड़ने-फोड़ने और आग के हवाले करने के बावजूद उनका जवाब उन्होंने घृणा या आक्रोश से देने के बजाय सृजन से दिया. निस्संदेह भारत के पिकासो के जाने से कला जगत की अपूरणीय क्षति हुई है.

***हर्षवर्द्धन कुमार**, पटना, बिहार.*

शिकायत और सराहना

चौथी दुनिया के 6-12 जून के अंक में प्रकाशित लेख-दयालु साई बाबा में मस्जिद में नाच, घुंघरुओं एवं सारंगी की आवाज़ और साई का अस्वाभाविक चमत्कार पढ़कर बड़ा अजीब लगा. यह पहली बार पढ़ने को मिला कि इबादतगाह मस्जिद में साई की उपस्थिति में रासरंग चलता था. कृपया ऐसे प्रसंग प्रकाशित न करें. मुसलमान इस्लाम को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं. ऐसे प्रसंगों से उनकी भावनाएं आहत होती हैं. इसी अंक में प्रकाशित फ़िरदौस ख़ान की महुआ माजी से बातचीत पसंद आई.

***डॉ. सेराज ख़ान बातिश**, कोलकाता, पश्चिम बंगाल.*

चौथी दुनिया को सलाम

चौथी दुनिया में प्रकाशित लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें बहा दीं, पढ़कर अख़बार के जज्बे, साहस और सच्ची पत्रकारिता को सलाम करने को जी चाहता है. आप हक़ और इंसाफ़ के लिए क़लम चला रहे हैं, जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है. मनीष कुमार बधाई के पात्र हैं. चौथी दुनिया एक ऐसा अख़बार है, जिसे सभी को पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए.

***शिबली रामपुरी**, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

राहुल जी, गांव में आपने क्या सीखा

बापू जब मोहनदास करमचंद गांधी थे, नौजवान वकील थे और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए तो उनके साथ एक हादसा हुआ. गोरों ने उन्हें प्रथम श्रेणी में बैठने के लायक़ नहीं समझा और ज़बरदस्ती गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दिया. जब वह हिंदुस्तान वापस आए, उनके मन में हिंदुस्तान में कुछ काम करने की इच्छा जागी. उन्हें लगा कि वह हिंदुस्तान में कुछ नया कर सकते हैं. उथल-पुथल उनके मन में मची हुई थी कि काम करना है, क्या करना है और कैसे करना है. वह सलाह लेने के लिए उस समय के एक बड़े राष्ट्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए. उन्होंने गोखले को अपने मन के भीतर चल रहे द्वंद्व से परिचित कराया. गोखले ने नौजवान मोहनदास करमचंद गांधी की बात को बहुत ग़ौर से सुना, उनका चेहरा देखा और एक छोटी सी सलाह दी कि अगर हिंदुस्तान में कुछ काम करना चाहते हो तो पहले हिंदुस्तान को समझो. गांधी ने पूछा कि हिंदुस्तान को समझने का मतलब क्या है. गोखले ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान को समझने का मतलब है हिंदुस्तान में ग़रीबी के कारण, हिंदुस्तान की ग़ुलामी के कारण, हिंदुस्तान में पिछड़ेपन के कारण, हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ का विरोध न करने की आदत के पीछे का कारण, हिंदुस्तान में समाज के तनाव, हिंदुस्तान में समाज के भीतर पनप रहे अंतर्विरोध, क्या है हिंदुस्तान, क्या वह हिंदुस्तान असली है जो बंबई और दिल्ली में दिखाई देता है या जो गवर्नर और वायसराय की पार्टी में दिखाई देता है या असली हिंदुस्तान कहीं अलग है?

गांधी ने पूछा, आख़िर असलियत क्या है? गोखले ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम किसी से सुनकर इसे न समझो. ख़ुद देखो और महसूस करो और समझो कि असली हिंदुस्तान क्या है और इस यात्रा के दौरान तुम्हें अपने काम करने का सही मक़सद, सही रास्ता मिल जाएगा. गांधी गोखले के पास से आए और उन्होंने दो साल के अंदर लगभग पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के गांवों को यानी हर जगह अपनी आंखों से जाकर देखा, महसूस किया, बातचीत की कि आख़िर इन चीज़ों का कारण क्या है. गांधी को जवाब मिला, कारण ग़ुलामी है. अंग्रेजों की ग़ुलामी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों की तरक़्क़ी के लिए, इनकी ख़ुशी के लिए कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं जाता है. यहां का पैसा विदेश में जाता है, यहां का बनाया हुआ माल विदेश में जाता है. विदेश से कच्चा माल यहां आता है और यहां पक्के माल में परिवर्तित होकर फिर विदेश चला जाता है. दो साल में गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तान की संपूर्ण आज़ादी ही हिंदुस्तान की समस्याओं का इलाज है और वहां से गांधी की यात्रा शुरू हुई, जो बापू में तब्दील हुई, जिसने हिंदुस्तान को ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया. उन दिनों के क्रांतिकारी रहे हों या अहिंसक आंदोलन के लोग, सभी के ऊपर गांधी का प्रभाव पड़ा. बापू का प्रभाव पड़ा. एक पार्टी जो सिर्फ़ समाज सुधार का काम करती थी, एक राष्ट्रीय पार्टी सचमुच लोगों के दिल की पार्टी बन गई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आज़ादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. लोग टूटे, छिटके, अंतर्विरोध आए, लेकिन आज़ादी की वह लड़ाई नहीं रुकी.

आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह जब पिछले तीन दिनों में गांवों में गए या शायद इससे पहले भी तीन-चार दिनों के लिए गए तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वह सीखा, जो न उन्हें दिल्ली सिखा पाई और न संसद. यह बहुत ईमानदाराना वक्तव्य कहा जाएगा, लेकिन क्या यह सचमुच ईमानदाराना वक्तव्य है? क्या तीन दिन, पांच दिन, दस दिन या पंद्रह दिन में हिंदुस्तान की समस्याओं को समझा जा सकता है, हिंदुस्तान को जाना जा सकता है? आज़ादी के समय हिंदुस्तान की समस्या छूआछूत थी, ग़रीबी थी, बेरोज़गारी थी, पिछड़ापन और ग़ुलामी थी, हिंदुस्तानियों का दमन थी. आंखों में कोई सपना नहीं था. आज भी ये समस्याएं हैं, लेकिन कम परिमाण में हैं. समस्याओं का प्रकार बदल गया है. राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. शायद वह अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री बन भी जाएं, पर अगर राहुल गांधी इस यात्रा में कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाए तो उनकी यह यात्रा किसी पब्लिक रिलेशन कंपनी द्वारा सुझाई गई यात्रा में तब्दील होकर रह जाएगी. आख़िर राहुल गांधी को क्या सीखना है?

राहुल गांधी को सीखना है कि जिन गांवों से होकर वह जा रहे थे, जिन पगडंडियों से होकर वह गुज़र रहे थे, वे अभी तक पक्की क्यों नहीं हुईं, आज़ादी के साठ साल बाद भी हिंदुस्तान के गांवों को सड़कों से क्यों नहीं जोड़ा जा सका? राहुल गांधी को यह सीखना है कि वह जिन खेतों से गुज़र रहे थे, क्या उन खेतों की फ़सलें मंडियों तक सही समय पर पहुंच पाती हैं, क्या किसानों को उनकी फ़सल की सही क़ीमत मिल पाती है, क्या

गांधी ने पूछा, आख़िर असलियत क्या है? गोखले ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम किसी से सुनकर इसे न समझो. ख़ुद देखो और महसूस करो और समझो कि असली हिंदुस्तान क्या है और इस यात्रा के दौरान तुम्हें अपने काम करने का सही मक़सद, सही रास्ता मिल जाएगा. गांधी गोखले के पास से आए और उन्होंने दो साल के अंदर लगभग पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के गांवों को यानी हर जगह अपनी आंखों से जाकर देखा, महसूस किया, बातचीत की कि आख़िर इन चीज़ों का कारण क्या है.

उनकी फ़सलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल पाता है, क्या किसानों को सही समय पर और सही मात्रा में बीज तथा खाद उपलब्ध हो पाते हैं? जिन गांवों में राहुल गांधी खाना खा रहे हैं, जहां वह चाय पी रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि इन गांवों में पीने के पानी की समस्या है क्या? आख़िर यह क्या और कैसे हो गया कि आज़ादी के साठ साल के अंदर ही अधिकांश गांवों से पीने का पानी समाप्त हो गया. राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि जिन गांवों से होकर वह निकल रहे हैं, वहां दलितों और सवर्णों या दलितों और पिछड़ों के बीच कोई अंतर्विरोध तो नहीं है, उनके बीच कोई वैमनस्य तो नहीं है? राहुल गांधी जिन गांवों से होकर निकल रहे हैं, वहां पिछड़ों और सवर्णों के बीच तनाव कहीं कोई ख़तरनाक स्थिति तो पैदा नहीं कर रहा है, उन गांवों में बाल विवाह तो नहीं हो रहे हैं?

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन गांवों में रह रहे नौजवान जिनके प्रतिनिधि होने का दावा राहुल गांधी करते हैं और जिन्हें राजनीति में लाने की बात वह करते हैं, उनमें से कितनों के पास रोज़गार है? हमने टेलीविजन पर जो भीड़ देखी, राहुल गांधी के साथ चलते हुए जो लोग देखे, वे पूरे कपड़े पहने हुए लोग थे. क्या राहुल गांधी इन पूरे कपड़े पहने हुए लोगों से आगे जाकर गांव के दूसरे हिस्सों में रहने वाले उन परिवारों की व्यथा को समझ पाए, जिनके पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है? उन्हें पूरा खाना भी नहीं मिलता, न्यूट्रीशन की बात तो छोड़ ही दीजिए. वहां बच्चों का ड्राप आउट कितना है, क्या वहां प्राइमरी स्कूल हैं? और अगर हैं तो उनकी हालत क्या है? क्या वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ाता है? जिन गांवों से वह गुज़रे, क्या वहां उन्होंने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखा, क्या उन्होंने सोचा कि अगर यहां के लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कहां कराते हैं? और अगर यह सब नहीं है तो इसका कारण क्या है? पिछले साठ सालों से, जबसे देश आज़ाद हुआ, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? वह कौन सी मानसिकता ज़िम्मेदार है, जो देश के 80 प्रतिशत लोगों तक विकास का लाभ नहीं पहुंचने दे रही है? गांव वालों के मन में क्या कोई आशा है, जो इस मुल्क को नए सिरे से बनाने में काम आ सके? अगर राहुल गांधी इन बुनियादी बातों को नहीं समझ पाए तो उनका इन गांवों में या किसी और गांव में घूमना बेकार है. पर अगर राहुल गांधी सचमुच इन चीज़ों को समझ पाए तो हमारा मानना है कि देश को एक नया समझदार नौजवान नेतृत्व शायद मिल जाए. कांग्रेस के लोग इसका जवाब यह कहकर दे सकते हैं कि हमारा तो कम से कम एक नेता गांवों में जा रहा है, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं. दिल्ली, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ किसी भी राजधानी में बैठकर, आलीशान बंगलों में बैठकर वे केवल ग़रीब जनता की बात करते हैं. कांग्रेस का आरोप सही है, लेकिन आरोप लगाने से आपकी अपनी कमियां नहीं छुप जातीं. क्यों ऐसा है कि जब राहुल गांधी गांव में जाने की बात करते हैं तो सारे नेता उनके साथ चल पड़ते हैं, क्यों नहीं वे अपने-अपने क्षेत्रों के गांवों में जाते हैं?

कांग्रेस, जिसने देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगर वह ज़रा भी ज़िम्मेदारी का एहसास करती है तो यह देश के लिए भले की बात है, मगर वह ज़िम्मेदारी ईमानदाराना होनी चाहिए, विश्वास वाली होनी चाहिए. अन्यथा कांग्रेस नए सिरे से लोगों के बीच आशा पैदा कर फिर से उसे तोड़ने का काम करेगी. कांग्रेस पहले भी कई बार लोगों की आशा तोड़ चुकी है. देश का नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि कांग्रेस और विपक्ष दोनों को बार-बार याद दिलाएं कि उनका देश के प्रति भी कोई फ़र्ज़ है और देश से मतलब अमीरों और मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से नहीं है, देश का मतलब ग़रीबों से है, वंचितों से है, अल्पसंख्यकों से है. राहुल गांधी ने क्या इन गांवों में अल्पसंख्यकों की हालत देखी, उनके पास रोज़गार के कोई साधन देखे, उनकी शिक्षा की संस्थाएं देखीं? अगर देखीं तो हमारी मांग है कि इन सारे सवालों पर राहुल गांधी को मीडिया के सामने आकर अपनी फाइंडिंग्स, अपनी जानकारी शेयर करनी चाहिए, ताकि देश के लोगों को यह भरोसा हो कि जो नौजवान सीखने की बात ईमानदारी से कहकर निकला, उसने सचमुच ईमानदारी से सीखने की कोशिश की.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

डॉ. असगर अली इंजीनियर

शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका

क्या पुरुषों की तुलना में महिलाएं शांति स्थापना में बेहतर भूमिका अदा कर सकती हैं? कई स्त्रीवादियों का मानना है कि शांति स्थापना के कार्य लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कहीं अधिक उपयुक्त हैं. क्या महिलाओं में वे कमज़ोरियां नहीं होतीं, जो पुरुषों में होती हैं? क्या वे पुरुषों से बेहतर शासक साबित हुई हैं? वे कौन से कारक हैं, जो महिलाओं को पुरुषों से बेहतर शांति कार्यकर्ता बनाते हैं? हमारा समाज पितृसत्तामक है और अधिकांश महिलाएं दमित एवं शोषित हैं. अधिकतर मामलों में महिलाएं इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं, इसे अपनी किस्मत मान लेती हैं. वे घर-गृहस्थी तक सिमट जाती हैं और अपने पति एवं बच्चों की सेवा-सुश्रुषा को ही अपनी नियति मान लेती हैं. कुछ महिलाओं को घर-गृहस्थी संभालने के अलावा नौकरी भी करनी पड़ती है. उन पर दोहरा बोझ रहता है. औपचारिक लैंगिक बराबरी के बावजूद पश्चिम के उन्नत प्रजातांत्रिक देशों में भी महिलाओं को पितृसत्तामक सांस्कृतिक मूल्यों का बोझ ढोना पड़ता है. इस तरह पूरी दुनिया में महिलाएं दमित हैं और दमित वर्ग हमेशा दमनकारियों की तुलना में शांति की क़ीमत बेहतर समझता है. यह महिलाओं के शांति का बेहतर वाहक होने का पहला कारण है.

महिलाएं जननी होती हैं. मां के रूप में वे जीवन की सृष्टि करती हैं और उसका पोषण करती हैं. उनके गर्भ में मानव जीवन अस्तित्व में आता है. महिलाएं शिशु को नौ महीने तक अपने गर्भ में पालती हैं और उसके बाद अपना जीवन दांव पर लगाकर उसे दुनिया में लाती हैं. शिशु के पैदा होने के बाद भी महिलाओं को सालों तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है. मां से ज़्यादा जीवन का मूल्य भला कौन समझ सकता है? इसके विपरीत शक्ति के अहंकार के चलते पुरुष सत्ता की ख़ातिर किसी की जान लेने में भी तनिक नहीं सकुचाता. महीनों तक कष्ट भोगकर अस्तित्व में लाए गए जीवन को आधुनिक हथियारों के ज़रिए पल भर में समाप्त कर दिया जाता है. एक बटन दबाकर लाखों मनुष्यों की हत्या कर दी जाती है. एक महिला, जो जीवन को जन्म देती है और उसे पालती-पोसती है, वह कभी ऐसे युद्धोन्माद को प्रोत्साहित नहीं करेगी. पितृसत्तामक समाज में महिलाओं की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रहती. इसलिए उनका जीवन सत्ता के इर्द-गिर्द नहीं घूमता. चूंकि पुरुषों को गर्भधारण और शिशु जन्म की कष्टप्रद प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ता, इसलिए वे मानव जीवन के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते, जितनी महिलाएं. महिलाओं में जीवन के प्रति संवेदनशीलता पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है.

जीवन फलने-फूलने के लिए प्यार और संवेदनाओं की ज़रूरत होती है. घृणा से जीवन नष्ट होता है और प्रेम से पल्लवित. घृणा का जन्म अक्सर सत्ता संघर्ष से होता है. सत्ता का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है और वह इस ख़ातिर मानव जीवन का बलिदान करने से भी नहीं चूकता. ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी की जान नहीं ले सकतीं या नहीं लेतीं, परंतु जहां पुरुष क्रूरतापूर्वक हत्याएं करते हैं, वहीं महिलाएं किसी की जान लेने से पहले दस बार सोचती हैं. जीवन के प्रति महिलाओं और पुरुषों का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है. अगर महिलाएं सत्ता संघर्ष में शामिल होती हैं, तब भी वे निर्ममता से दूसरों की जान नहीं लेतीं. वे स्वभाव से ही दयालु होती हैं. हद से ज़्यादा प्रताड़ित किए जाने पर ही उनमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है. पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक धैर्यवान होती हैं. धैर्य और कष्ट सहने की क्षमता दो ऐसे गुण हैं, जो महिलाओं में अधिक होते हैं और इसी कारण वे मां बन पाती हैं.

कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं कम अपराध करती हैं. सैन्यबलों में महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर है. पिछले कुछ सालों से महिलाएं सेना के लड़ाकू दस्तों में भी भर्ती हो रही हैं, परंतु उसके पीछे युद्ध करने में रुचि कम, यह साबित करने की इच्छा ज़्यादा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं. मैं यह नहीं कहता कि महिलाओं को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, परंतु मेरी मान्यता है कि उन्हें सिर्फ़ रक्षात्मक लड़ाई लड़नी चाहिए. वे आक्रामक युद्ध के लिए बनी ही नहीं हैं. इस मामले में पुरुषों को महिलाओं से सीखने की ज़रूरत है. स्त्रीवादी कह सकते हैं कि आख़िर महिलाओं को पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर

युद्ध में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए. अगर महिलाएं हर मामले में पुरुषों के समकक्ष हैं तो युद्ध के मामले में क्यों नहीं. उन्हें भी लड़ाई के मैदान में पुरुषों जैसी क्रूरता और आक्रामकता का प्रदर्शन करना चाहिए. यह बात तार्किक लगती है, परंतु तर्क हमेशा सही राह नहीं दिखाते. महिलाओं को मातृत्व का वरदान प्राप्त है और मातृत्व के लिए ज़रूरी हैं जीवन को संरक्षण देने और उसे ख़तरों से महफ़ूज़ रखने के गुण, जो उन गुणों के ठीक विपरीत हैं, जो एक सफल योद्धा में होने चाहिए.

पितृसत्तामक मूल्यों के पैरोकार इस तर्क का इस्तेमाल महिलाओं को बराबरी के दर्जे से महरूम करने के लिए कर सकते हैं, परंतु हमें कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी दुविधा का सामना करना ही पड़ता है और उस दुविधा से हमें न तो केवल तार्किकता बाहर निकाल सकती है और न परंपरावादिता. इस धरती को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल सकारात्मक मूल्य. पितृसत्तामक व्यवस्था से न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक मूल्यों का घोर अभाव उत्पन्न हो गया है, वरन् मानवता को अनेक हादसों से भी गुज़रना पड़ा. इतिहास में अब तक हुई हज़ारों लड़ाइयों में करोड़ों जानें जा चुकी हैं. ये सब लड़ाइयां क्यों हुईं? केवल इसलिए, क्योंकि एक पितृसत्तामक समूह दूसरे पितृसत्तामक समूह पर अपनी प्रभुता क़ायम करना चाहता था. अगर हमारी दुनिया मातृसत्तामक होती तो शायद इसका चेहरा और इतिहास एकदम भिन्न होता. यह समझना महत्वपूर्ण है कि मातृसत्तामक मूल्य जीवन के प्रति हमारे मूल नज़रिए को ही बदल देते हैं. मातृसत्तामक व्यवस्था का मूलमंत्र है ज़िंदगी को संरक्षित करने वाले कारकों को प्रोत्साहन देना और शांति इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है. किसी भी युद्ध या हिंसक संघर्ष में मनुष्यों की जानें तो जाती ही हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले तत्वों का विनाश भी होता है. हर युद्ध अपने साथ जीवन स्तर में गिरावट लाता है.

इसके विपरीत जीवन की बेहतरी महिलाओं की चिंता का मुख्य विषय रहता है. जीवन समृद्ध और पूर्ण तभी हो सकता है, जब शांति हो और इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में पितृसत्तामक व्यवस्था के बजाय मातृसत्तामक व्यवस्था हो. पुरुषों द्वारा तैयार की गईं शांति संधियों का चरित्र अस्थायी होता है. दोनों पक्ष इन संधियों के जरिए केवल फिर से युद्ध की तैयारी के लिए समय चाहते हैं. इसके विपरीत महिलाओं की प्राथमिकता अगला युद्ध लड़ना और जीतना नहीं, वरन् स्थायी शांति स्थापित करना होगा, क्योंकि स्थायी शांति जीवन को समृद्ध करती है. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा लागू की जाने वाली संधियों को तैयार करने में मुख्यत: पुरुषों की भूमिका होती है. ये संधियां इतनी जटिल होती हैं कि कोई न कोई देश संधि की किसी न किसी शर्त का उल्लंघन कर ही देता है और यह एक नए युद्ध का बहाना बन जाता है. ऐसी संधियों में ज़ोर उस देशभक्ति पर रहता है, जो शांति स्थापना को नहीं, बल्कि अधिक से अधिक भूमि क़ब्ज़ाने को अपनी सफलता मानती है. अगर महिलाएं शांति संधियों का मसौदा तैयार करें तो शायद वे उनमें ऐसी शर्तें डालें, जिनसे हिंसा के पुन: फूट पड़ने की आशंका कम से कम रहे.

स्थायी शांति के लिए यह आवश्यक है कि सभी धार्मिक विचारधाराओं में विश्वास रखने वालों और विभिन्न धर्मावलंबियों को बराबरी का दर्जा मिले. सभी नस्लीय समूहों, विशेषकर अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों को एहसास हो कि देश उनका भी है. शांति तभी स्थायी हो सकती है, जब समाज को बांटने वाली बातों को दरकिनार कर दिया जाए. इतिहास बताता है कि जमीन के ऐसे टुकड़ों की ख़ातिर, जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, हजारों लोगों की जानें ले ली गईं. सच्ची शांति तभी स्थापित होगी, जब हम जमीन से कम और मनुष्यों से अधिक प्रेम करें. देशभक्ति को भूमि पर स्वामित्व से जोड़ना एक ख़तरनाक अवधारणा है. इसी के चलते माताओं को ऐसे पुत्रों को जन्म देने के लिए सम्मानित किया जाता है, जो देश की भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं. यह महिलाओं की शांति की अवधारणा नहीं है. यह एक सामंती और पितृसत्तामक अवधारणा है. ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए जानें गंवाने से शांति नहीं आएगी. शांति के लिए हमें चाहिए धैर्य, सहिष्णुता, प्रजातंत्र और सबको साथ लेकर चलने की इच्छा.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आस्ट्रेलिया की आदिम प्रजाति और नेपाल में पाई जाने वाली किराती मूल प्रजाति के लोगों की औसत आयु अपने ही देश की दूसरी जनसंख्या से 20 वर्ष कम है.

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आवासीय इलाक़ों में ग़ैर क़ानूनी व्यवसायिक गतिविधियां

यह समस्या लगभग हर छोटे–बड़े शहर की है. आवासीय–रिहायशी इलाक़ों में लालची और स्वार्थी क़िस्म के लोग ऐसे–ऐसे व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उस इलाक़े में रहने वाले लोगों के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. मसलन, जहां अवैध गोदाम, पार्किंग, मोटर वर्कशॉप चल रहे हैं, जिनकी वजह से वहां प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही वहां रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं. सवाल यह है कि सरकार और अदालतों के स्पष्ट आदेशों के बाद भी आख़िरकार रिहायशी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की इजाज़त कौन देता है? इस सवाल का एक आम जवाब लोग यह देते हैं कि यह व्यवसाय रिश्वतख़ोरी की वजह से ज़िंदा है. बहुत हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के अवैध व्यवसाय के बारे में सरकारी अधिकारियों या संबंधित विभागों को जानकारी नहीं होती है. इस तरह के व्यवसायी पैसे की बदौलत अपने ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने देते. यह तो बात समस्या की थी, अब समाधान की बात करते हैं कि कैसे इस समस्या का हल एक आम आदमी ख़ुद निकाल सकता है. इस अंक में हम एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें हमने इस समस्या से निजात पाने संबंधी उपाय बताए हैं. इस आवेदन का इस्तेमाल करके आप यह सूचना पा सकते हैं कि आपके इलाक़े में ऐसे कितने भवन हैं, जिनका उपयोग क़ानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. आप ऐसे भवनों की सूची मांग सकते हैं. इनके ख़िलाफ़ संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसका पूर्ण विवरण मांगा जा सकता है. आप इस आवेदन के इस्तेमाल से उन नियमों, क़ानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी भी ले सकते हैं, जिनका उल्लंघन किया जा रहा है. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सज़ा अथवा नियम के मुताबिक़ की जाने वाली कार्रवाई का विवरण भी मांगा जा सकता है. ऐसे मामले में संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी भी जुटाई जा सकती है. अगर आप चाहें तो ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराकर उसके बाद एक आरटीआई आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आप यह पूछ सकते हैं कि आपकी शिकायत पर संबंधित विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है. आप अपने इलाक़े के कई लोगों की ओर से भी आवेदन और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि संबंधित विभाग पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बने.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

कृपया.....क्षेत्र में व्यवसायीकरण से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:
1. उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी भवनों की सूची प्रदान करें, जिनका उपयोग क़ानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.
2. ऐसे प्रत्येक मामले में किस तरह के क़ानूनों का और किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है? इसका विवरण दें. आपके विभाग को इन उल्लंघनों के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली?
3. इन उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दें.
4. कृपया उन नियमों, क़ानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी दें, जिनका आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उल्लंघन हुआ है.
5. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सज़ा अथवा नियम के मुताबिक़ की जाने वाली कार्रवाई का विवरण दें.
6. ऐसे प्रत्येक मामले में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रत्येक घटना का अलग-अलग पूरा विवरण दें. यदि किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों?
7. मैं ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेज़ों एवं फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे दिन, समय एवं स्थान के बारे में सूचित करें, जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं.
8. उन अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क का विवरण बताएं, जो इस व्यवसायीकरण के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार हैं.
9. क्या ये अधिकारी क़ानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई न करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण क़ानून की धारा 13 (घ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?
10. इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ अब आगे कब और क्या कार्रवाई की जाएगी?
11. उपरोक्त व्यवसायीकरण कब तक पूर्ण रूप से रोक अथवा हटा दिए जाएंगे?
12. उपरोक्त क्षेत्र से दिनांक.....से.....के दौरान आपके विभाग को व्यवसायीकरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

भूखों की रोटी कहां है

यूं तो भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में अगला स्थान हासिल है, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जो इस सच को ठुकराने लगते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़कर 6.3 करोड़ हो गई है. एक ग़ैर सरकारी संस्था द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि ख़राब आहार प्रणाली और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के कारण भूखे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है. संस्था के प्रबंधक का कहना है कि भूखे लोग या यूं कहें कि जिन लोगों को दो वक़्त का भोजन कभी–कभी ही नसीब होता है, उनकी संख्या इस वजह से बढ़ी, क्योंकि आर्थिक विकास में ग्रामीण ग़रीबों को नहीं शामिल किया गया. सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जो सरकार द्वारा चलाई गईं, उनका लाभ ऐसे ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा. सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसी दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां भूखे लोगों की संख्या पहली बार एक अरब से ज़्यादा हो गई है. संस्था के प्रतिनिधियों का कहना है कि दुनिया के एक अरब भूखे लोगों में हर चौथा व्यक्ति भारत का नागरिक है. उन्होंने कहा कि यह हक़ीक़त किसी को भी विचलित कर देने के लिए काफ़ी है. बावजूद इसके सरकारें इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही हैं. देश में पांच साल से कम उम्र के क़रीब 40 प्रतिशत बच्चों का वज़न सामान्य से कम है और 48 प्रतिशत बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, जिनका समुचित विकास मां के गर्भ में नहीं हो पाता. अब ऐसे में हम विकास की बात कैसे कर सकते हैं.

आदिवासी अल्पायु होते हैं

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के कई देशों में रहने वाली आदिम प्रजातियों के लोगों की आयु शेष जनसंख्या से कहीं कम होती है यानी वे दूसरों की तुलना में कम जीते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने अपने इतिहास में पहली बार आदिम प्रजातियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है. ये ऐसी जातियां हैं, जो किसी भी देश के ज्ञात इतिहास में सबसे पुराने समय से रह रही हैं. इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में कुछ डराने वाले आंकड़े प्रकाश में आए हैं. आस्ट्रेलिया की आदिम प्रजाति और नेपाल में पाई जाने वाली किराती मूल प्रजाति के लोगों की औसत आयु अपने ही देश की दूसरी जनसंख्या से 20 वर्ष कम है, जबकि कनाडा में रह रही फर्स्ट नेशन, इनुइत और मेतिस प्रजातियों का अनुमानित जीवनकाल अपने देशवासियों से लगभग 17 वर्ष कम है. संयुक्त राष्ट्र ने आदिम प्रजातियों और दूसरे देशवासियों के बीच मौजूद अमीरों और ग़रीबों के बीच की खाई को इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है.

रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हालांकि आदिम प्रजातियां दुनिया की पूरी आबादी का मात्र पांच प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन वे गांवों में बसने वाली दुनिया की बेहद ग़रीब आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं. औसत आयु कम होने के साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाली इन आदिम प्रजातियों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बनी रहती हैं. संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट के ज़रिए आदिम प्रजातियों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा की भी निंदा की है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
वाणी पर नियंत्रण बनाएं रखें. व्यवसायिक मामलों में वास्तविकता को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. इस सप्ताह आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ उतार–चढ़ाव महसूस करेंगे. किसी परिवारीजन का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है. ईश्वर पर भरोसा रखें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आपको काफ़ी बुद्धिमानी से काम लेना होगा. आपके नए प्रोजेक्ट परिणाम देने में कुछ और समय लेंगे. यात्रा के दौरान कोई महिला चिंता का कारण बन सकती है. हो सके तो यात्रा को स्थगित कर दें, यही बेहतर होगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आपका मन जिस बात के लिए तैयार नहीं है, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होगा. किसी महिला की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आप प्रॉपर्टी ख़रीदने की योजना बना सकते हैं. जिनसे आप प्यार करते हैं, वे इस बात से बहुत ख़ुश होंगे. पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन में आपकी क्षमता बढ़ेगी, व्यवसाय में भी अच्छा फ़ायदा होगा. ईमानदारी और मेहनत आपके मूलमंत्र हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
नफ़ा–नुक़सान की परवाह किए बिना आप अपने काम पर यथोचित ध्यान देंगे. बच्चों एवं रिश्तेदारों पर ख़र्चे बढ़ेंगे. विश्वास ही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है. पारिवारिक आयोजन आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे. यात्रा के दौरान सावधानी अपेक्षित है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. सेहत के प्रति लापरवाही समस्याएं पैदा कर सकती हैं. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
अपने भीतर की आवाज़ सुनें, इससे आप अपना लक्ष्य जल्दी पूरा कर पाएंगे. यात्रा पर ख़र्च बढ़ेगा. छुट्टियां बिताना मज़ेदार साबित होगा. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, मगर नहीं आ पा रहे हैं. इस सप्ताह आपकी यह समस्या हल हो जाएगी. परिवार का कोई सदस्य आपकी सहायता करेगा. कार्यक्षेत्र का माहौल पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. पेट संबंधी कोई बीमारी आपको तकलीफ़ दे सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे. यात्रा आपके तनाव को कम करेगी. ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास बनाए रखें, सफलता के रास्ते आसान होते जाएंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति सुधरेगी. अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई निराशा भी हाथ लग सकती है. परिवार से ख़ुशी और सहयोग की प्राप्ति होगी. वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना होने की आशंका है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहें. यात्रा सामान्य रहेगी. दूसरों को कटु वचन मत बोलें, इससे आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर ख़र्चे बढ़ेंगे. नए स्थानों की यात्रा सफल रहेगी. परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत होगी. कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है. मेहनत से पीछे न हटें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

सामंती मानसिकता के कई रूप समाज में परवान चढ़ चुके हैं. एक घूसघोर घूस देने वाले के साथ विनम्रता से पेश आता है, यह भी सामंती मानसिकता का एक रूप है.

पाकिस्तान

सामंतवादी तंत्र की हक़ीक़त

महमूद अयाज़

फ्यूडलिज्म या सामंतवादी तंत्र एक सोच का नाम है. एक ऐसे व्यक्ति की सोच, जो दूसरों को अपने मुक़ाबले तुच्छ मानता हो और उनका हक़ छीनना जायज़ समझता हो. ऐसी नकारात्मक सोच और चिंता रखने वाले वर्ग सामंतवादी तंत्र को जन्म देते हैं. यह तंत्र अमीरों को कमज़ोरों के शोषण का गुण सिखाता है, नाजायज़ तरीक़े से दौलत जमा करता है, ग़रीब को और ग़रीब बनाता है, अमीर को और अमीर बनाता है. लिहाज़ा कोई व्यक्ति या वर्ग जो ऐसी सोच का पक्षधर हो, वह सामंतों की श्रेणी में आता है. इतिहासकार लिखते हैं कि सामंतवाद की परिभाषा 15वीं शताब्दी में प्रकाश में आई. अंग्रेज़ों के सत्ता में आने के बाद भारत की कृषि व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए, नतीजतन, सामंतों ने जन्म लिया. ब्रिटिश सरकार ने छोटे राजाओं, नवाबों और सरदारों को सामंतों में तब्दील कर दिया. ऐसे लोगों भी जागीरें दी गईं, जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार को स्थिर बनाने का काम किया.

पाकिस्तान के इतिहास का निष्पक्षता से अध्ययन किया जाए तो यह बात सामने आती है कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोकेसी आधारित प्रतिष्ठान ने हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के जागीरदारों–सरदारों का बचाव किया. उत्तरी पाकिस्तान में सामंती तंत्र नहीं था और न वहां के लोग इस मानसिकता के थे. पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही पश्चिमी पाकिस्तान के फ्यूडल लॉर्ड्ज, जो सियासी रसूख रखते थे, को आशंका हो गई कि अगर संविधान तत्काल बना दिया गया तो बंगाली सत्ता में आ जाएंगे और सामंती तंत्र खत्म हो जाएगा. लिहाज़ा संविधान बनाने में विलंब किया गया और 1956 में जो संविधान बनाया गया, उसमें जानबूझ कर बंगालियों को नज़रअंदाज़ किया गया. एक अजीब बात यह भी है कि उत्तरी पाकिस्तान ने 50 के दशक में सामंती तंत्र को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था. परिणामस्वरूप वहां लोकतंत्र विकसित हुआ और लोकतांत्रिक सभ्यता विस्तार पकड़ने लगी. यह एक ऐतिहासिक सच है कि अगर संविधान आरंभिक दौर में बन जाता तो केंद्र में उत्तरी पाकिस्तान की सरकार होती. अगर बंगाली प्रधानमंत्री अपनी बाहुल्यता के बल पर पाकिस्तान में सरकार चला रहे होते तो सामंती तंत्र का ख़ात्मा कर देते और सिविल ब्यूरोक्रेसी और सेना सत्ता में न आती, सोवियत संघ के विरुद्ध शीतयुद्ध में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान फ्रंट स्टेट न बनता. इतिहास बताता है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने सामंतों के साथ मिलकर उत्तरी पाकिस्तान के बहुमत को अल्पमत में तब्दील किया, लियाक़त अली ख़ां को शहीद करा दिया गया. शुरुआती 10 सालों में 7 प्रधानमंत्री बदले गए, ताकि पाकिस्तान के विकास पर रोक लगा दी जाए और इन सबके पीछे फ्यूडल मानसिकता वाले लोगों का हाथ था.

उत्तरी पाकिस्तान में सामंती तंत्र नहीं था और न वहां के लोग इस मानसिकता के थे. पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही पश्चिमी पाकिस्तान के फ्यूडल लॉर्ड्ज, जो सियासी रसूख रखते थे, को आशंका हो गई कि अगर संविधान तत्काल बना दिया गया तो बंगाली सत्ता में आ जाएंगे और सामंती तंत्र खत्म हो जाएगा. लिहाज़ा संविधान बनाने में विलंब किया गया और 1956 में जो संविधान बनाया गया, उसमें जानबूझ कर बंगालियों को नज़रअंदाज किया गया. एक अजीब बात यह भी है कि उत्तरी पाकिस्तान ने 50 के दशक में सामंती तंत्र को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था. परिणामस्वरूप वहां लोकतंत्र विकसित हुआ और लोकतांत्रिक सभ्यता विस्तार पकड़ने लगी.

ऐसे लोगों ने शुरुआती कुछ सालों में ही पाकिस्तान की राजनीति पर हावी होना शुरू कर दिया. इस वर्ग ने देश की बहुमत आबादी यानी बंगालियों को (जो उस समय पाकिस्तान की कुल आबादी की 56 प्रतिशत थी, जिसने उत्तरी पाकिस्तान में 319 सीटों में से 313 सीटें जीतकर मुस्लिम लीग का नामोनिशान मिटा दिया था) राजनीति से बेदख़ल कर दिया. सामंती मानसिकता रखने वाले हमेशा से सत्ता के मज़े लूटते आए हैं. सीनेट और राज्य विधानसभा जैसी संस्थाओं में फ्यूडल मानसिकता वाले लोग क़ानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं. मेरिट का उल्लंघन होता रहा, बड़े असामियों तक ग़रीब तबके की पहुंच असंभव हो गई. इतिहास बताता है कि सरकार हमेशा दो वर्गों में बंटी रही, एक तरफ़ सेना और दूसरी ओर सामंती एवं पूंजीपति वर्ग. कोई तीसरा आज तक पाकिस्तान की सत्ता में नहीं आ सका और जनता भी इन्हीं को आंखें बंदकर वोट देती रही. यह वर्ग हर शासनकाल में जनता का शोषण करता आया है और इसका शिकार मज़दूर वर्ग रहा. जागीरदारों के अत्याचार से बचने के लिए मज़दूरों ने शहर का रुख़ किया, जहां वे पूंजीपतियों के हत्थे चढ़ गए. जब एक जागीरदार सत्ता में होता है तो वह कारख़ाने बंद करने के हथकंडे इस्तेमाल करता है, ताकि जो मज़दूर उसके हाथों से निकल गए थे, वे वापस आकर फिर से उसकी ज़मीनें आबाद करें. जबसे पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, देश का ग़रीब और मध्य वर्ग इसी चक्कर में फंसा हुआ है.

देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और ग़रीबी के कारणों पर ध्यान दें तो उनकी जड़ें वडेरा कल्चर और सामंतवाद से जा मिलेंगी. कौन नहीं जानता कि अमेरिकी डॉलरों के बदले अनगिनत बेगुनाहों की बलि दी जा चुकी है. जागीरदार भ्रष्टाचार को अपना हक़ समझता है. (एक निर्वाचित विधायक ने पिछले दिनों टीवी पर बातचीत करते हुए कहा था) शुरू से लेकर आज तक क्षेत्रीय अधिकारों और स्वायत्तता को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की गई, नतीजतन, उत्तरी पाकिस्तान अलग हो गया. आज ब्लूचिस्तान में भी बग़ावत की वही स्थिति पाई जाती है. सामंती तंत्र की परंपरा, रस्म, रिवाज और नैतिकता को धर्म का चोला पहना कर इस तरह पवित्र बना दिया जाता है कि कोई इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता. यह व्यवस्था पूरी दुनिया से खत्म हो गई, मगर दुर्भाग्य से पाकिस्तान में मौजूद है. ख़ासकर दो राज्यों पख्तूनख्वा और ब्लूचिस्तान में यह न केवल मौजूद है, बल्कि इतनी स्थिर भी कि ख़ुद इन राज्यों की शिक्षित–अशिक्षित जनता इसकी संरक्षक बनी बैठी है. हम अपने समाज से आज तक जागीरदारी ख़त्म नहीं कर सके. सामंती मानसिकता के कई रूप समाज में परवान चढ़ चुके हैं. एक घूसघोर घूस देने वाले के साथ विनम्रता से पेश आता है, यह भी सामंती मानसिकता का एक रूप है. अगर किसी अधिकारी के कार्यालय में आप दाख़िल हों तो वहां का क्लर्क आपके सलाम का जवाब नहीं देता, पूछताछ करने वाले खड़े–खड़े थक जाते हैं, यह भी सामंती मानसिकता है. अधिकारी जब अपने परिवारीजनों से बात करता है तो उसका अंदाज अलग होता है और जब नौकरों से मुख़ातिब होता है तो उसके स्वरों में तल्ख़ी आ जाती है. यह भी सामंतवाद है. हालांकि ये सब जागीरदार नहीं हैं, लेकिन इनके अंदाज़ में सामंतवादी सोच घर कर चुकी है. अफसोस की बात यह है कि हम विदेशी समाज को बुरा–भला कहते हैं और हमें अपने समाज के नासूर का पता नहीं है. सामंती तंत्र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह हावी है. देश की 60 प्रतिशत कृषि आबादी डवेरों और जागीरदारों की गुलाम है. जागीरदार इस 60 प्रतिशत आबादी से वोट लेता है और सत्ता के मज़े लूटता है और दूसरी तरफ वह कृषि यानी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के बलबूते पूंजी जमा करता है. यही वजह है कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन के रास्ते पर है. पाकिस्तान में दो बार कृषि सुधार लागू हुए. एक बार जनरल अय्यूब और दूसरी बार ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो ने लागू किए, मगर कोई नतीजा नहीं निकला. इसकी वजह ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों का गठजोड़ था. इसका एक नुक़सान यह हुआ कि सेंट्रल पंजाब में छोटे ज़मींदारों का जाल बिछ गया और सिंध में भी बड़े जागीरदारों के साथ–साथ छोटे ज़मींदार मज़बूत होते चले गए. 1947 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि पर रखी गई. उस समय औद्योगिक ढांचे का अस्तित्व न के बराबर था और राजनीतिक संस्थाओं पर जागीरदार छाए हुए थे. नतीजतन हमें राष्ट्रीय विकास, समृद्धि और संस्थाओं की स्थिरता में नाकामी का सामना करना पड़ा और अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई. इस वर्ग ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान के कृषि ढांचे का शिकार किया, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा. एक ऐसा देश जहां कृषि से जुड़े पांच में से चार लोग सिरे से ही भूमिहीन हों, जहां ज़मीन पर पसीना बहाने वाले मजदूरों को उनकी निजी संपत्ति से वंचित रखा जाए, जहां लोकतंत्र का दावा करने वाले लाखों एकड़ ज़मीनों के मालिक बन बैठे हों, वहां की अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं. आज तो सामंती वर्ग उद्योगपति बन चुका है. बड़ी–बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां उनके स्वामित्व में हैं. सरकारी संपत्तियों को फॉर्म हाउस की शक्ल दे दी गई है, जहां बड़े–बड़े अधिकारी और राजनीतिज्ञ ऐश की जिंदगी गुज़ार रहे हैं. सामंती वर्ग की वजह से देश की हुनरमंद और शिक्षित आबादी विदेश पलायन कर गई है. रही–सही कसर आतंकवाद की तथाकथित जंग ने पूरी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान अब तक अरबों रुपये गंवा चुका है. इस जंग से जागीरदारों और राजनीतिज्ञों के अलावा किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

इस जंग में देश को 2009–10 में सकल उत्पादन के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर नुक़सान पहुंचा और पिछले आठ सालों में लगभग 9 हज़ार पाकिस्तानी इसकी भेंट चढ़ चुके हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2001–10 के बीच आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को 43 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा का नुक़सान हुआ. 2007–08 में आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयों से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा. सामंती तंत्र और सामंती मानसिकता रखने वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें कृषि संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन करना होगा. कृषि सुधारों के बग़ैर पाकिस्तान की क़िस्मत में कोई अर्थपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है. अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीति की बर्बादी और समाज के पिछड़ेपन का ख़ात्मा सिर्फ़ तभी संभव है, जबकि भूमि सुधारों के अमल को संभव बनाया जाए, ताकि यह देश सामंती और डवेरा तंत्र से छुटकारा पा सके.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

चातुर्य त्याग कर सदैव साई-साई स्मरण करो. इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 18 जुलाई-24 जुलाई 2011

साई का सानिध्य

ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं. इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में लाओ. यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण, वरन स्त्रियां और अन्य दलित जातियां भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी. सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो. तब तो निश्चित है कि वह कृपा अवश्य करेंगे.

शिरडी में नानावल्ली नामक एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था. वह बाबा के सभी कार्यों की देखभाल किया करता था. एक दिन जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा. वह स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था. इसलिए उसने बाबा से वहां से हटने को कहा. बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और नानावल्ली वहां विराजमान हो गया. कुछ समय वहां बैठकर वह उठा और उसने बाबा से अपना स्थान ग्रहण करने को कहा. बाबा पुनः आसन पर बैठ गए. यह देखकर नानावल्ली उनके चरणों पर गिर पड़ा और फिर भाग गया. इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र अप्रसन्नता की झलक नहीं थी.

यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी. उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे. उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूंका. उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई-साई स्मरण करो. इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. पंचामि, तप, त्याग, स्मरण और अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं. मन का कार्य विचार करना है. बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता. यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा. आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता का श्रवण कर चुके हैं. यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साई का कीर्तन है. संतों की कथा का स्मरण उतना कठिन नहीं, जितना कि अन्य साधनाओं का, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है.

ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं. इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में लाओ. यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण, वरन स्त्रियां और अन्य दलित जातियां भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी. सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो. तब तो निश्चित है कि वह कृपा अवश्य करेंगे. यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि हर कोई इसका अवलंबन नहीं करता. कारण केवल यह है कि ईश कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती. ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है. संतों की कथा का श्रवण संत समागम सदृश है. संत सानिध्य का महत्व अति महान है. इससे अहंकार और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य स्वरूप है. विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है, दुःखों एवं सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है. यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि प्रयोग नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भवसागर के उस पार उतार देंगे.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

इसी कार्य के निमित्त संत विश्व में प्रगट होते हैं. पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे. ऐसा संतों का प्रभाव है. गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरुप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है. उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है. मस्जिद के किनारे पर खड़े होकर वह भक्तों के कल्याणार्थ उदी का वितरण करते थे. जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे, ऐसे सच्चिदानंद श्री साई महाराज के चरणों को बार-बार नमस्कार है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरुष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

गौरैया के घोंसले घरों के सुराख़ों में, चट्टानों में, नदी के किनारे, झाड़ियों में, आलों में या प्रवेश द्वारों पर होते हैं, जो घास के तिनकों से बने होते हैं और उनमें पंख भरे होते हैं.

अनंत विजय

निज भाषा पर अभिमान करो

हिंदी में प्रकाशित किसी भी कृति–उपन्यास या कहानी संग्रह या फिर कविता संग्रह को लेकर हिंदी जगत में उस तरह का उत्साह नहीं बन पाता है, जिस तरह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बनता है. क्या हम हिंदी वाले अपने लेखकों को या फिर उनकी कृतियों को लेकर उत्साहित नहीं हो पाते हैं. हिंदी में प्रकाशक पाठकों की कमी का रोना रोते हैं, जबकि पाठकों की शिकायत किताबों की उपलब्धता को लेकर रहती है. यह स्थिति पहले मुर्ग़ी या पहले अंडा जैसी है, लेकिन इसमें हम हिंदी वालों का नुक़सान हो रहा है. अपनी भाषा को लेकर जिस तरह का गर्व हमारे मन में होना चाहिए या फिर जिस तरह का लगाव दिखना चाहिए, उसका नितांत अभाव दिखाई देता है. दरअसल, इसके लिए हिंदी के लेखक भी कम ज़िम्मेदार नहीं हैं. हिंदी के लेखकों में एक–दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, उससे उनका बड़ा नुक़सान हो रहा है. इस स्थिति से उबरने के लिए हिंदी के लेखक, उनके तीन संगठन और ज़ाहिर सी बात है कि प्रकाशक भी कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं.

अब हम अंग्रेजी को देखें. हाल ही में अंग्रेजी के भारतीय लेखक अमिताभ घोष की महत्वाकांक्षी ट्रायोलॉजी के तहत लिखा गया दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ. कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाज़े जा चुके अमिताभ घोष के उपन्यास रिवर ऑफ स्मोक के प्रकाशित होने के पहले और बाद में हमारे देश के अंग्रेजी अख़बारों ने एक ऐसा माहौल बनाया, लगा कि जैसे साहित्यिक जगत में कोई विशेष घटना घटी हो. अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय अख़बारों ने आधे पन्ने पर अमिताभ घोष के इंटरव्यू छापे. अख़बारों के रविवारीय परिशिष्ट में लेखक पर कवर स्टोरी प्रकाशित हुई. बात यहीं तक नहीं रुकी. उपन्यास के प्रमोशन के लिए लेखक का वर्ल्ड टूर आयोजित किया गया. ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ़ अमिताभ घोष के लिए ही किया गया. यह अंग्रेजी प्रकाशन जगत के लिए सामान्य सी बात है. कोई भी उपन्यास या अहम कृति प्रकाशित होती है तो उसे लेकर योजनाबद्ध तरीक़े से एक समन्वित प्रयास किया जाता है. इस प्रयास में अंग्रेजी के अख़बार भी सहयोग करते हैं. अमिताभ घोष या फिर अन्य अंग्रेजी लेखकों को जिस तरह उनकी कृति के बहाने प्रचारित किया जा रहा है या जाता रहा है, उससे हिंदी समाज को सीख लेनी चाहिए. लेकिन बजाय उनसे सीख लेने के हम अपनी जड़ता को लेकर ही बैठे रहते हैं.

हमें तो यह याद नहीं पड़ता कि हिंदी के किसी लेखक को उसकी कृति के प्रकाशन के बाद इतना प्रचार मिला हो. चाहे वह हमारे स्टार लेखक राजेंद्र यादव हों, कमलेश्वर हों, निर्मल वर्मा हों या फिर आज की पीढ़ी का कोई नया लेखक हो. सवाल प्रचार का नहीं है, एक समन्वित प्रयास का है. क्या हिंदी के प्रकाशकों ने कभी अपने लेखकों को प्रचारित करने, उनकी कृति को प्रमोट करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया? मैं तो बहुत नज़दीक से हिंदी प्रकाशन को तक़रीबन डेढ़ दशक से देख रहा हूं, इस तरह का कोई प्रयास मुझे नज़र नहीं आया. मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले में हिंदी प्रकाशन जगत की स्थिति बेहद दयनीय है. हिंदी का इतना विशाल पाठक वर्ग है, सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी पट्टी में अपने बाज़ार का विस्तार कर रही हैं,

लेकिन हमारे हिंदी के प्रकाशक अब भी सरकारी ख़रीद के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें हिंदी के पाठकों पर भरोसा नहीं है. हिंदी के प्रकाशक किताबों के प्रचार–प्रसार पर ख़र्च नहीं करना चाहते. किसी लेखक की विदेश यात्रा की बात तो दूर, हिंदी पट्टी में भी पाठकों से संवाद का कार्यक्रम आयोजित नहीं कराया जाता. हमारे प्रकाशक किताब का विमोचन (वह भी लेखकों के साझा प्रयास से) कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं. कई बार तो लेखकों को विमोचन पर आए ख़र्च को भी साझा करना पड़ता है. उसके पीछे यह मनोविज्ञान काम करता है कि यह सब फ़िज़ूलख़र्ची है. जबकि प्रकाशकों को यह समझना चाहिए कि यह एक लंबी अवधि का निवेश है, जिसमें जमकर रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए हिंदी के प्रकाशकों को तात्कालिक लाभ का मोह छोड़ना होगा. हिंदी के पाठकों के बीच एक संस्कार विकसित करने की दिशा में प्रयास करना होगा. इसके लिए हमें अपने लेखकों को उनके बीच लेकर जाना होगा. ऐसा नहीं है कि हमारे प्रकाशकों के पास पैसे की कमी है, लेकिन उसे ख़र्च करने की इच्छाशक्ति का अभाव ज़रूर है.

दरअसल, अंग्रेजी और हिंदी के प्रकाशकों में एक बुनियादी फ़र्क़ है. अंग्रेजी के प्रकाशक भविष्य की योजना बनाकर काम करते हैं, जबकि हिंदी के प्रकाशकों की कोई भी फॉर्वर्ड प्लानिंग नहीं होती. उदाहरण के तौर पर आपका बताऊं कि जब 1857 की क्रांति के डेढ़ सौ साल पूरे हो रहे थे तो अंग्रेजी के प्रकाशकों ने धड़ाधड़ कई किताबें छापीं, लेकिन हिंदी प्रदेश में हुई इस घटना से हिंदी के प्रकाशक उदासीन रहे. कोई भी बड़ी घटना या फिर अहम तिथि आती है तो अंग्रेजी में धड़ाधड़ किताबें आ जाती हैं. देश में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ तो अंग्रेजी में कई किताबें आईं, लेकिन हिंदी में ऐसे इक्का–दुक्का प्रयास ही देखने को मिले. अंग्रेजी और हिंदी प्रकाशन में इस तरह के अंतर के कई उदाहरण मौजूद हैं. अंग्रेजी प्रकाशकों का तंत्र बेहद मज़बूत और प्रोफेशनल है, जबकि हिंदी का प्रकाशन व्यवसाय अब भी पारिवारिक कारोबार है. किसी भी हिंदी प्रकाशन गृह में प्रोफेशनलिज्म का घोर अभाव है. प्रोफेशनल काम करने वाले लोग किसी भी हिंदी प्रकाशन गृह में लंबे समय तक टिक नहीं सकते. अंग्रेजी के मुक़ाबले में हिंदी का प्रचार–प्रसार तंत्र बेहद लचर है. अंग्रेजी प्रकाशन गृह में एक सूची होती है, जिसमें वैसे चुनिंदा लोग होते हैं, जिन्हें किताब छपने से पहले ही उसके अंश और बाज़ार में किताब आने के पहले उन्हें किताब मुहैया करा दी जाती है. पाठकों में रुचि जगाने के लिए किताब के चुनिंदा अंश लीक कराकर पाठकों के मन में जिज्ञासा पैदा कराई जाती है. इसके दो बेहतरीन उदाहरण हैं, एक तो टोनी ब्लेयर की आत्मकथा–अ जर्नी और दूसरा जोसेफ लेलीवेल्ड की किताब–द ग्रेट सोल. ब्लेयर और उनकी पत्नी के पूर्व प्रकाशित सेक्स प्रसंग और गांधी और कैलनबाख के संबंधों को सनसनीख़ेज़ तरीक़े से प्रचारित किया गया, जैसे कोई नया ख़ुलासा हो, जबकि दोनों प्रसंग पहले से ही ज्ञात थे. नतीजा यह हुआ कि किताब आने के पहले ही उसका एक बाज़ार तैयार हो गया. प्रकाशकों को भी लाभ हुआ और लेखकों को भी रॉयल्टी में लाखों रुपये मिले. मैं अपने देश के भी दो–तीन अंग्रेजी लेखकों को जानता हूं, जिन्हें उनकी किताब पर लाखों रुपये की रॉयल्टी मिली. लेकिन हिंदी के शीर्ष लेखकों को भी साल में एक कृति पर लाख रुपये की रॉयल्टी मिलती हो, उसमें मुझे संदेह है. जबकि हिंदी में समीक्षकों को किताबें देने में (कुछ अपवाद को छोड़कर) अधिकतर प्रकाशक आनाकानी करते हैं.

अब वक़्त आ गया है कि हिंदी के प्रकाशक अपनी संकुचित मानसिकता से उठकर विचार करें और एकल या सामूहिक रूप से लेखकों और उनकी कृतियों को पाठकों के बीच ले जाने का प्रयास करें. कृतियों को प्रचारित या प्रसारित करने के लिए एक प्रोफेशनल तंत्र का विकास करें. हिंदी के अग्रणी प्रकाशन गृह होने की वजह से राजकमल और वाणी प्रकाशन समूह की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे इसमें पहल करें. ऐसा करने से उनका और लेखकों यानी दोनों का भला होना निश्चित है. सिर्फ़ प्रकाशकों की नहीं, हिंदी मीडिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने लेखकों को उचित सम्मान और स्थान दें.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

लौट आओ गौरैया

कभी सर्वत्र दिखाई देने वाली, हमारे घर–आंगन में फुदकती प्यारी सी चिड़िया गौरैया (स्पैरो) आज एक संकटग्रस्त पक्षी है, जो पूरे विश्व में तेज़ी से दुर्लभ हो रही है. एक–दो दशकों पहले तक गौरैया के झुंड हमारे घरों, सार्वजनिक स्थलों, खिड़कियों, चबूतरों, यहां तक कि कमरों के अंदर भी देखे जा सकते थे. उसका फुदकना और चहचहाना हर किसी का मन मोह लेता, उसको दाना चुगते देखना अच्छा लगता. हमारे बचपन की बहुत सी यादें इस नन्हीं सी चिड़ियों की अठखेलियों से जुड़ी होंगी. घरेलू गौरैया एक बुद्धिमान चिड़िया है, जिसने अपने को आश्रय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया. यही कारण रहा कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चहचहाती चिड़िया बन गई थी, परंतु आज यह संकट में है. इसकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है और निकट भविष्य में इसके विलुप्त होने का ख़तरा है. भारत ही नहीं, यूरोप के बड़े हिस्सों में कभी सामान्य रूप से दिखाई देने वाली गौरैया अब काफ़ी कम रह गई हैं. नीदरलैंड में तो घरेलू गौरैया को दुर्लभ प्रजाति के वर्ग में रखा है. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, फिनलैंड और बेल्जियम में भी इसकी संख्या तेज़ी से गिरी है.

भारत में गौरैया के कई नाम हैं, जैसे गौरा और चटक. तमिलनाडु और केरल में यह कूरूवी नाम से जानी जाती है, जबकि जम्मू–कश्मीर में इसे चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी और उड़ीसा में घरचटिया कहते हैं. तेलुगु में इसे पिच्चूका, कन्नड़ में गुब्बाच्ची, गुजराती में चकली, मराठी में चिमानी, पंजाबी में चिड़ी,

उर्दू में चिड़िया और सिंधी में झिरकी कहा जाता है. घरेलू गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है. कुछ लोग इसे वीवर फिंच परिवार से संबंधित मानते हैं. नर गौरैया को सीने के रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है. इसकी लंबाई 14 से 16 सेमी होती है. इसके पंखों का फैलाव 19 से 25 सेमी तक होता है. इसका भार केवल 26 से 32 ग्राम होता है. नर गौरैया का सिर, गाल और अंदर का भाग धूसर होता है तथा सीने के ऊपर, गला, चोंच एवं आंखों के बीच का भाग काला होता है. गर्मी में गौरैया की चोंच का रंग नीला–काला और पैर का रंग भूरा हो जाता है. सर्दी में इसकी चोंच का रंग पीला–भूरा हो जाता है. एक प्रजनन अवधि में इसके कम से कम तीन बच्चे होते हैं. इनके अंडे अलग–अलग आकार के होते हैं. अंडों को सेहने का काम मादा गौरैया के ज़िम्मे होता है. गौरैया 10–12 दिनों तक अंडे सेहती है. गौरैया की प्रजनन सफलता उम्र बढ़ने के साथ–साथ बढ़ती जाती है.

गौरैया के घोंसले घरों के सुराख़ों में, चट्टानों में, नदी के किनारे, झाड़ियों में, आलों में या प्रवेश द्वारों पर होते हैं, जो घास के तिनकों से बने होते हैं और उनमें पंख भरे होते हैं. ये मानव निर्मित स्थलों, दरारों और बग़ीचों में भी अपना घोंसला बनाती हैं. कभी–कभी घरेलू गौरैया अन्य चिड़ियों के घोंसले भी हड़प लेती है और उनके द्वारा बनाए गए घोंसलों के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है. गौरैया सामाजिक पक्षी है, अधिकतर झुंड में उड़ती है. एक झुंड 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है. भोजन तलाशने के लिए यह अधिक दूरी भी तय करती है. गौरैया दिन भर भोजन जुटाने में लगी रहती है. इसका प्रमुख आहार अनाज के दाने हैं. यह अन्य आहार से भी अपना पेट भर लेती है. घरेलू गौरैया परजीवी पद्धति वाली होती है. यह घरों से बाहर फेंके गए कूड़े–करकट में से अपना आहार ढूंढ लेती है. आधुनिक युग में रहन–सहन और वातावरण में आए बदलावों के कारण आज गौरैया पर कई ख़तरे मंडरा रहे हैं. सबसे प्रमुख ख़तरा उसके आवास स्थलों का उजड़ना है. आज हमारे घरों में आंगन होते ही कहां हैं, फिर बेचारी गौरैया घोंसला बनाए कहां? आधुनिक युग में पक्के मकानों की बढ़ती संख्या एवं लुप्त होते बाग़–बग़ीचे भी उसके आवास स्थल को छीन रहे हैं. इसके अलावा भोजन की कमी भी गौरैया के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है. गौरैया प्राय: दाना खाती है, लेकिन उसके बच्चों को प्रोटीन के लिए नन्हें कीड़े चाहिए, जिन्हें मां गौरैया ढूंढकर लाती है और उनके मुंह में अपनी चोंच से डालती है. शहरों में आवास बढ़ने और हरियाली की कमी के कारण चिड़ियों को कीड़े–मकोड़े भी आसानी से नहीं मिल पाते. अब घर की छत पर दालें भी नहीं सुखाई जातीं. कई अन्य मानवीय गतिविधियां भी गौरैया के अस्तित्व को चुनौती दे रही हैं, जैसे मोबाइल फोन के टॉवर से निकलने वाली रेडियो तरंगें. इनसे भोजन की तलाश में निकली गौरैया की सोचने–समझने की क्षमता कम हो जाती है और वह रास्ता भटक जाती है. रेडियो तरंगों के प्रभाव से अंडों के बाह्य आवरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण का भी असर गौरैया पर पड़ रहा है. सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने पर उसके दहन से मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक बनता है, जो गौरैया जैसे छोटे जंतुओं के लिए काफ़ी ज़हरीला साबित होता है. कभी गौरैया अपने फुदकने, दाने चुगने, गर्दन घुमाकर अपने आसपास के माहौल को देखते रहने की चौकन्नी प्रवृत्ति के कारण हमारा मन मोह लेती थी, लेकिन अब यह प्यारी सी चिड़िया हमारी गतिविधियों के चलते हमसे दूर होती जा रही है.

सभी जीवों का अपना–अपना महत्व है. खाद्य शृंखला में गौरैया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इस जीव का संरक्षण आवश्यक हो गया है. वर्तमान में इसके संरक्षण को लेकर प्रयास हो रहे हैं. इसी भावना के अनुरूप पिछले साल से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है. गौरैया के अस्तित्व के लिए हम सभी को अपने–अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, ताकि यह प्यारा सा, नन्हा सा जीव फिर से हमारे घर–आंगन में चहक सके, हमारे जीवन से लुप्त न हो जाए. हम अपने घरों में उचित स्थानों पर पानी, बाजरा, टूटा चावल आदि रखकर अपना योगदान दे सकते हैं. (चरखा)

नवनीत कुमार गुप्ता
feedback@chauthiduniya.com

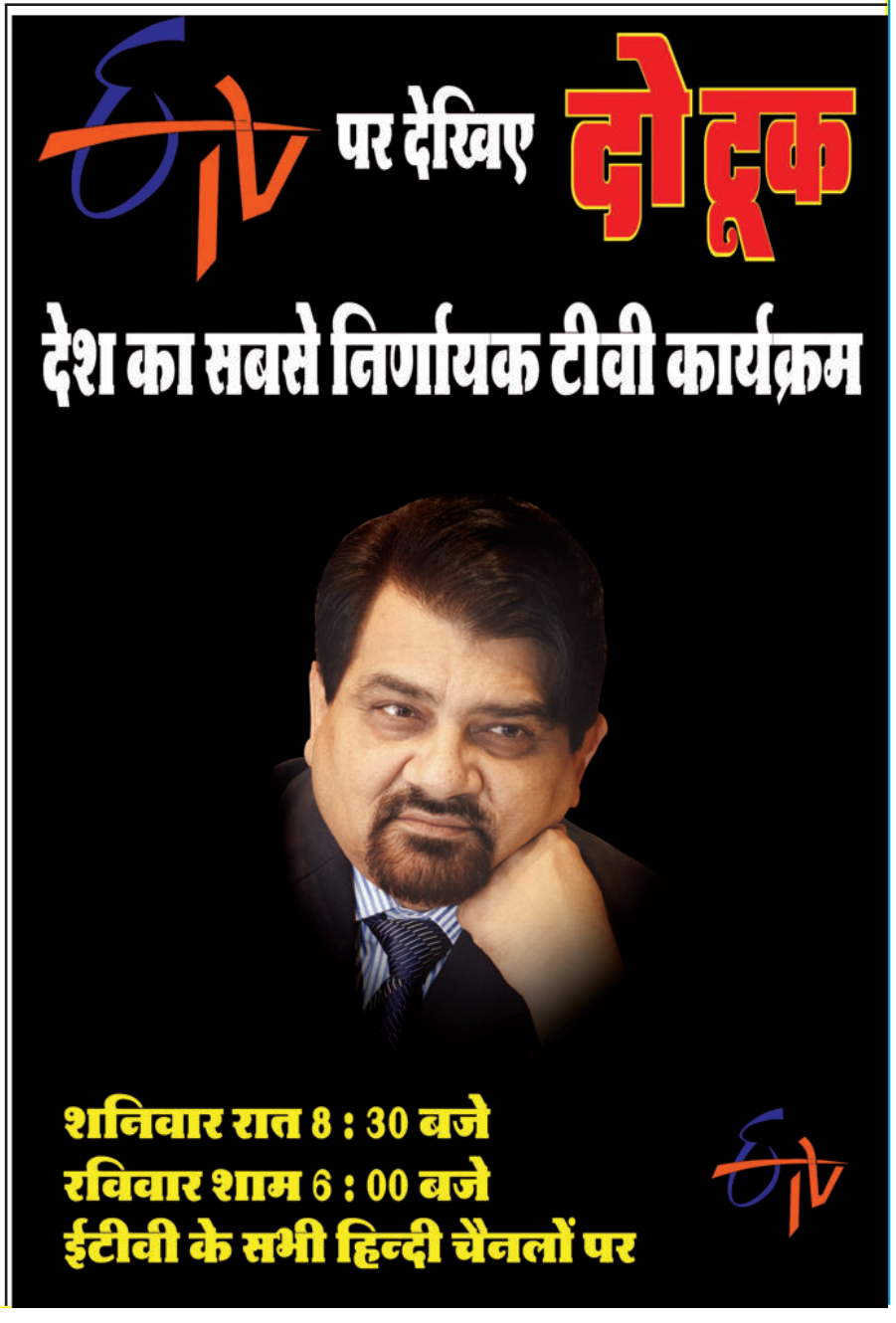

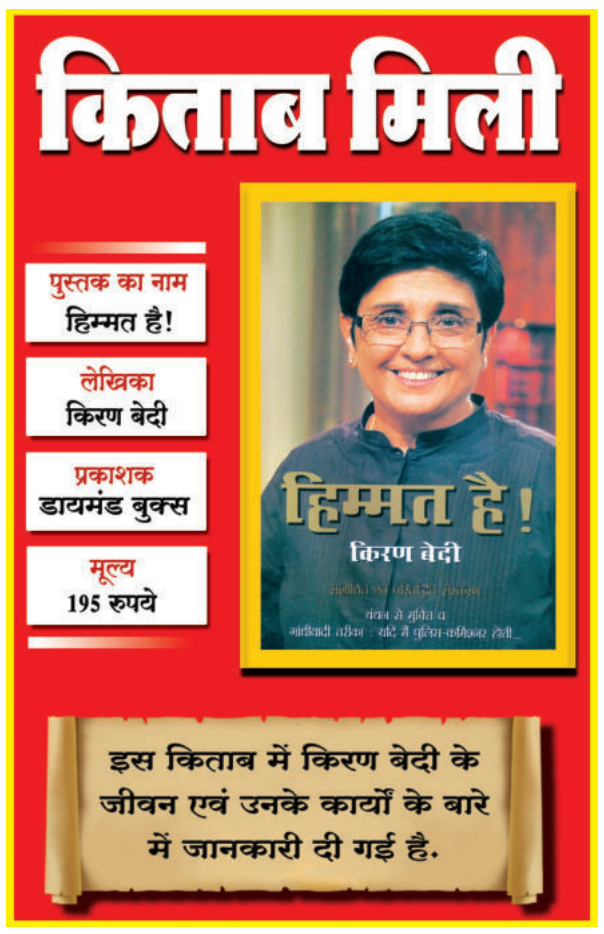

भारतीय सड़कों पर लीवा का कड़ा मुक़ाबला मारुति की स्विफ्ट, निसान माइक्रा, हुंदई आई-20 और फोक्स वैगन की पोलो से होगा.

भारतीय बाज़ार में बॉश एंड लॉम्ब

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत कंपनी बॉश एंड लॉम्ब ने हेल्थ केयर उत्पादों के क्षेत्र में अग्रणी माइक्रो लैब के सहयोग से भारत में फार्मास्युटिकल कारोबार शुरू करने की घोषणा की है. इस महत्वपूर्ण भागीदारी के चलते बॉश एंड लॉम्ब उन्नत उत्पादन क्षमताएं उपलब्ध कराएगी. परिणामस्वरूप आंखों की देखभाल के लिए नई प्रेस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दवाओं का वितरण किया जा सकेगा. माइक्रो लैब के साथ क़रार के चलते बॉश एंड लॉम्ब ने भारत के तेज़ी से बढ़ रहे ऑप्थेलमिक फार्मास्युटिकल्स मार्केट पर क़ब्ज़ा जमाने का लक्ष्य रखा है. इसीलिए कंपनी आंखों की देखभाल में सुधार लाने के लिए प्रेक्टिशनरी एवं पेशेंट एजुकेशन कार्यक्रमों का भी संचालन करेगी. इस मौक़े पर कंपनी के अध्यक्ष (एशिया) रॉडनी डब्ल्यू इंसवर्थ ने कहा कि भारत में आंखों की बीमारियों से त्रस्त क़रीब 76 फ़ीसदी मरीज़ इलाज नहीं करा पाते. बॉश एंड लॉम्ब को यक़ीन है कि यह समय यहां के बाजार में पैठ बनाने की दृष्टि से काफी उपयुक्त है और यह मरीज़ों को फायदा दिलाते हुए उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा. कंपनी इसके लिए उन्नत गुणवत्ता वाले ऐसे विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराएगी, जिनकी बदौलत लोग बेहतर ढंग से देखने के साथ-साथ बेहतर जीवन जी सकेंगे. इसके तहत मॉक्सीसर्ज, एक्वासर्ज, एक्वासर्ज मैक्स, ब्रॉमव्यू, केटोव्यू और मॉक्सीसर्ज-केटी समेत छह नए आई ड्रॉप्स बाजार में उतारे जाएंगे.

सहयोगी कंपनी माइक्रो लैब्स के निदेशक आनंद सुराना ने कहा कि आंखों की देखभाल के क्षेत्र में शक्तिशाली ब्रांड बॉश एंड लॉम्ब द्वारा भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार में प्रवेश के मौके पर उसके साथ भागीदारी इस बात का सबूत है कि यहां फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग काफी परिपक्व हो चुकी है और हमारे उत्पाद गुणवत्ता संबंधी कड़े वैश्विक मानकों का पालन करते हैं. बॉश एंड लॉम्ब ने भारत में अपने कॉन्टेक्ट लेंसों और सॉल्यूशन कारोबार के साथ 1992 में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था और 1996 में उसने आंखों की सर्जरी से संबंधित उत्पादों के क्षेत्र में कदम रखा. आज बॉश एंड लॉम्ब भारत में लेंस एवं सॉल्यूशन कारोबार में अग्रणी है और इस क्षेत्र में सर्जिकल ऑप्थेलमोलॉजी के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से है. बॉश एंड लॉम्ब इंडिया के प्रबंध निदेशक हरीश नटराजन ने कहा कि कंपनी भारत में आंखों की बेहतरीन देखभाल के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है और यह डॉक्टरों को बेहतर पेशकश का लाभ दिलाते हुए मदद कर रही है तथा तेज़ी से और गुणवत्ता के साथ ऐसा करने में माइक्रो लैब्स के साथ कंपनी का गठबंधन काफ़ी सहायक साबित होगा.

माइक्रो लैब के साथ क़रार के चलते बॉश एंड लॉम्ब ने भारत के तेजी से बढ़ रहे ऑप्थेलमिक फार्मास्युटिकल्स मार्केट पर क़ब्ज़ा जमाने का लक्ष्य रखा है. इसीलिए कंपनी आंखों की देखभाल में सुधार लाने के लिए प्रेक्टिशनरी एवं पेशेंट एजुकेशन कार्यक्रमों का भी संचालन करेगी.

हार्ड ड्राइव वाला टेबलेट कंप्यूटर

हार्ड ड्राइव वाले दुनिया के पहले टेबलेट कंप्यूटर के लिए सीगेट ने हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज पेश किया है. आर्कोस 9 और 10 इंच टेबलेट के लांच की घोषणा कर दी गई है. ये सीगेट की पतली हार्ड ड्राइव मोमेंटस थिन से लैस हैं. यह सुपर स्लिम 7 एमएम प्रोफाइल और तेज परफॉर्म करने वाला नोटबुक ड्राइव है. मोमेंटस थिन ड्राइव की परफॉर्मेंस और क्षमता आर्कोस जी-9 फैमिली के टेबलेट के लिहाज से बेजोड़ है. इसमें इंडस्ट्री का सबसे तेज ड्यूल कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा है और मोमेंटस थिन ड्राइव की ताकत तो है ही. इसमें 250 जीबी की कैपेसिटी है, जो किसी भी 32 जीबी के स्टैंडर्ड टेबलेट की तुलना में 8 गुना से भी ज्यादा है और वह भी बराबर कीमत पर. इस तरह आर्कोस जी-9 सबसे ज्यादा किफायती और अच्छी परफॉर्मेंस वाला ड्राइव बन जाता है. 8 इंच का आर्कोस 80 जी-9 और 10 इंच का आर्कोस 101 जी-9 सितंबर में उपलब्ध हो जाएगा. आर्कोस 80 जी-9 की अनुमानित कीमत 279 डॉलर है, जबकि 10 इंच का आर्कोस 101 जी-9 349 डॉलर में खरीदा जा सकेगा. 3.1 एंड्रॉयड पर चलने वाला आर्कोस टेबलेट 8 इंच के डिसप्ले में 1024/768 पिक्सल और 10 इंच के डिसप्ले में 1280/800 पिक्सल की क्वालिटी देता है. ये दोनों 250 जीबी हार्डडिस्क या 16 जीबी फ्लैश मेमोरी ड्राइव के साथ उपलब्ध हैं. ये टेबलेट 1.5 गीगाहर्ट्ज आर्म ड्यूल कोर ओएमएपी 4 प्रोसेसर के साथ आते हैं. सीगेट के चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर रॉकी पीमेंटल ने कहा, इस शक्तिशाली आर्कोस टेबलेट के लिए मोमेंटस थिन ड्राइव पेश कर सीगेट ने अपने ग्राहकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पाद और तकनीक मुहैया कराने का सिलसिला बरकरार रखा है. मोमेंटस थिन ड्राइव टेबलेट खरीदने वालों को विशाल स्टोरेज क्षमता और बेहतरीन प्रदर्शन की गारंटी देगा. यह नए आर्कोस उत्पाद के साथ एंड्रॉयड और मल्टी मीडिया का शानदार अनुभव कराएगा.

मोटोरोला की नई पेशकश

भारतीय बाज़ार में गैजेट लवर्स को देखते हुए कई देशी-विदेशी कंपनियां यहां अपने नए-नए प्रोडक्ट लांच कर रही हैं. कम से कम कीमत पर बढ़िया और नई तकनीक बाज़ार में लाने की होड़ सी मच गई है. सभी कंपनियों द्वारा बाजार में अपने मोबाइल, आईपैड और आईफोन लांच किए जाने के बाद यह दौर टेबलेट का है. इसी क्रम में मोटोरोला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. मोटोरोला ने अपना जूम टेबलेट भारत में लांच कर दिया है. ध्यान रहे कि यह वही जूम टेबलेट है, जिस पर गूगल ने अपने टेबलेट्स के लिए विशेष तौर पर बनाया एंड्रॉयड 3.0, जिसे हनीकॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, को सबसे पहले लगाया था. मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया ने अपने टेबलेट जूम को पेश किया है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 32,990 रुपये है. यह टेबलेट निजी कंप्यूटर (पीसी) जैसा कार्य करता है, लेकिन आकार में छोटा होता है. एंड्रॉयड आधारित जूम 10.1 इंच एचडी डिस्पले, 1 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर और पांच मेगा पिक्सल के कैमरे से लैस है. यह वाई-फाई और 3-जी संस्करणों में उपलब्ध है, जिनकी क़ीमत क्रमश: 32,990 और 39,990 रुपये है. मोटोरोला मोबिलिटी मोबाइल डिवाइस बिजनेस के कंट्री प्रमुख राजन चावला ने कहा कि मोटोरोला जूम टेबलेट का इस्तेमाल काफी आसान है. इसे भारत में एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब, ब्लैकबेरी प्लेबुक और एचटीसी फ्लायर से प्रतिस्पर्धा करनी होगी.

मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया ने अपने टेबलेट जूम को पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 32,990 रुपये है.

टोयोटा की लीवा

भारतीय बाज़ार में टोयोटा की पहचान अभी तक बड़ी कारों से की जाती रही है, लेकिन कंपनी की यह पहचान अब बदल जाएगी. दरअसल, दुनिया की इस दिग्गज कार कंपनी ने भारतीय बाज़ार में अपनी हैचबैक लीवा पेश कर दी है. लीवा हाल में लांच की गई कार टोयोटा इटियोस का हैचबैक वर्जन है. भारत में यह टोयोटा की सबसे सस्ती कार होगी. इस कार का इंटीरियर कुछ हद तक टोयोटा इटियोस से ही मिलता- जुलता है. लीवा में एबीएस, एयरबैग्स और ईबीडी जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं. हालांकि ये तीनों फीचर्स लीवा के वी और वीएक्स वैरिएंट्स में दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस कार में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फीचर को भी शामिल किया गया है. लीवा में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो 80 बीएचपी पावर देगा. फ़िलहाल कंपनी ने इसे केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही लांच किया है, लेकिन इस साल के अंत तक इसका डीजल वैरिएंट भी पेश किया जा सकता है.

भारतीय सड़कों पर लीवा का कड़ा मुक़ाबला मारुति की स्विफ्ट, निसान माइक्रा, हुंदई आई-20 और फोक्स वैगन की पोलो से होगा. हालांकि कंपनी का दावा है कि लीवा अपनी प्राइस रेंज में सबसे बेहतर कार साबित होगी. कंपनी भारत में इसे चार मॉडलों जे, जी, वी और वीएक्स में उतार रही है. शहरों में यह कार 18.31 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 3.99 लाख से लेकर 5.99 लाख रुपये तक होगी.

एचटीसी का फ्लायर टेबलेट

फ्लायर में एचटीसी का शानदार सेंस इंटरफेस है, जिससे टेबलेट को इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है और आप इस पर कलम जैसी स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं.

एचटीसी ने भारतीय बाज़ार में अपना फ्लायर टेबलेट लांच कर दिया है. लांच के साथ ही गैजेट लवर्स ने इससे काफी उम्मीद लगाई है. इस टेबलेट की कीमत काफ़ी चौंकाने वाली है यानी 39,890 रुपये. इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर नहीं है. हालांकि 1.5 का क्वालकॉम प्रोसेसर सिंगल कोर होने के बावजूद काफी तेज़ है, इसका डिसप्ले सात इंच का है और यही नहीं, इसमें एंड्रॉयड 2.3 है, जो फ़ोन पर ज्यादा देखने को मिलता है. फ्लायर में एचटीसी का शानदार सेंस इंटरफेस है, जिससे टेबलेट को इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है और आप इस पर कलम जैसी स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं.

स्मार्ट फोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी एचटीसी इंडिया के कंट्री मैनेजर फैजल सिद्दीकी ने कहा, मैंने एक अलग तरह की निजता वाला टेबलेट अनुभव पेश करने को अवसर के तौर पर देखा. हम फ्लायर को भारत में पेश करके उत्साहित हैं. एचटीसी फ्लायर को बाजार में पहले से मौजूद सैमसंग गैलेक्सी, ब्लैकबेरी प्लेबुक और एप्पल आईपैड जैसे बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा. इसका सात इंच का टच स्क्रीन टेबलेट खास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस-एचटीसी सेंस से लैस है. इसके अंतर्गत इस टेबलेट में नेचुरल टच और पेन इंट्रैक्शन की सुविधाएं हैं. एचटीसी के मुताबिक़, उसने अपनी नई वीडियो सर्विस, जिसे एचटीसी वॉट नाम दिया गया है, को टेबलेट में पहली बार इस्तेमाल किया है. साथ ही कंपनी ने अपने टेबलेट पर गेमिंग को रोमांचक बनाने के लिए क्लाउड गेमिंग की सबसे प्रमुख कंपनी ऑन लाइव इंक के साथ समझौता भी किया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

इन सभी खिलाड़ियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. नाडा अभी भी कई नमूनों की जांच कर रहा है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस टेस्ट में अभी कई खिलाड़ियों के नाम सामने आ सकते हैं.

डोपिंग का जाल

सिर्फ़ खिलाड़ी और कोच दोषी नहीं

डोपिंग के शिकार खिलाड़ी

नाम	सज़ा	खेल
विली मेस	20 साल आठ महीने	बेसबॉल
मेल हॉल	45 साल	बेसबॉल
ऐडी जॉन्सन	आजीवन प्रतिबंध	बास्केटबॉल
फ्लोड मेवेदर सी.	5 साल	बॉक्सिंग
माइक टाइसन	3 साल	बॉक्सिंग
मिसी जिवो	6 महीने	साइक्लिंग
स्टीव डर्बानो	7 साल	आइस हॉकी
इवेंजोलोस गाउसिस	20 साल	मार्शल आर्ट
वाइस ली	12 साल	मोटर स्पोर्ट
जे एडम्स	2 साल 6 महीने	स्केटबोर्डिंग
सिलिवीनो फ्रेंसिस्को	3 साल	स्नूकर
क्रिस्टोस लैकोवोस	5 साल	भारोत्तोलन

इनके अलावा और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बाद में डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाने पर उनके गोल्ड मेडल्स तक वापस छीन लिए गए हैं.

भारत के ज़्यादातर खेल पहले से ही क्रिकेट के मायाजाल में फंसकर ख़ुद के अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में डोपिंग के बढ़ते मामलों ने उन उभरते हुए खेलों और खिलाड़ियों को हाशिए पर डालने का काम किया है, जो किसी तरह क्रिकेट के बाज़ार के बीच अपने स्वर्ण पदकों की बदौलत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे. जिस तरह स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में एक-एक करके असफल होते जा रहे हैं, उससे न सिर्फ़ इन खिलाड़ियों की प्रतिभा पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, बल्कि इससे देश और संबंधित खेलों पर भी एक बदनुमा दाग़ लग गया है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर इस डोपिंग के लिए ज़िम्मेदार कौन है? खिलाड़ियों से पूछिए तो वे बताएंगे कि हमें तो सप्लीमेंट हमारे कोच देते हैं और हम अनजाने में इस तरह की अवैध दवाओं के शिकार हो जाते हैं. अगर यही सवाल कोच से पूछा जाता है तो उनका जवाब और भी ग़ैर ज़िम्मेदाराना होता है. उनके मुताबिक़ वे तो सारे खिलाड़ियों को सही सप्लीमेंट देते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में उक्त खिलाड़ी बाहर का खाना और पेय इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके शरीर में कुछ तत्व ऐसे आ जाते हैं, जो डोपिंग टेस्ट को पॉजिटिव बना देते हैं. यही सवाल अगर खेल मंत्रालय और फेडरेशन से पूछा जाता है तो उनका जवाब यह होता है कि इसके लिए खिलाड़ियों के कोच और उनके मार्गदर्शक ज़िम्मेदार हैं. हो सकता है कि सबके तर्क अपनी-अपनी जगह पर सही हों, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है, इस बात पर किसी को भी कोई तर्क नहीं सूझता और न कोई इसे रोकने के ठोस समाधान पर बात करता है.

हाल में जिस तरह 8 खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, उससे इतना तो साबित हो गया कि यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है. राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के टेस्ट के दौरान जिन 8 खिलाड़ियों के ए सैंपल में स्टेरॉयड पाए गए हैं, उनमें धाविका सिनी जोस, जौना मूर्मू, टियाना मैरी थॉमस, लंबी कूद के हरि कृष्णन और गोला फेंक की खिलाड़ी सोनिया आदि नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि सिनी जोस ने राष्ट्र मंडल और एशियाई खेलों की 4 गुना 400 मीटर रिले में पिछले वर्ष स्वर्ण पदक जीता था. सिनी, जौना, हरि कृष्णन और सोनिया के यूरिन सैंपल्स में मेथनडाइनोन पाया गया, जबकि टियाना के सैंपल में एपिमैथानडियॉल पाया गया. नतीजतन, इन सभी खिलाड़ियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. नाडा अभी भी कई नमूनों की जांच कर रहा है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस टेस्ट में अभी कई खिलाड़ियों के नाम सामने आ सकते हैं. भले ही हम कुछ खिलाड़ियों पर अस्थायी निलंबन की कार्यवाही करें या फिर किसी विदेशी कोच को बर्ख़ास्त कर दें.

हाल में जिस तरह 8 खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, उससे इतना तो साबित हो गया कि यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है. राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के टेस्ट के दौरान जिन 8 खिलाड़ियों के ए सैंपल में स्टेरॉयड पाए गए हैं, उनमें धाविका सिनी जोस, जौना मूर्मू, टियाना मैरी थॉमस, लंबी कूद के हरि कृष्णन और गोला फेंक की खिलाड़ी सोनिया आदि नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं.

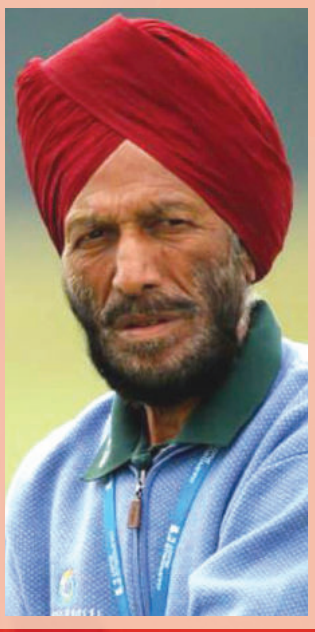

कोच ही खिलाड़ियों से कहता है कि अगर आप यह दवा लेंगे तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, आप दूर तक गोला फेंक पाएंगे. खिलाड़ियों को इन दवाओं के बारे में पता ही नहीं होता. तभी मैं कहता हूं कि कोचों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले कोचों को सबक मिले.

-मिल्खा सिंह

ज़्यादातर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, उनके कोच उन्हें जो भी देते हैं, वे उन पर विश्वास करके ले लेते हैं. इसलिए डोपिंग के लिए खिलाड़ियों को दोष देना सही नहीं है. मैं ऐसे कई खिलाड़ियों को जानती हूं, जिन्होंने यह बात ख़ुद मुझे बताई है.

-साइना नेहवाल

किसी विदेशी कोच को बर्ख़ास्त करने और आगे से ऐसे किसी भी कोच की सेवा न लेने का फ़ैसला काफ़ी हास्यास्पद है. क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि देशी कोच की मौजूदगी में इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे? पिछले कुछ सालों से भारत में डोपिंग के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का गठन किया था. यह संस्था काफ़ी हद तक सफल भी रही. मई 2010 से लेकर अब तक यानी 11 महीनों के दौरान 122 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए. इनमें अधिकतर पहलवान और भारोत्तोलक हैं. इसके अलावा वर्ष 2010 में अगस्त तक नाडा ने 2047 एथलीटों के नमूने लिए थे, जिनमें 103 एथलीट विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थ सेवन करने के दोषी पाए गए. इनमें कुछ जूनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं. हाल में राष्ट्र मंडल खेलों की टीम में शामिल 18 खिलाड़ी भी डोपिंग के दोषी पाए गए, जिनमें 12 खिलाड़ी मिथाइलहेक्सानेमाइन के सेवन के दोषी पाए गए.

जिस तरह नाडा अपना काम कर रही थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि डोपिंग के शिकंजे से खिलाड़ियों को छुड़ाना अब आसान हो गया है, लेकिन इस वाक़िये ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है. मामलों को बढ़ता देख अब टेस्ट के अलावा ड्रग्स की धोखेबाज़ी को पकड़ने के लिए एनएडीए खिलाड़ियों के घरों पर भी छापा मारने की बात कही जा रही है. असल में छापा मारने की कवायद नाडा ने एक ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के आधार पर तय की है, जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी के घर अचानक छापा मारा जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे पर बहुत प्रभावी काम किया है, लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे रहा है कि यह मॉडल नाडा से कितना बेहतर साबित होगा. कहीं ऐसा न हो कि छापेमारी चलती रहे और खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आते रहें. अगर फेडरेशन वाक़ई इस संकट से निजात चाहता है तो वह पहले खिलाड़ियों और उनके कोचों की दलीलों में न फंसकर गंभीरता से जांच करे कि खिलाड़ियों के भोजन, पेय और सप्लीमेंट तक आख़िर ये प्रतिबंधित पदार्थ पहुंचते कहां से हैं? साथ ही वह खिलाड़ियों को यह संदेश भी दे कि वे अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों पर आश्रित होने के बजाय अभ्यास और कड़ी मेहनत पर ज़ोर दें. अन्यथा ये खिलाड़ी फिर किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाएंगे और प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के आरोप में वापस भेज दिए जाएंगे. अभी मामला घर में है, यहीं सुलझा लिया जाए और इस डोपिंग के जिन्न के असली आक़ा को पकड़ा जाए तो बेहतर होगा.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 जुलाई–24 जुलाई 2011

भंसाली ने लीक से हटते हुए अगली फिल्म बनाई-ब्लैक. 2005 में रिलीज़ इस फिल्म में भंसाली ने अपनी निर्देशकीय क्षमता को पूरी शिद्दत के साथ पेश किया.

हिट शो के लिए तरसते शो मैन–4

संजय लीला भंसाली : कैमरे में कमाल, कहानी से कंगाल

सुषमा गुप्ता

संजय लीला भंसाली. आज के दौर के भारत के सबसे महंगे निर्देशक. सिनेमा में लाइट और कलर की जैसी समझ संजय लीला भंसाली को है, वैसी समझ आज के दौर के किसी दूसरे फिल्मकार को नहीं है. संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में कैमरे के कमाल से विमल रॉय जैसे फिल्मकार की याद दिलाते हैं. भंसाली की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म गुज़ारिश कामयाबी हासिल नहीं कर सकी. सांवरिया के बाद भंसाली की एक और फिल्म फ्लॉप. हालांकि इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी भंसाली की फिल्मों का क्रेज बरक़रार है और अभिनेता ही नहीं, दर्शकों को भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है. भंसाली ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट नहीं की हैं. वह एक फिल्म पूरी होने के बाद अगली फिल्म पर काम करने में यक़ीन रखने वाले फिल्मकारों में से एक हैं. लेकिन इसके बाद भी संभावनाओं से भरपूर यह निर्देशक कभी हिट और कभी फ्लॉप रहा. आख़िर इसकी वजह क्या है, यह समझना भी ज़रूरी है.

निर्देशक बनने से पहले भंसाली ने निर्देशन की बारीकियां सीखने के लिए विधु विनोद चोपड़ा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया. परिंदा और 1942 ए लव स्टोरी में संजय विधु विनोद चोपड़ा के सहायक थे. इसके बाद 1996 में उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की–ख़ामोशी द म्यूज़िकल. सलमान ख़ान, मनीषा कोईराला स्टारर इस फिल्म में नाना पाटेकर और सीमा विश्वास ने मनीषा कोईराला के ऐसे माता–पिता का किरदार निभाया, जो बोल और सुन नहीं सकते. फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन समीक्षकों ने सराहा और संजय की संवेदनशीलता की तारीफ़ की. भंसाली इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या को लेकर हम दिल दे चुके सनम लेकर आए. फिल्म हिट रही और समीक्षकों ने भी सराहा. भंसाली ने इसके बाद देवदास बनाई, लेकिन समीक्षकों को नए देवदास में वह दम नज़र नहीं आया. फिल्म अपनी भव्यता को लेकर ज़रूर चर्चाओं में रही. इन फिल्मों ने भंसाली को कामयाब तो बना दिया, लेकिन वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, जो उनके अंदर विद्यमान थीं.

भंसाली ने लीक से हटते हुए अगली फिल्म बनाई–ब्लैक. 2005 में रिलीज़ इस फिल्म में भंसाली ने अपनी निर्देशकीय क्षमता को पूरी शिद्दत के साथ पेश किया. कहानी, प्रस्तुति, अभिनय एवं कलात्मकता हर तरीक़े से फिल्म लाजवाब थी. न सिर्फ़ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में इस फिल्म का डंका बजा. फिल्म को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया भर में साल की पांच फिल्मों में शुमार किया. फिल्म ऑस्कर की दावेदार थी, पर राजनीति के चलते फिल्म को ऑस्कर में नहीं भेजा गया. लेकिन इस कामयाबी के बाद ही भंसाली अपने ट्रैक से हट गए. ब्लैक के बाद भंसाली ने सांवरिया बनाई, लेकिन काले रंग की तरह नीला रंग दर्शकों को लुभा नहीं पाया. दर्शकों को समझ में नहीं आया कि वे क्या देखने आए हैं. यहां से भंसाली समय और समाज से ख़ुद को जोड़ने में नाकाम साबित हुए. भंसाली इस पीढ़ी के विरले फिल्मकार हैं. वह ट्रेंड और फॉर्मूला आदि का पालन नहीं करते. उनके सुंदर संसार में सब कुछ सामान्य से अधिक सुंदर और विशाल होता है. पूरे माहौल में भव्यता नज़र आती है. भंसाली के किरदारों का सामाजिक आधार काल्पनिक होता है. उनके आलोचक कह सकते हैं कि भंसाली अपनी फिल्मों की ख़ूबसूरती, भव्यता और मैलोड्रामा की दुनिया को रीयल नहीं होने देते. कई बार यह बात चमत्कृत करती है तो ब्लैक बनती है और कई बार कोई प्रभाव पैदा नहीं हो पाता तो वह सांवरिया बन जाती है. दरअसल, भंसाली की फिल्में काफ़ी कलात्मक और भव्य होती हैं. फिल्म का सेट शानदार होता है. फ्रेम ख़ूबसूरत पेंटिंग की तरह नज़र आता है. ऐसी मेहनत करने वाले कम ही कलाकार होते हैं. लेकिन भंसाली जितनी मेहनत अपनी फिल्मों को कैमरे से रचने में करते हैं, शायद उतनी मेहनत क़लम से रचते वक़्त नहीं करते. उनकी जितनी भी फिल्में आईं, ज़्यादातर में कहानियां नई नहीं हैं. देवदास शरत चंद्र की कालजयी रचना है तो हम दिल दे चुके सनम वो सात दिन से प्रभावित थी. ब्लैक की कहानी के बारे में कहा गया कि विदेशों में इस पर फिल्में बन चुकी हैं. हालिया रिलीज़ गुज़ारिश की कहानी पर भी एक लेखक ने दावा ठोंक दिया है और आरोप लगाया है कि भंसाली ने उनकी कहानी चुराई. उनकी फिल्मों में कई बातें अच्छी तरह व्यक्त ही नहीं हो पातीं. संजय लीला भंसाली की सृजनात्मकता और सिनेमाई समझ पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन यह फिल्मकार अगर समय और समाज से जुड़कर कुछ नई कहानियों पर काम करे तो यक़ीनन ब्लैक जैसी फिल्म बार–बार देखने को मिलेगी.

feedback@chauthiduniya.com

काजल की ख़ुशी का राज़

पंजाबी कुड़ी काजल अग्रवाल ख़ुश हैं और उत्साहित भी कि बतौर नायिका हिंदी फिल्मों में उनके सफ़र की शुरुआत हो चुकी है. काजल कहती हैं कि मुंबई में पले–बढ़े होने के कारण हिंदी फिल्मों में काम करना उनका सपना था, जो अब पूरा हो रहा है. हिंदी फिल्मों में काम करना उनके लिए स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय मुंबई में बिताया है. सिंघम जैसी बड़ी फिल्म से उनका डेब्यू हो रहा है और इसके लिए वह बेहद एक्साइटेड हैं. काजल ख़ुद को साउथ की हीरोइन नहीं मानती हैं, क्योंकि वह पंजाबी हैं. फिर भी वह दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हैं कि उन्हें वहां अपना टैलेंट दिखाने का बेहतरीन मौक़ा मिला. उसी वजह से वह इस मुक़ाम पर हैं. सिंघम की शूटिंग के दौरान अजय देवगन का साथ काजल को ख़ूब भा रहा है. वह कहती हैं, सेट पर मैंने उनके साथ ख़ूब एंज्वॉय किया. उनके साथ फिल्म में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा. हिंदी फिल्मों में बतौर लीड रोल काजल के सफ़र की शुरुआत कितनी धमाकेदार होती है, यह तो सिंघम की रिलीज के बाद पता चलेगा, पर फिल्मी गलियारे में काजल की ख़ूबसूरती के चर्चे काफ़ी गर्म हैं. अजय भी इस युवा अभिनेत्री के अंदाज़ और ख़ूबसूरती के मुरीद हैं. काजल के पास हिंदी फिल्मों के प्रस्ताव बड़ी संख्या में आ रहे हैं. वह कहती हैं, यह तो होना ही था, मुझे हिंदी फिल्मों का हिस्सा बनना था, मैं ख़ुश हूं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

सिंघम

गोलमाल सीरीज में कॉमेडी करने वाले अजय देवगन अब फिर से मारधाड़ करते नज़र आएंगे. अजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिंघम तैयार है. फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है. फिल्म के लिए अजय ने बॉलीवुड में चल रहे फैशन और स्टाइल को अपनाया है. यह फिल्म सफलतम तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी संस्करण है. इसमें अजय के साथ बॉलीवुड छोड़कर तेलुगु सिनेमा की मुख्य नायिका के तौर पर स्थापित हो चुकीं अभिनेत्री काजल नजर आएंगी. काजल 2004 में बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना में नज़र आ चुकी हैं. अजय देवगन बहुत ही देशी और रोमांचकारी एक्शन सीन के साथ बाजीराव सिंघम नामक एक ऐसे पुलिस वाले की भूमिका में हैं, जो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है.

फिल्म में अजय देवगन, काजल अग्रवाल, प्रकाश राज, अशोक सर्राफ, सचिन खेडेकर, सोनाली कुलकर्णी एवं अनंत जोग आदि मुख्य: किरदारों में नज़र आएंगे. सिंघम एक भोले-भाले पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है. महाराष्ट्र के एक क़स्बे में उसकी पोस्टिंग है. वह अपने हिसाब से वहां लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करता है. उसकी भिड़ंत एक शहरी अपराधी से हो जाती है. उस अपराधी के राजनीतिक संबंध बहुत ऊंचे हैं. सिंघम को सबक़ सिखाने के लिए वह उसका प्रमोशन और ट्रांसफर करा देता है. यह फिल्म एक भोले व्यक्ति और करप्ट सिस्टम के बीच की जंग है. रोचकता बनाए रखने के लिए फिल्म की शूटिंग गोवा, मुंबई एवं सतारा आदि स्थानों पर की गई. तमिल फिल्म सिंघम में अभिनेता सूर्या थे और यह बहुत लोकप्रिय हुई थी. अब अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई के सुपरहिट फार्मूले पर आधारित सिंघम क्या अजय देवगन को एक बार फिर एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित कर पाएगी? फिल्म के लिए अजय ने छाती पर एक शिवा का टैटू गुदवाया है. सिक्स पैक बनाने के लिए अजय ने तीन महीने जिम में पसीना बहाया. अपने पसंदीदा कलाकार अजय देवगन को एक बार फिर एक्शन हीरो के रूप में देखना बढ़िया अनुभव होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश

मिनिषा लांबा अपनी तुलना शायद शाहरुख़ ख़ान से करने लगी हैं या फिर उनका मज़ाक़ उड़ा रही हैं. पिछले दिनों अघोषित आभूषण साथ में रखने के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर रोके जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मिनिषा कहती हैं कि उस अनुभव से उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ है. अब अगर उन्हें किसी फिल्म में ऐसी लड़की का रोल मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया हो तो वह उस रोल को अच्छी तरह निभा सकती हैं. उस परिस्थिति में कैरेक्टर का रिएक्शन कैसा होगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, इसका उन्हें अनुभव हो चुका है. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जिसे इस घटना ने उन्हें सिखा दिया है. इसका क्या मतलब निकाला जाए मिनिषा, क्या आप आने वाली किसी फिल्म में अपने कैरेक्टर का संकेत दे रही हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के किसी डायरेक्टर- प्रोड्यूसर को ऐसे हालात पर फिल्म बनाने का आइडिया दे रही हैं. पिछले ही दिनों मिनिषा विनय पाठक की फिल्म भेजा फ्राई-2 में नज़र आई थीं. मिनिषा स्वीकार करती हैं कि भेजा फ्राई-2 में अभिनय के दौरान वह एकता कपूर से प्रेरित थीं. पूरी दुनिया ने एकता कपूर की सफलता की कहानी देखी और सुनी है. चूंकि मैं टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही लड़की की भूमिका निभा रही थी, इसलिए एकता से इंस्पायर होना मेरे लिए लाज़िमी था. अब मिनिषा फिल्मों के चयन के प्रति सतर्क हो गई हैं. वह बताती हैं, मैंने बचना ऐ हसीनों, किडनैप, रॉकी और अनामिका जैसी बड़ी कॉमर्शियल फिल्में की हैं. अब मैं वैसी फिल्में करना चाहती हूं जो अच्छी हों. उनका बजट मेरे लिए मायने नहीं रखता. मेरा मानना है कि फिल्म बड़ी हो या छोटी, दर्शकों का पूरा मनोरंजन होना चाहिए. मैं फिल्में बजट के हिसाब से नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट देखकर स्वीकार करती हूं. मिनिषा बताती हैं, फिल्म भेजा फ्राई-2 के डायरेक्टर सागर बेल्लारी के साथ एक फिल्म कर रही हूं, नाम है हम तुम और शबाना. एक और फिल्म शिरीष कुंदेर की है जोकर, उसमें भी मैं काम कर रही हूं.

चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 जुलाई–24 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश कब लगेगा

भारत में पिछले तीन दशकों में क़रीब 42 लाख से 1.21 करोड़ के बीच कन्या भ्रूणों की हत्या की जा चुकी है. इतना ही नहीं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में रहने वाले भारतीय भी बेटी की बजाय बेटे को तरजीह देते हैं और लिंग परीक्षण कराते हैं. कन्या भ्रूण होने पर तत्काल गर्भपात करा लेते हैं.

राजेश नामदेव

देश में सब कुछ बदल रहा है, पर जो नहीं बदल रहा है वह है मानसिकता. हमारी सोच आज भी बेटे-बेटियों के मामले में अब भी पुरातन व रूढ़ीवादी है. यही कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. अफ़सोसजनक-शर्मनाक तथ्य यह है कि कन्या भ्रूण हत्या कराने में पढ़ा-लिखा और अपने को सुसंस्कृत कहने वाला वर्ग सबसे आगे है. इसलिए शासकीय व सामाजिक संगठनों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चलाए गए सारे जनजागरण अभियान असफल सिद्ध हो रहे हैं. जनगणना में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों की संख्या में गिरावट के बावजूद किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन राज्य के पिछड़े समझे जाने वाले मराठवाड़ा के बीड़ ज़िले में खुलेआम मादा भ्रूण मिलने की घटना ने खलबली मचा दी. यह हालत महाराष्ट्र की है जो देश के उन्न और शिक्षित राज्यों में गिना जाता है.

महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले में जून माह के दूसरे सप्ताह में एक नाले में 9 मादा भ्रूण मिलने की घटना ने राज्य में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में आ रही गिरावट का रहस्य खोल दिया है. जनगणना के आंकड़ों को देखने से साफ़ पता चलता है कि महाराष्ट्र में लड़कियों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है. जहां 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों के अनुपात में 946 लड़कियां होती थीं, वहीं यह आंकड़ा 2001 में 913 और अब 2011 की जनगणना में घटकर 883 पर आ गया है. इन आंकड़ों को लेकर सरकार जहां चिंतित है, वहीं बेटे की चाहत रखने वाले लोग ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना की गर्भ में ही हत्या करने-करवाने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं. यह महाराष्ट्र की आधुनिकता, सभ्यता और हर तरह के विकास पर तमाचा है. संसाधनों के मामले पर हम चाहे जितना विकास कर चुके हों, पर मानसिकता के मामले में आज भी हम पिछड़े हैं. इससे यह भी अहसास हो रहा है कि शिक्षित गंवारों की संख्या बढ़ रही है, जो आधुनिकता के लिबास में अपना गंवारपन छुपाए हुए है, क्योंकि पिछड़े-अनपढ़ दलित, आदिवासियों में कन्याओं की गर्भ में हत्या नहीं की जाती है. ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि जलगांव की 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर मात्र 801 लड़कियां हैं यानी राज्यस्तरीय औसत से 82 कम.

बीड़ में भ्रूण हत्या की घटना के बाद एकाएक राज्य सरकार की आंख तब खुली जब एक वरिष्ठ राजनेत्री रजनीताई पाटिल ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाक़ात कर इस मामले की शिकायत की और मामले को गंभीरता से लेने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी को बुलाकर पूरे भ्रूण हत्या मामले की जांच करने के निर्देश दिए. जांच के प्रारंभिक चरण में सभ्य समाज के चेहरे की सफ़ेदी उतरने लगी और कालिख पुता चेहरा सामने आने लगा. नागपुर, बीड़, मुंबई पुणे, चंद्रपुर, गोंदिया, अमरावती आदि राज्य के शहरों में जैसे-जैसे जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ा वैसे-वैसे शिक्षित सभ्य लोगों का वीभत्स चेहरा सामने आता गया. जून माह के अंत तक छापामार कार्रवाई कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क़रीब 200 सोनोग्राफी जांच केंद्रों को सीलबंद कर उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में अवैध रूप से लिंग परीक्षण का धंधा ज़ोरों पर चल रहा है. आरेंज सिटी अस्पताल व रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ. अनूप मरार का कहना है कि कन्या भ्रूण हत्या होना ग़लत है, यह अपराध है. लड़के-लड़कियों के बीच का बढ़ता अनुपात चिंता का विषय है. इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए. उपाय किए जाने चाहिए, वरना एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अभी लड़की को देखने लड़के आते हैं तो भविष्य में लड़कों को देखने लड़कियां जाया करेंगी. मगर उन्होंने जांच अभियान के तरीक़े पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि बीड़ का मामला उजागर होने के बाद जिस तरीक़े से सोनोग्राफी सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उससे यह कैसे पता चलेगा कि कौन-सा सोनोग्राफी सेंटर लिंग परीक्षण के कार्य में लिप्त है. कार्रवाई होना सही है और दोषियों को उनकी करनी का फल मिलना चाहिए, पर जांच के तरीक़े का अब तक सरकार ने कोई ख़ुलासा नहीं किया है. इस संबंध में जब राज्य के स्वास्थ्य विभाग पुणे के अतिरिक्त निदेशक डॉ. सूरज गुप्ता से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम पूरे राज्य में स्थित 7939 सोनोग्राफी सेंटरों की जांच कर रहे हैं. एमटीपी एक्ट 1971 व अन्य क़ानूनों में लिंग परीक्षण रोकने के संबंध में 30-35 प्रावधान हैं. जो भी सोनोग्राफी सेंटर इन प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है. कुछ सोनोग्राफी सेंटर संचालकों ने तो अपने एक से अधिक सेंटरों को बंद करने के लिए आवेदन देना भी शुरू कर दिया है. लातूर रेडियोलॉजी एसोसिएशन ने अपने कुछ सेंटर बंद करने के लिए आवेदन दिया है. हाल ही में पुणे स्थित संस्था विजन इंडिया साफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स द्वारा विकसित डिवाइस साइलेंट आब्जर्वर को सोनोग्राफी सेंटरों में लगाए जाने के संबंध में डॉ. गुप्ता ने कहा कि अभी यह डिवाइस प्रायोगिक स्तर पर है और यदि नतीजे उत्साहवर्धक रहे तो ज़रूर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. जनसंख्या के आधार पर सोनोग्राफी सेंटर स्थापित करने विषय में उन्होंने बताया कि यह सब्जेक्ट मीटिंग में उठा और चर्चा भी हुई, पर इस मामले में हम जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं लिया जा सकता है. पहले हमें एक मशीन की क्षमता का आकलन करना होगा, उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितनी जनसंख्या के बीच कितनी मशीन लगाई जाए. यह प्रस्ताव विचाराधीन है. दोषी पाए गए सोनोग्राफी सेंटरों के लाइसेंस रद्द करने संबंध में उन्होंने बताया कि इस जांच अभियान के बाद एक समिति बैठेगी और सभी मामलों पर ग़ौर कर कोर्ट में पेश किया जाएगा. उसके बाद कोर्ट क़ानूनी प्रक्रिया के तहत अपना फ़ैसला देगा और उस अमल किया जाएगा. कन्या भ्रूण हत्या की विकृति को बढ़ावा लालची तत्व देकर चिकित्सकीय पेशे को बदनाम कर रहे हैं. इन हैवानों ने श्रद्धा-भक्ति के पात्र देवी-देवताओं को भी अपने गोरखधंधे का हिस्सा बना लिया है. बीड में जांच के दौरान पता चला कि लिंग परीक्षण का गोरखधंधा करने वाले डॉक्टरों ने परीक्षण के लिए आने वाले दंपत्तियों को यह बताने के लिए कि लड़का है या लड़की, नए कोड वर्ड बना रखा था, ताकि वहां मौजूद अन्य शख़्स को उन पर किसी तरह का का कोई संदेह न हो. परीक्षण के परिणामस्वरूप यदि गर्भ का लिंग नर होता तो डॉक्टर जय श्री गणेश कहता था और लड़की होने पर जय माता दी. यह सर्वविदित है कि जय माता दी और जय श्री गणेश का उद्घोष महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लोग दशहरा उत्सव और गणेशोत्सव में बड़ी श्रद्धा व भक्तिभाव से लगाते हैं. मगर इन भगवानों को भी शैतानी डॉक्टरों ने नहीं बख़्शा है. जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि एक ही व्यक्ति के सोनोग्राफी के 8-9 तक केंद्र हैं. मामला उजागर होने के बाद सरकार का कहना है कि अब जनसंख्या के आधार पर सोनोग्राफी केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है. पिछले वर्ष किए गए अध्ययन से जो तथ्य सामने आए उससे यह समस्या और भी भयावह हो उठती है. एक विदेशी पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वे में बताया गया है कि भारत में पिछले तीन दशकों में क़रीब 42 लाख से 1.21 करोड़ के बीच कन्या भ्रूणों की हत्या की जा चुकी है. इतना ही नहीं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में रहने वाले भारतीय भी बेटी की बजाय बेटे को तरजीह देते हैं और लिंग परीक्षण कराते हैं. कन्या भ्रूण होने पर तत्काल गर्भपात करा लेते हैं. शिक्षित संपन्न भारत का यह चेहरा बेहद शर्मनाक है. देश का हर समझदार तबक़ा कन्या-भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं से चिंतित है और हर तरह से इसे रोकना चाहता है, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे वर्तमान से ज़्यादा भविष्य जुड़ा हुआ है. सरकार की तरफ़ से भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई अभियान चलाए गए और चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन अभियानों का अभी तक कोई ख़ास असर समाज पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है. कन्या-भ्रूण हत्या का खेल बदस्तूर जारी है. क़ानूनी तौर पर भ्रूण हत्या अपराध है. इसके बावजूद यह अपराध अजन्मी बच्चियों के मां-बाप लालची डॉक्टरों से मिलीभगत कर करते हैं. क़ानूनी प्रावधानों के तहत इसके लिए दोषियों के लिए सज़ा का प्रावधान तो है, पर कार्रवाई नहीं होती है. एमपीटी एक्ट 1971 के अनुसार किसी ग़ैर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा गर्भपात किए जाने का मामला ज़ाहिर होने पर संस्था संचालक और डॉक्टर को 2 से 7 साल के कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान है. साथ ही प्रसव से पहले लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर को भी 3 से 5 साल कारावास की सज़ा या 10 से 50 हज़ार जुर्माना अथवा दोनों से ही दंडित किया जा सकता है. इसके बाद भी भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकारी निगरानी एजेंसियां निष्क्रिय बनी रहती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

लाइसेंस की शर्तें सख्त होंगी : शेट्टी

स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी का कहना है कि सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के मामले को गंभीरता से लिया है. इस समस्या के निवारण के लिए सरकार शीघ्र की एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, ताकि लोग ऐसे सोनोग्राफी सेंटरों की सूचना दे सकें जो अवैध लिंग परीक्षण के धंधे में लिप्त हैं. इसके अलावा सरकार लोगों में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों में जनजागृति लाने के लिए अभियान भी शुरू करेगी. सोनोग्राफी सेंटरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया के कुछ प्रावधानों को सख्त किए जाने की ज़रूरत है. ख़ासकर जिन लोगों को उचित शिक्षा, उचित प्रशिक्षण या उचित अनुभव नहीं है, उन्हें इसका लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए. इसके लिए क़ानून में परिवर्तन करने के लिए केंद्र से संपर्क किया जाएगा. एमटीपी क़ानून में भी परिवर्तन की ज़रूरत है.

नकोशियों का दर्द

अनचाही पैदा हुई बेटियां भी लिंग भेद प्रताड़ना का शिकार बनती हैं. अचाही या अनचाही जन्मी बेटियों को महाराष्ट्र में नकोशी कहा जाता है. इन अचाही बेटियों को परिवार वाले नकोशी नाम से ही संबोधित करते हैं. इनकी पीड़ा यह है कि उन्हें परिवार में उपेक्षित समझा जाता है, क्योंकि बेटे की जगह उनका जन्म होता है. यह हमारे देश की पुरानी और बीमार मानसिकता का परिचायक है. कुछ ही दिनों पहले पुणे के एक गांव नरहे की एक नकोशी सरपंच बनी. उसने सरपंच बनने के बाद अपना नाम बदलने का फ़ैसला किया. इस नकोशी का नाम परिवर्तन गांव में धूमधाम से किया गया और उसने अपना नाम स्वयं चुना जयश्री. जब नकोशी से नाम बदल कर जयश्री रखने की समारोह में घोषणा की गई तो वहां उपस्थित सभी लोग चिल्ला रहे थे- तुम नकोशी (अचाही) नहीं हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है. सरपंच ने अपना नाम इसलिए बदला, क्योंकि पुराना नाम अपमानजनक लगता था. समारोह में 25 अन्य नकोशियां भी उपस्थित थीं और सभी ने अपना नाम बदलने की इच्छा ज़ाहिर की. उन नकोशियों की भी सम्मानजनक जीवन जीने की तमन्ना है. यह नकोशी परंपरा भ्रूण हत्या का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है.

सामाजिक दायित्व निभाएं

भारतीय समाज चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हर व्यक्ति को देवता के समकक्ष मानता है, क्योंकि वे लोगों का उपचार कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य करते हैं. इसके बावजूद यदि यही लोग यमराज की भूमिका निभा रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि वे अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभा रहे हैं. हर हॉस्पिटल व क्लीनिक में यह लिखा रहता है कि यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है. लिंग परीक्षण कराना क़ानूनन अपराध है. इसके बाद भी लिंग परीक्षण जारी रहना चिंता का विषय है. चौथी दुनिया सभी चिकित्सकों से यह आह्वान करता है कि लिंग परीक्षण करने वालों को वे बेनक़ाब करें और ख़ुद भी यमराज की भूमिका त्याग कर गर्भपात करने के पहले ज़रा सोचें. अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए अपने देवतुल्य भूमिका का सम्मान बचाए रखें, वरना उनमें और क़साई में क्या फ़र्क़ रह जाएगा.

दादा का स्पष्ट मत है कि बिजली भारनियमन से मुक्त होने के बाद राज्य का विकास और तीव्र गति से हो सकेगा.

अब रामदेव बाबा का आंदोलन तो सरकार ने कुचल दिया, ऐसा सरकार को लग रहा है, लेकिन अब इमारे अण्णा नामक जिन्न से वह परेशान हैं. रोज़ नए पैंतरे खेले जा रहे हैं.

सबके दादा अजीत दादा

महाराष्ट्र के जननेता और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का 22 जुलाई को जन्मदिन है. चौथी दुनिया महाराष्ट्र की ओर से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं.

प्रशासन पर कड़ी पकड़, कुशल प्रशासक, स्पष्ट वक्ता और त्वरित निर्णय जैसे कुछ गुण दादा में ऐसे हैं जो उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में हर दृष्टि से दादा के रूप में सम्मान प्रदान करते हैं. हमारे महाराष्ट्र में दादा का अर्थ बड़ा भाई होता है. बड़ा भाई वह जो सभी के साथ समान व्यवहार कर सके, वह जो सभी को समान न्याय दे सके. परिवार के हर सदस्य के साथ समानता का व्यवहार कर सके. महाराष्ट्र के ये दादा हैं अजीत दादा पवार. यानी राज्य के उपमुख्यमंत्री. अन्य प्रांतों में दादा शब्द का अर्थ दादागिरी से भी लिया जाता है. जब प्रशासन में अपने निष्पक्ष फैसले को लागू करने की बारी आती है तो दादा की सख्ती का खौफ भी छाया रहता है. लेकिन राज्य की जनता के लिए तो उनका स्नेह भ्रातृत्व तुल्य है. यही कारण था कि जल संपदा मंत्री रहते हुए उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, उर्वरित महाराष्ट्र के साथ समान इंसाफ किया और जो काम आजादी के बाद नहीं हो पाए थे, उन्हें पांच वर्षों में ही कर दिखाया. अब उपमुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के खजाने की चाबी भी उनके हाथ में है. यानी वे राज्य के वित्त मंत्री भी हैं. इस वर्ष उन्होंने जब पहला बजट पेश किया तो उनके तमाम आलोचक तिलमिला कर रह गए. कारण साफ था, बजट में पूरे राज्य के साथ न्याय था. और बजट पेश करने के बाद जब शनिवार–रविवार को विधानमंडल का अवकाश था, नेता, अफसर छुट्टी मना रहे थे, दादा निकल पड़े थे राज्य के दौरे पर.

अजीत दादा देश के कृषि मंत्री शरद पवार को भतीजे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक कद विरासत में मिला है. गलत है. हां, पिता अनंतराव पवार का आशीर्वाद व चाचा शरद पवार का मार्गदर्शन व मदद मिली लेकिन 15 वर्षों के राजनीतिक सफर में दादा ने व्यक्तिगत रूप से जो मेहनत की है, उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है. जब पहली बार शरद पवार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी दादा किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे. 1978 में पिता का निधन हो जाने के बाद दादा ने कृषि कार्य शुरू कर दिया. 1984 में पहली बार छत्रपति सहकारी साखर (शक्कर) कारखाना के संचालक मंडल का चुनाव हुआ. इसमें संचालक के रूप में दादा भी निर्वाचित हुए. यह पहली बार था जब किसी पद पर वे निर्वाचित हुए थे. उस समय शरद पवार विरोधी पक्ष नेता हुआ करते थे और राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था. तब शरद पवार को महसूस हुआ कि बारामती में कोई जवाबदार व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी अनुपस्थिति जनता के संपर्क में रह सके. 1987 में दादा बारामती खरीदी बिक्री संघ जाने लगे. लोगों से संपर्क बढ़ता गया. हर किसी का काम करना. जब शरद पवार दोबारा मुख्यमंत्री बने तो दादा की भी जवाबदारी बढ़ी और उन्हें पुणे जिले में संपर्क का दायरा बढ़ाना पड़ा. लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ ही दादा ने युवा कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी टीम भी तैयार की थी. दादा खुद स्वीकार करते हैं कि इसके बाद ही वे शरद पवार के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में कमाल ही हो गया था. पहली बार जिला स्तर पर दादा ने कोई चुनाव लड़ा था. इसमें 200 में से 173 मत उन्हें मिले थे. यानी विरोधियों ने भी उन्हें मत दिए थे. इसके बाद दादा को बैंक का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था. इस जीत के बाद तो कहते हैं, शरद पवार ने भी पूछा था कि इतने वोट कैसे मिल गए. खैर 1991 में लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो शरद पवार को केंद्र की राजनीति में जाना पड़ा और अजीत दादा को राज्य में वापस लौटना पड़ा और तब से अब तक वे विधायक हैं.

दादा के राजनीतिक सफर पर संक्षिप्त नजर डालने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि जिन्हें उनके राजनीतिक सफर की जानकारी नहीं है, वे गलती से यह सोच बैठते हैं कि दादा को बैठे बिठाए शरद पवार के भतीजे होने के कारण उपमुख्यमंत्री पद की कुर्सी आसानी से मिल गई. चाचा शरद पवार की तरह ही अजीत दादा का राजनीतिक ग्राफ भी कभी नीचे नहीं आया है. नई तकनीक के साथ दादा ने स्वयं को हमेशा अपडेट किया है. यही कारण है कि पुणे का नाम आज आईटी के क्षेत्र में देश ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है. किसी पद पर आने के पहले ही जब दादा तहसील स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, उस समय से ही उनकी संगठन क्षमता निर्विवाद रही है. यही कारण है कि कार्यकर्ताओं की फौज हमेशा उनके साथ रही है. जनता का विश्वास ऐसा कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने 3.5 लाख मतों के अंतर से जीता था. राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही जनता की समस्याओं का हल कराने के लिए दादा का स्वभाव हमेशा कड़क रहा है. प्रशासन के सामने दादा का यह कड़क स्वभाव आज भी जारी है. झूठे आश्वासन देने वाले कार्यकर्ता दादा के सामने टिकते नहीं और काम करने में लापरवाही या आलस्य करने वाले सरकारी अधिकारी दादा के सामने जाने से ही घबराते हैं. वैसे दादा को स्पष्ट वक्ता कहा जाता है. उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है. जो कहते हैं, वही करते भी हैं. बारामती, पुणे में शरद पवार के प्रतिनिधि और फिर विधायक और मंत्री के रूप में दादा ने विकास कार्य क्या होता है, यह लोगों को बताया. जल संपदा मंत्री रहते हुए उन्होंने सिंचन अनुशेष काफी कम कर दिया. अब वे उपमुख्यमंत्री हैं. इस पद पर आने ही उन्होंने उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया कि उपमुख्यमंत्री का पद सिर्फ नाम का होता है. अपने स्तर पर बैठकें लेकर उन्होंने अपने स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लिए. इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई. लेकिन वे तो दादा हैं, दादा यानी बड़ा भाई, बड़ा भाई यानी जो सबका ध्यान रखे. राजनीति में सबके चश्मे अलग–अलग होते हैं. हर कोई दादा के कार्यों को अपने–अपने चश्मे से देखता है. लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं होता कि आखिर दादा ने वे सभी काम कैसे कर दिए जो आजादी के बाद 50 वर्षों में नहीं हुए थे. अजीत दादा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही पूरे राज्य का दौरा कर सभी क्षेत्रों की समस्याओं का जायजा लिया और उन्हें समझा. समाज के विविध घटकों से सीधा संवाद साध कर और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से समन्वय स्थापित कर राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रयत्नशील हैं. उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ ही उनके कंधों पर वित्त व ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार भी है. विविध प्रश्नों व संपूर्ण राज्य की भौगोलिक बारीकियों से अवगत होने के बाद अजीत दादा ने राज्य के सभी संभागों का दौरा कर जिला नियोजन समिति की बैठक ली. बैठक में संबंधित जिलों के प्रश्न, उनकी जरूरत और उनके समाधान के लिए आवश्यक निधि की प्रमाणिक रिपोर्ट प्राप्त की. सभी विभागों व सभी जिलों का समतुल्य विकास हो, इन बैठकों का यही मुख्य उद्देश्य था. इसके साथ ही उन्होंने सभी मंत्रालयों के सभी मंत्रियों व सचिवों की बैठक लेकर वर्ष 2011–12 का बजट बनाने की दृष्टि से विचार विनिमय किया. संबंधित विभाग की प्राथमिकताओं, आवश्यक प्रस्ताव आदि बातों पर चर्चा की और राज्य के सभी जनसमुदायों को न्याय मिले. इस ध्येय के साथ राज्य का बजट तैयार किया जिसकी झलक उनके द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में पेश अर्थसंकल्प में साफ देखी गई.

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी पूरे प्रदेश में समान वितरण दादा ने किया. स्वास्थ्य संस्थाओं की इमारत निर्माण के लिए 241.95 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान बाबत 166 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष किया. ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स–रे व ईसीजी की सुविधा तथा ग्रामीण अस्पतालों में रक्तदान की सुविधा के लिए 24 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया. राज्य के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के निर्माण व विकास के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराने का फैसला वित्त मंत्री ने लिया. ससून चिकित्सालय, पुणे को 20.50 करोड़ रु., शासकीय महाविद्यालय नांदेड़ को 8.33 करोड़, कैंसर चिकित्सालय को औरंगाबाद 5.43 करोड़, घाटी चिकित्सालय औरंगाबाद 25 करोड़, कस्तूरबा कैंसर हास्पिटल वर्धा को 6 करोड़ रुपये दिए गए. इसी तरह शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर में नये पुस्तकालय की इमारत के लिए 2 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया. सरकारी मेडिकल कॉलेज यवतमाल के भवन निर्माण के लिए शीघ्र निधि उपलब्ध कराई जाएगी.

● **किसानों के हमदर्द** – देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों से दादा का खास लगाव है. इसीलिये किसानों की समस्याओं को प्रधानता देते हुए उनका समाधान करने के लिए दादा हमेशा तत्पर रहते हैं. बेमौसम बारिश हो या फिर, अतिवृष्टि, या फिर अकाल, हर संकट में दादा किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं. किसानों की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति की समस्याओं का दादा ने हल निकाला. इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले कई वर्षों के बाद मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति का टर्नओवर चार गुना बढ़ गया है. किसानों को 50,000 रुपये तक शून्य दर पर कर्ज देने का प्रावधान किया गया. किसानों की आत्महत्याओं के दौरान यह बात मुख्य रूप से सामने आई कि इसके पीछे मुख्य कारण बैंकों का कर्ज और उसका बढ़ता ब्याज है. दादा ने किसानों को दो प्रतिशत की ब्याज दर से तीन लाख रुपये तक ऋण दिए जाने की व्यवस्था भी राज्य में पहली बार की. खरीफ फसल के दौरान समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए खाद को आरक्षित रखने का फैसला किया. किसानों की सुविधा के लिए सस्ते में बिजली उपलब्ध कराने बाबत 2500 करोड़ का प्रावधान किया. कृषि पंपों के विद्युतीकरण का अनुशेष भरने के लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए. कृषि संजीवनी योजना के तहत 22 लाख किसानों का 3000 करोड़ तक का ब्याज और विलंब अधिभार माफ करने की घोषणा की. राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना अंतर्गत मानसून पर निर्भर खेती करने वाले 22 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 4515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. कृषि विपणन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 60 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 745 करोड़ का प्रावधान किया. इसी तरह जवाहर कुओं के लिए 221 करोड़ और फलोत्पादन के लिए 134 करोड़ रुपये दिलाने की घोषणा की. पशु चिकित्सा संस्थाओं के आधुनिकीकरण व मजबूती हेतु 57 करोड़ का प्रावधान बजट में किया. मछलीमार नौकाओं व उनके यंत्रों हेतु 42 करोड़, सिंचाई योजनाओं के लिए 6300 करोड़, जल क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 112 करोड़ प्रावधान किया.

● **एक साल में लोडशेडिंग से मुक्ति** – सरकार ने दिसंबर 2012 तक राज्य को बिजली लोडशेडिंग से मुक्त करने का संकल्प लिया है. दादा ने ऊर्जा मंत्रालय का काम उस समय संभाला जब पूरा राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा है. इस दृष्टि से दादा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में ऊर्जा विभाग उक्त संकल्प को पूरा करने में जोर–शोर से काम कर रहा है. संकल्पपूर्ति की दिशा में किए गए प्रयत्नों का असर राज्य में धीरे–धीरे दिखाई पड़ने लगे हैं. दादा का स्पष्ट मत है कि बिजली भारनियमन से मुक्त होने के बाद राज्य का विकास और तीव्र गति से हो सकेगा. जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित होने में आने वाली अड़चनों को दूर कर प्रकल्प को शीघ्र पूरा कराने के लिए प्रयत्नशील हैं. इस संयंत्र के स्थापित होने से स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न होने देने का वादा दादा ने जनता से किया है. राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 380 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखा जा रहा है. जिन इकाइयों से प्रदूषण फैल रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है. दादा की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि राज्य के कई बड़े शहर लोडशेडिंग से मुक्त हो चुके हैं. निजी क्षेत्रों की कई इकाइयों में जल्द ही बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा.

● **पारंपरिक खेलों से लगाव** – सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी अजीत दादा ने पहल की है. दादा महाराष्ट्र खो–खो और कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. विविध खेल संगठनों के पदाधिकारियों व खिलाड़ियों से मिलकर क्रीड़ा क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा की जिसके आधार पर कई ठोस निर्णय लिए. देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला नियोजन के खाते में कुश्ती और कबड्डी के मैच के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश संबंधितों को दिया है. महाराष्ट्र केसरी खिताब के विजेता पहलवानों के मानधन के संदर्भ में उम्र और आय के नियमों को शिथिल करने का मन दादा ने बनाया है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी, रूस्तम–ए–हिंद और महान भारत केसरी खिताब के विजेता पहलवानों को महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा लागू होनी चाहिए. इसके अलावा शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने की सहूलियत कूपन की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का निर्णय अजीत दादा ने लिया है. विशेषकर स्वर्गीय खाशाबा जाधव कुश्ती प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है. इसी के साथ शिव छत्रपति पदक कबड्डी स्पर्धा और खाशाबा जाधव कुश्ती स्पर्धा के साथ ही स्वर्गीय भाई नेरूरकर पदक खो–खो स्पर्धा के लिए 50 लाख रुपये तक अनुदान बढ़ाने का निर्णय दादा ने वित्तमंत्री होने पर लिया है.

● **माटी से जुड़े संस्कार** – देसी खेलों के विकास के माध्यम से राज्य में खेल, संस्कृति के प्रति लोगों में रुचि जगाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं. मराठी संस्कृति का अविभाज्य अंग है नाट्यकला. नाट्य क्षेत्र के नाट्यकर्मी और परदे के पीछे कार्य करने वाले कलाकारों की समस्या सुलझाने के लिए दादा ने अग्रणी भूमिका निभाई है. मराठी रंगभंव के कलाकारों की बैठक करके उनकी समस्या को समझा और मराठी चित्रपट के निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान के आधार पर नाट्यगृह निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है. प्रत्येक जिले में नाट्यगृह बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने जिला विकास के बजट से निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है. नागपुर के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए एक और नाट्यगृह बनाने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश सांस्कृतिक विभाग को दिया है. विशेषकर रत्नागिरी में अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मराठी नाट्य परिषद को विविध उपक्रमों के लिए शासन की ओर से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा दादा ने की.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunnya.com

महाराष्ट्र हलचल

महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा कृषि दिवस पर पुणे में आयोजित कृषिरत्न पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार प्रदान करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व अन्य

महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन नागपुर में आयोजित स्त्री भ्रूण हत्या विरोध अभियान का आयोजन किया गया. इस अवसर पर महिला सदस्यों द्वारा लगाए गए घरेलू उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन करती हुई महिला व बाल विकास मंत्री वर्ष गायकवाड

महंगाई के विरोध में नागपुर के टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर चूल्हा जलाकर आंदोलन करती भाजपा की महिला कार्यकर्ता

नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में हुए दंगे के दौरान पथराव करती दंगाई भीड़

रसोई गैस, डीजल, केरोसिन के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करती राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता

स्कूल खुले और स्कूल चलें हम.....

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा वितरित तिपहिया साइकिल प्राप्त अपंग बच्चों के साथ केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, नागपुर के पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक, विधायक एस.क्यू जमा, आशीष जायसवाल व जि.प. अध्यक्ष सुरेश भोयर

ब्लडी सिविलियन्स बनाम राजनेता

देश में इन दिनों ब्लडी सिविलियन्स बनाम राजनेता का खेल खेला जा रहा है. अब हमें यह मसला इसलिए कचोट रहा है क्योंकि यह हमारे महाराष्ट्र से जुड़ा है. हमारे महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं. नाम है अन्ना हजारे. वैसे मराठी भाषा में इन्हें अण्णा हजारे लिखा जाता है. इन दिनों अण्णा भाऊ (भाई) देश भर में खासी सुर्खियों में हैं. अब रामदेव बाबा का आंदोलन तो सरकार ने कुचल दिया, ऐसा सरकार को लग रहा है, लेकिन अब हमारे अण्णा नामक जिन्न से वो परेशान है. रोज नए पैंतरे खेले जा रहे हैं. यानी हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कह कर पत्रकारों की बोलती बंद करा दी कि रामदेव के समर्थकों पर आधी रात हुए हमले की जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं. अब उनसे कौन पूछे कि सजा कौन तय करेगा. खैर, बात हमारे अण्णा की हो रही है. जब सरकार की समझ में आ गया कि हमारे अण्णा तो असली मराठी माणुस हैं, किसी बहकावे में आकर कुछ उल्टा–पुल्टा कदम उठाने वाले नहीं हैं तो फिर संसदीय लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया गया है. अब संसद सर्वोपरि का नारा सामने रख कर इस विधेयक को संसद की अनुमति

आख़िर कौन चाहेगा कि यह बिल उस मसौदे के रूप में पास हो जो अण्णा भाऊ की कंपनी चाहती है. चलिए हम आपको बताते हैं कि भाऊ आख़िर चाहते क्या हैं? यह विधेयक जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल द्वारा वेबसाइट पर लोगों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है. इस विधेयक के अनुसार जन लोकपाल संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी.

के लिए सर्वदलीय बैठक बुला ली गई. दो माह की इतनी धमाचौकड़ी के बाद आखिर सरकार को विपक्ष की याद आ ही गई और विपक्ष को भी लाज–शरम तो है नहीं, चले गए बैठक में शामिल होने. अब विधेयक के मसौदे पर मतभेद होना तो लाजिमी है. यह तो आजादी के बाद से लगातार होता आ रहा है. अब वही होगा. माया बहन, मुलायम भाई और कुछ और भाइयों के साथ जया बहन, ममता बहन वगैरह–वगैरह खेल दिखाऐंगे. भाजपा वगैरह–वगैरह वॉकआउट कर जाऐंगे और बिल पास हो जाएगा. आखिर कौन चाहेगा कि यह बिल उस मसौदे के रूप में पास हो जो अण्णा भाऊ की कंपनी चाहती है. चलिए हम आपको बताते हैं कि भाऊ आखिर चाहते क्या हैं? यह विधेयक जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल द्वारा वेबसाइट पर लोगों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार–विमर्श के बाद तैयार किया गया है. इस विधेयक के अनुसार जन लोकपाल संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी. कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा. इस बिल को शांति भूषण, जे.एम. लिंगदोह, किरण बेदी, अन्ना हजारे आदि का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है. सीवीसी, सीवीआई के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एंटी करप्शन विभाग) का लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा. लोकपाल को किसी जज, ठेकेदार, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने व मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था होगी. लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा. इसमें किसी भी नेता की कोई भागीदारी नहीं होगी. इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से, जनता की भागीदारी से होगी. इस बिल की मांग है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किसी भी मामले की जांच एक साल के भीतर पूरी की जाए. जांच एक साल के अन्दर पूरी होगी और दो साल के अंदर–अंदर भ्रष्ट नेता व अधिकारियों को सजा सुनाई जाएगी. इसी के साथ ही भ्रष्टाचारियों का अपराध सिद्ध होते ही सरकार को हुए घाटे की वसूली की जाए. अब ये बात तो हमारे देश के एक बच्चे को भी समझ में आता है कि कोई भी नेता ऐसा बिल संसद में क्यों पास कराना चाहेगा. यह बिल संसद में पास होना यानी नेताओं ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना. अब प्रधानमंत्री आवास पर तीन घंटे चली सर्वदलीय बैठक में एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जो कहता है, सर्वदलीय बैठक में यह सहमति बनी कि सरकार निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संसद के अगले सत्र में एक मजबूत और प्रभावकारी लोकपाल विधेयक पेश करे. इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से पहले ही अण्णा भाऊ की टीम यानी सिविल सोसाइटी यानी ब्लडी सिविलियन्स से बात करने और उनके सुझावों व प्रावधानों को शामिल करने को लेकर सरकार को अन्य दलों के नेताओं ने आड़े हाथों लिया. यह संदेश दे दिया कि देश में कानून की बात सिर्फ राजनेता ही करेंगे. ब्लडी सिविलियन्स नहीं कर सकते. हमारे अण्णा भाऊ प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका और संसद के अंदर सांसदों के आचरण को लोकपाल के दायरे में लाना चाहते हैं. भाई तो इसमें गलत क्या है? किसकी प्राइवेसी खराब हो रही है? जो जवाब इस समय आरटीआई के तहत नहीं मिल पाते, उन्हें मत लाओ दायरे में. हो गई बात खत्म. कुछ शब्दों का हेरफेर कर सब कुछ कन्फ्यूज कर दो. मगर भाई कुछ तो करो. लोकतंत्र में ये सब क्या हो रहा है.....

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunnya.com

चौथी दुनिया
दिल्ली, 18 जुलाई–24 जुलाई 2011

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

डीजे इन रेव पार्टियों की जान होते हैं. इन डीजे की वजह से ही टॉक्सिक इग्ग लेने केबाद नशेड़ी कई घंटे तक नाचते रहते हैं. मॉडल तो इन पार्टियों में अक्सर देखी जाती हैं.

मुंबई-पुणे और अब पूरा देश

रेव पार्टी का मायाजाल

शराब, ड्रग्स के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ना ही होगा सरकार को. अब भी समय है सरकार को चेत जाना होगा. क्योंकि रेव पार्टी अब सिर्फ़ गोवा, पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगड़ तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि इसकी जड़ें अब दिल्ली से एनसीआर और फिर लखनऊ, कानपुर, रायपुर, इंदौर, ग्वालियर, बंगलुरु, नागपुर आदि में भी फैलनी शुरू हो गई हैं. लेकिन अब भी रेव पार्टी के सबसे बड़े गढ़ मुंबई, पुणे, खंडाला जैसे स्थान ही माने जाते हैं.

हाल ही में मुंबई के नजदीक करजत के पास जब समूचे इलाके में रात का सन्नाटा पसरा था, एक होटल ऐसा भी था जहां रेव पार्टी चल रही थी. सन्नाटे को चीरती तेज़ डीजे की आवाज पर थिरकते युवाओं का समूह और इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात थी, एंटी नार्कोटिक्स सेल के एक इंस्पेक्टर अनिल जाधव की उपस्थिति. छापे के दौरान जाधव की गिरफ्तारी से इस बात का खुलासा हो गया है कि नशे के सौदागरों ने एंटी नार्कोटिक्स सेल में सेंध लगा दी है. ख़बर ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए भी थी क्योंकि एंटी नार्कोटिक्स सेल विशेष रूप से नशे के गैरकानूनी धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है. यह अफसोसनाक था कि इसी सेल के एक इंस्पेक्टर की देखरेख में यह रेव पार्टी चल रही थी. इस रेव पार्टी में तकरीबन 300 यंगस्टर्स शामिल थे. इनमें जाने-माने परिवारों की 60 लड़कियों समेत लगभग 280 लड़के थे. मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का बेटा साक्षी खन्ना भी इसमें शरीक बताया जाता है. पुलिस को वहां से 2 किलो गांजा, 57 ग्राम चरस, कोकीन, एमडीएम टेबलेट ऐंड लिक्विड तथा 3 लाख आठ हजार नगद रुपये मिले. यह पहला मामला नहीं है जब किसी रेव पार्टी में छापा पड़ा है. मुंबई और पुणे में रेव पार्टियों का चलन पुराना है. रेव पार्टियों का एक खतरनाक पहलू पिछले साल उस समय सामने आया था जब 4 अगस्त को पुणे के जाने-माने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिम्बॉयसिस के 254 लड़कों और 235 लड़कियों को रेव पार्टी से हिरासत में लिया था. ये रेव पार्टी पुणे-सोलापुर हाईवे पर स्थित एक फॉर्म हाउस में चल रही थी. अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर एक साथ कई गाड़ियों के आवागमन को देख किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया था और पुलिस ने इस पार्टी में छापा मारकर मस्ती में खलल डाल दिया था. बाद में सिम्बायसिस कॉलेज के प्रबंधन ने कार्रवाई, जांच की बात कही और बाद में बात ठंडे बस्ते में चली गई. 4 मार्च 2007 को पुणे के पास खालापुर में चल रही रेव पार्टी पर पुणे पुलिस ने छापा मार कर 3 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए थे. इस रेव पार्टी से 151 युवाओं को हिरासत में लिया गया था जिनमें 27 लड़कियां थीं. ये सभी कॉलेज के थे. 6 अक्टूबर 2008 को मुंबई स्थित जुहू के पब 72 डिग्री ईस्ट में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मार कर 240 युवाओं को हिरासत में लिया. इनमें एक फिल्म स्टार का बेटा और कुछ विदेशी भी थे. यहां से हेरोइन, एलएसडी और कोकीन का जखीरा मिला था. पुलिस ने यहां से आठ ड्रग्स पेडलर को भी पकड़ा था. 27 जून 2009 को मुंबई लोखंडवाला में पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें दो गुजरात के व्यापारी और सात कॉलगर्ल और एक हाई प्रोफाइल मॉडल भी थी. पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब, कंडोम के पैकेट और 40 हजार रुपये नगदी बरामद की थी.

गौर करने वाली बात यह है कि क्रिकेट के बुकी या फिर गलत धंधा कर पैसा कमाने वालों का रेव पार्टी में शामिल होना या गुलछर्रे उड़ाना तो समझ में आता है लेकिन अब मध्यमवर्गीय समाज का युवा वर्ग इस रेव पार्टी की गिरफ्त में आता जा रहा है. आखिर उसके पास इतने पैसे आते कहां से हैं कि वह महंगे ड्रग्स का सेवन इन रेव पार्टियों में कर सके? मामला साफ है, पहले ये पार्टियां रईसजादों का शगल हुआ करती थीं, उनमें सेक्स की भी उन्मुक्तता थी. लेकिन अब नशे के साथ सेक्स को जोड़ दिया गया है. मध्य वर्ग की लड़कियां और लड़के इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं. क्योंकि वैश्विक बाजार व्यवस्था के साथ उपहार में मिली जीवन शैली के उन्हें घर से मिलने वाली राख खर्च करने के लिए कम पड़ती है. इसलिए अतिरिक्त धन कमाने के लिए पहले सेक्स और फिर नशे की गिरफ्त में आना इनके लिए बड़ी बात नहीं है. रेव पार्टी का मतलब ही है मौज मस्ती की पार्टी. कहते हैं कि रेव पार्टी में भाग लेने वाले बड़े घाघ किस्म के होते हैं. पार्टी के बारे में वे सर्किट के बाहर के लोगों को जरा भी भनक नहीं लगने देते. एसएमएस की सूचना भेज दी जाती है. रेव पार्टी के नौसिखियों से समस्या यह है कि ये कभी-कभी इंफार्मेशन लीक कर देते हैं और मस्ती में पुलिस का खलल पड़ जाता है.

अब दूसरा पहलू- नशे और सेक्स के इस घालमेल ने रेव पार्टी की सूरत के साथ ही उसकी सीरत भी बदल दी है. पहले यह खुले में होता था अब छिपकर होने लगा है. नशीले पदार्थ बेचने वालों के लिए ये रेव पार्टियां धंधे की सबसे मुफीद जगह बन गई हैं. यही कारण है कि मुंबई-पुणे से दूर किसी ऐसे स्थान पर इन पार्टियों का आयोजन होता है जहां लोगों की आवाजाही आमतौर पर कम होती है. डीजे इन रेव पार्टियों की जान होते हैं. इन डीजे की वजह से ही टाक्सिक ड्रग्ग लेने के बाद नशेड़ी कई घंटे तक नाचते रहते हैं. मॉडल तो इन पार्टियों में अक्सर देखी जाती हैं. हम भले ही लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या में कमी होने का रोना रोते हों लेकिन इन रेव पार्टियों के मामले में लड़कियों ने लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है. सौ नशेड़ियों में लड़कियों की संख्या 60 होती ही है. महानगरों के युवकों का रेव के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है. अब रेव का मतलब डांस में डोपिंग यानी नशे का सेवन और सेक्स होता जा रहा है. बिना ड्रग्स (एसिड व इक्सटैसी) लिए वे लगातार 8 घंटे साइकेडेलिक ट्रांस म्यूजिक पर थिरक ही नहीं सकते. कुछ तो है कि जो उनमें लगातार नाचने का जुनून पैदा करते हैं. जिनके पास पैसे होते हैं वे एसिड व इक्सटेसी जैसे महंगे ड्रग्स लेते हैं. जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, जिन्हें अपनी बजट भी देखनी होती है वे वे श्रूम्स (मशरूम), हशीश या गांजा से ही काम चला लेते हैं. इसमें भाग लेने वाले बिंदास युवकों के लिए सेक्स और प्यार की नैतिकता कोई मायने नहीं रखती.

दरअसल मध्यमवर्गीय परिवार के युवाओं को सीधे-सीधे देह व्यापार और नशे की दुनिया की ओर खींचने के लिए अखबारों में भी फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर हजारों रुपए कमाने जैसे विज्ञापन दिए जाते हैं. वैसे भी आज की युवा पीढ़ी को शार्टकट तरीका बखूबी भाता है. ये क्लब रेव पार्टियों में युवक-युवतियों की भीड़ जुटाने के लिए भी कई बार ऐसे विज्ञापन देते हैं. वो जमाना हुआ करता था जब यह अमीरों का शगल हुआ करता था लेकिन अब तो यह अमीर और मध्यमवर्गीय के बीच का पुल बन गया है. बड़े शहरों में छापे मारे जाते हैं. गिरफ्त में आते हैं ये बेगुनाह युवक-युवतियां और असली अपराधी तो पकड़ में ही नहीं आते. घर से दूर रह कर पढ़ाई कर रहे युवा एक बार इनके जाल में फंस जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है. गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम आदि का बेखौफ इस्तेमाल, समाज में सेक्स की बदलती परिभाषा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, काले धन का दुष्प्रभाव जैसे कई कारण हैं जो इस प्रचलन को बढ़ावा दे रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पार्टी के बारे में वे सर्किट के बाहर के लोगों को ज़रा भी भनक नहीं लगने देते. एसएमएस की सूचना भेज दी जाती है. रेव पार्टी के नौसिखियों से समस्या यह है कि ये कभी-कभी इंफार्मेशन लीक कर देते हैं और मस्ती में पुलिस का खलल पड़ जाता है.

वर्ल्ड क्लॉस टॉउनशिप, सर्टिफाईड इन्वेस्टमेंट, ग्यारन्टेड रिटर्न्स!

The Palm City

'द पाम सिटी' दिपावली 2013 उपरांत भव्य रंगारंग
कार्यक्रम द्वारा फेज I का पजेशन दिया जाना तय हैं। इस 30 माह की
अवधि में समय समय पर होनेवाली मूल्यवृध्दि के कारण
पजेशन के समय 'द पाम सिटी' के दाम रु.3000/- प्रति वर्ग फुट से ज्यादा रहेगें।

जरा सोचें, आपका फायदा निर्णय आज लेने में है या निर्णय कल लेने में

दि.5 जुलाई से 2250/-

आपका निर्णय आपकी विजय

Ashtavinayak EMPIRE
आपकी खुशियों के सह-निर्माता

MODERN AMENITIES
- Approach Road Palm Street
- Palm Square 10,000 Ft. with large Fountain
- 6.50 Lac Sq.ft. Green Zone
- Mini Theater
- 3 Swimming Pool
- 2 Mini Cricket Ground
- Township Area 33 Acre
- Road Sizes 45 & 30 Ft.
- Grand Entrance
- Club House with All Modern Facilties
- School CBSE Pattern
- Proposed Hospital
- Palm Commercial Plaza
- Door Step Bus Facility
- Rain Water Harvesting
- Sewage & water Treatment Plant

START FROM Rs. 11,70,000/-*

कॉरपोरेट ऑफिसः पांचवा माला,लक्ष्मीसदा अपार्टमेंटस्, साई मंदिर के पास छत्रपती चौक, वर्धा रोड, नागपुर

Note: This advertisement is only a conceptual presentation of the project & not a legal offering. "Condition.

20% मार्जिन मनी 80% बैंक लोन
मार्जिन मनी का भुगतान
दो माह में दो किश्तों में

Akruti Advt.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 18 जुलाई-24 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

सरकार और राजभवन की लड़ाई में

उच्च शिक्षा का बंटाधार

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

दुनिया भर में शिक्षा की अलख जगाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बुलंदी तक ले जाने की कवायद इन दिनों बिहार में तेज़ हो गई है. बैठकों का दौर जारी है और नालंदा में विशेषज्ञों का जमावड़ा लग रहा है. लेकिन इस असरदार पहल के बीच एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि सूबे में उच्च शिक्षा अराजकता के दौर से गुज़र रही है.

विश्वविद्यालय महीनों से बिना कुलपतियों के हैं और पठन पाठन से लेकर सारे काम भगवान भरोसे हैं. छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ राजभवन और सरकार के बीच अंह की लड़ाई के कारण हो रहा है. नीतीश कुमार व राज्यपाल देवानंद कुंवर के बीच कई मुलाकातों का भी कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है. आख़िरकार हाईकोर्ट ने दखल देते हुए कुलपतियों की स्थायी नियुक्ति नहीं किए जाने पर कुलाधिपति सह राज्यपाल को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से बताने को कहा है कि स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति में कैसी बाधा आ रही है. कोर्ट को एक लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों एवं शिक्षकों का भविष्य दांव पर लग गया है. जबकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने दलील दी कि वीसी नियुक्ति में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है. मानव संसाधन मंत्री द्वारा एक दर्जन पूर्णकालिक चयनित शिक्षकों की सूची भेजी गई है पर कुलाधिपति समय नहीं दे पा रहे हैं. कोर्ट से बाहर की बात की जाए तो यह अब साफ हो गया कि कुछ नाम को सरकार नहीं चाहती है और कुछ नामों को कुलाधिपति नहीं चाहते हैं. अहं की इस लड़ाई के कारण सूबे के सभी विश्वविद्यालय पंगु होकर रह गए हैं. सूत्र बताते हैं कि छपरा व मगध विश्वविद्यालय को लेकर ज्यादा परेशानी आ रही है. इन विश्वविद्यालयों के वीसी के नाम कई बार भेजे गए पर कुलाधिपति को यह नहीं भाया. नतीजतन अब कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है. वास्तव में विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वह शिक्षा का मंदिर न होकर उहापोह और अराजकता का केंद्र बिंदु हो गए हैं. तथागत की तपोभूमि में स्थित मगध विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा अराजक स्थित में है. इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था और कार्य संस्कृति एक तरह से खत्म हो चुकी है. कुलपति के न रहने से शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य पूरी तरह चरमरा गए हैं. इसका सबसे बडा खामियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है. समय से पार्ट वन और एमए की परीक्षाएं नहीं हो पाईं दूसरी ओर पार्ट टू और पार्ट थ्री की परीक्षाओं के बाद उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समय से नहीं हो पाया. इस विश्वविद्यालय से विभिन्न विषयों में पास करने वाले छात्र-छात्राओं को डिग्रियां नहीं मिल पाईं. मगध विश्वविद्यालय के कुल 44 अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन की आवांटित राशि आने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हो सका. सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व से निर्धारित कुलपति से अनुमति के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को बैंक से ऋण लेने कि ज़रूरत पड़ी क्योंकि इन परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण परीक्षा विभाग ने तत्कालीन कुलपति अरविंद कुमार से अनुमति लेकर की थी. लेकिन परीक्षा की तारीख़ निकट आने के पूर्व ही अरविंद कुमार को पटना हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया. जिसके कारण क़रीब 42 दिनों तक मगध विश्वविद्यालय में सारे कार्य पूरी तरह बाधित रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह के वित्तीय कार्य और अन्य सभी तरह के कार्यों के लिये कुलपति की अनुमति अनिवार्य होती है. 42 दिनों के बाद कुलाधिपति द्वारा प्रभारी कुलपति बनाए जाने के बाद इस विश्वविद्यालय के कार्यों में कुछ गति आई. लेकिन जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है. कुलपतियों के न रहने से सभी विश्वविद्यालयों में शोध कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ. सभी जगह कोई शोध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए भी वीसी की अनुमति ज़रूरी है. कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति भी नहीं हो पा रही है.

मणि कहते हैं कि अगर यह मान भी लिया जाए कि कुलपति के मामले में राज्यपाल की तरफ़ से अड़चन है तो सरकार यह तो बताए कि उसकी तरफ़ से जो नियुक्तियां हुई हैं, उनका क्या मापदंड है.

विधान पार्षद प्रेमकुमार मणि कहते हैं कि पहले से ही गर्त में चली गई सूबे की शिक्षा व्यवस्था नीतीश राज में और भी गर्त में चली गई. लालू राज में तो 1996 और 2003 में विश्वविद्यालयों में बहाली हुई पर इस सरकार में पिछले छह सालों में एक भी विश्वविद्यालय शिक्षक की बहाली नहीं हुई पर ग़ैर शैक्षणिक कार्यों के लिए बहाली का अंबार लग गया है. मणि ने कहा कि अगर राज्यपाल से कोई दिक्कत है तो सरकार या पार्टी उन्हें हटाने की आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रही है. विशेष राज्य पर बेवजह चिल्लाया जा रहा है लेकिन राज्यपाल को बदलने पर चुप्पी है. मणि कहते हैं कि अगर यह मान भी लिया जाए कि कुलपति के मामले में राज्यपाल की तरफ से अड़चन है तो सरकार यह तो बताए कि उनकी तरफ से जो नियुक्तियां हुई हैं, उसका क्या मापदंड है. राष्ट्रभाषा परिषद का अध्यक्ष 90 साल से ज्यादा उम्र के रामबुझावन सिंह को बनाया गया. संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश्वर सिंह को बनाया गया, जिनके संस्कृत ज्ञान से सभी अवगत हैं. उन्होंने कहा कि एक वकील को शिक्षा मंत्री बनाकर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं, यह समझ से परे है. मणि का आरोप है कि सरकार ने न केवल उच्च शिक्षा बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती. साफ़ कहें तो शिक्षा के मामले में यह सरकार दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली की दौड़ लगा रही है.

विधान पार्षद नवल यादव कहते हैं कि अगर उच्च शिक्षा बदहाल है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. सरकार की ग़लत नीतियों को वह इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं. यादव कहते हैं कि उच्च शिक्षा के साथ प्रयोग की परंपरा ने सब चौपट करके रख दिया. अनावश्यक प्रयोग के पीछे नवल यादव का तर्क है कि सूबे के विश्वविद्यालयों में किसी बड़े नेता व अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे में अगर सारी व्यवस्था चौपट हो जाए तो उन्हें क्या फ़र्क़ पड़ता है. ग़रीब घर के बच्चों के भविष्य से ऐसे नेताओं व अफसरों का कुछ लेना देना नहीं है. महीनों से कुलपतियों के पद खाली पड़े हैं. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है. हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन महीने के अंदर खाली पड़े पदों को भरने को कहा है. दूसरी तरफ़ विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह कहते हैं कि राजभवन कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं है. सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसका असर पठन पाठन व प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है. कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति इतनी भयावह है कि अगर हालात जल्द न सुधरे तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

Ph:0612-3296829, 9334252869, 9386941721

Approved by Govt. of India ... The Way to Grow

SKY CONSULTANCY SERVICE PVT. LTD

DIRECT & CONFIRM ADMISSION

Contact : 604, 6th Floor LUV-Kush Tower Exhibition Road, Patna-1

Ph: 0612-3296829
9334252869
9386941721

2010 Admission Report

Engineering | MBA/PGDBM | MBBS | MCA | B.Ed

B.Pharma | Polytechnic | BBA | ITI

Branch: Yadav Market, Near Circut House Pakri Chowk Ara,
Mob;9798662051, 9334006756, Muzaffarpur Chhapra

Email : consultancy.sky.patna@gmail.com

Our Copration with you from 2001 to 2011

SCSPL

अगर रेल प्रशासन नदी के कटाव को रोकने में अंकुश नहीं लगा पाया तो यह रेल खंड भी लंबे समय तक के लिए बंद हो जाएगा.

प्रत्येक साल बाढ़ से जान-माल की तबाही मचाने वाली इस नदी में मुख्य धारा के अलावा एक नई धारा का निर्माण हो गया है, जिससे बाढ़ का पानी का नए इलाके में फैल सकता है.

एक नज़र

पटना में ट्रॉमा सेंटर पल्स की शुरुआत

पटना के राजेंद्र नगर स्थित दिनकर चौक के निकट आईसीयू एवं ट्रॉमा सेंटर-पल्स का उद्घाटन पीएमसीएच के निश्चेतना विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. (प्रो.) हरिनन्दन प्रसाद ने किया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यहां सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, ऐसे में यहां अत्याधुनिक आईसीयू एंड ट्रॉमा सेन्टर की कमी महसूस की जा रही थी. पल्स एंड ट्रॉमा सेन्टर के उद्घाटन के बाद राज्यवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी. पोस्ट को-ऑपरेटिव आईसीयू का उद्घाटन डॉ. वरूण कुमार सिन्हा (यूरोलॉजिस्ट), राष्ट्रीय अध्यक्ष एएसआई द्वारा किया गया. जबकि एनसीआईसीयू का उद्घाटन प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. गोपाल प्रसाद ने किया. इस अवसर पर उपस्थित महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह, पीएमसीएच में ईएनटी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वृजलाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एचएन दिवाकर, ऑन्कोसर्जन डॉ.वी.पी. सिंह एवं अन्य चिकित्सकों ने इसे एक बेहतरीन प्रयास बताया. – *चौथी दुनिया ब्यूरो*

अररिया में अन्याय नहीं होने देंगे : रंजीत

भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य सरकार को भजनपुर गांव की बेहतरी व ग्रामीणों की तरक्की के लिए गांव को गोद लेने का अनुरोध करेंगें. शाहनवाज के बेहद करीबी युवा नेता रंजीत यादव ने इस पर कहा कि शाहनवाज हुसैन का प्रयास कभी असफल नहीं होता है. रंजीत यादव ने कहा कि भजनपुर की घटना पर हुसैन ने राजनीतिक मरहम नहीं बल्कि भावनात्मक मरहम लगाकर दर्द को कम करने का सकारात्मक प्रयास किया है. इस प्रयास से ही फारबिसगंज के गांव भजनपुर में शांति व सौहार्द कायम करने की दिशा में मदद मिली है. रंजीत यादव ने कहा कि अररिया जिले में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. अगर कहीं से ऐसी कोई शिकायत आती है तो मैं अररिया से लेकर पटना तक संघर्ष करूंगा. उन्होंने दावा किया कि भजनपुर के लोगों को जल्दी ही न्याय मिलेगा. – *एस सोनी*

विधि व्यवस्था पहली प्राथमिकता : सुनील

पूर्णिया सदर थाने में पदास्थापित थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने दुरूस्त विधि व्यवस्था को अपना मिशन बनाया है. 1994 बैच के कर्मठ, तेज तर्रार, कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ सुनील कुमार सिंह के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके कार्यकाल में जहां विधि व्यवस्था दुरूस्त हुई है, वहीं थानेदार एवं जनता के बीच संवाद के माध्यम से थाना एवं जनता के बीच दूरी भी घटी है. मालूम हो कि पुलिस की नौकरी में इन्हें विशिष्ट पदक मिल चुके हैं. सदर थाना में रहते इन्होंने नकली खाद, नकली कीट नाशक, नकली सरसों तेल एवं बर्मा सेल के पाईप लाइन से तेल निकालते पेट्रोलियम माफिया को रंगे हाथों पकड़ा. इसके पूर्व कटिहार के कई थानों जैसे मनिहारी, टाउन थाना में क्राइम कंट्रोल विधि व्यवस्था के मामले में इनका कार्य सराहनीय रहा है. सुनील कुमार सिंह का कहना है कि ज़िले के पुलिस कप्तान के आदेश का पालन करना इनके लिए सर्वोपरि है. इन्ही के निर्देशानुसार वे जनता के हित में विधि व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं. – *नीरज कुमार सिंह*

कोसी: कहीं क़ब्रगाह न बन जाए

मनोज ठाकुर

अगस्त 2008 में कुशहा बांध टूटने से आई तबाही से सहमे-सिहरे कोसी प्रमंडल के लोग मात्र तीन वर्षों के भीतर ही फिर से रतजगा करने को विवश हैं. हो भी क्यों न? कोसी नदी अपने ऊपर बने तटबंध जो नेपाल से 32 किमी और कोसी प्रमंडल में 125 किमी की दूरी तय करता है, के कई बिंदुओं पर ख़तरनाक दबाव डाल रही है. नदी तटबंध से मात्र 5 मीटर की दूरी पर बह रही है. ऐसे में तटबंध के बाहर रहने वाली लाखों की आबादी भला रतजगा न करे तो क्या करे. वहीं सरकारी दावे की बात करें तो सरकार कुशहा टूटने से पूर्व दिए गए आश्वासन से भी बड़े आश्वासन की घुट्टी पिला रही है. जलस्तर के लगातार बढ़ने से सुनसरी (नेपाल) के प्रकाशपुर राजा बांध समेत पूर्वोत्तर बांध के कई स्तर बह जाने से पानी का दबाव मुख्य बांध पर आ गया है. नेपाल के गृह सचिव लीलामणी पौडेल ने भी तटबंधों का दौरा कर इसे संवेदनशील घोषित कर रखा है. वहीं सुनसरी के डीएम एम चुनमणी पौडेल ने बांध पर भारतीय ठेकेदार व कामगरों को कटाव रोकने के काम में तेज़ी लाने का निर्देश भी जारी कर रखा है. वहीं भारतीय तटबंध के सीमावर्ती क्षेत्र के लाखों लोग बाढ़ की संभावना और बांध के टूटने को लेकर चिंतित ही नहीं हो रहे बल्कि खौफ भरी जिन्दगी जीने को मजबूर भी हो रहे हैं. इनकी चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है. अगर कहीं तटबंध टूटता है तो वे कोसी क्षेत्र से भाग भी नहीं पाएंगे! कोसी क्षेत्र से बाहर निकलने के सभी मार्ग जिसमें से अधिकांश मार्ग या तो अवरुद्ध हैं या भारी वर्षा में अवरुद्ध हो जाने के कगार पर हैं.

डूमरी पुल ध्वस्त है. डूमरी पर बना स्टील पाइल पीपा पुल भी बंद नहीं होने जा रहा बल्कि नदी इसे अपने में समाने भी जा रही है. मतलब 17 करोड़ की लागत से बना पुल 17 दिन भी काम नहीं आया. चौथी दुनिया ने पुल बनने से पूर्व ही इस घटना से आगाह कर दिया था. वहीं सहरसा-पूर्णिया सड़क मार्ग पर मुरलीगंज के समीप 2008 के बाढ़ में ध्वस्त बलुआहा घाट पुल नहीं बन पाया है और पुल के समीप बना एप्रोच पथ (डायवर्सन) लगातार बारिश व नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में जल में प्लावित हो कर अवरुद्ध हो सकता है. अब प्रमंडल से बाहर निकलने का एक मात्र रेल खण्ड सहरसा-मानसी रेल खण्ड है. इस रेल खण्ड के बदला और धमाहरा स्टेशनों के बीच पुल नं. 51 के पिलर 4 व पिलर 5 के नीचे बागमती नदी का कहर जारी है. इन पायों के नीचे हो रहे कटाव से मिट्टी खिसक रही है. जिससे रेल प्रशासन ने फिलहाल ट्रेनों की गति कम करने (30 किमी/घंटा) की हिदायत दे रखी है. हालांकि पायों को बचाने के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर पायों के नीचे बोल्डर डाल रही है. लेकिन अगर रेल प्रशासन नदी के कटाव को रोकने में अंकुश नहीं लगा पाया तो यह रेल खंड भी लम्बे समय तक के लिए बन्द हो जाएगा. ऐसे में कोसी के 80 लाख लोग बाढ़ के आने पर यहां से बाहर किस मार्ग से अपनी जान बचा पाएंगे. ये चर्चा का विषय बना हुआ है. सुपौल ज़िले के वीरपुर से सहरसा ज़िले के अंतिम छोर तक के 125 किमी लम्बे तटबंध के विभिन्न बिन्दुओं की स्थिति जहां कोसी तटबंध को तोड़ने का प्रयास कर रही है. कोसी जुलाई के पहले सप्ताह में ही अपने उफान पर है. कोसी का डिस्चार्ज 1.50 लाख क्यूसेक को पार करने वाला है. याद करें वर्ष 2008 में कुशहा का बांध 1.65 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज में ही अगस्त के दूसरे सप्ताह में टूट गया था. मतलब वह आंकड़ा भी जल्द ही निकट आने वाला है. जल संसाधन विभाग कोसी की महत्वपूर्ण समस्या इसके तलहट्टी में जमी गाद व बालू है, जिसे निकालने का एक मात्र साधन ड्रेजर मशीन है. जो 1970 के दशक के बाद वीरपुर को दी गई थी. दोनों ड्रेजर मशीन असैन्य प्रमंडल द्वारा संचालित होती है. 1 जुलाई को 1 ड्रेजर मशीन नदी में बह गयी. अब ड्रेजर मशीन के बहने का कारण भी जान लें. ड्रेजर मशीन के काम करने की क्षमता 50 हजार क्यूसेक जल निकासी में ही संभव है. लेकिन विभाग ने इसे उस वक्त काम पर लगाया जब जल डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से अधिक था. मतलब जानबूझ कर ड्रेजर मशीन को कोसी में समाने को छोड़ दिया गया. अब गाद और बालू की सफाई कैसे हो पायेगी. यह समस्या सबके सामने है.

कोसी क्षेत्र से बाहर निकलने के सभी मार्ग जिसमें से अधिकांश मार्ग या तो अवरुद्ध हैं या भारी वर्षा में अवरुद्ध हो जाने के कगार पर हैं. डुमरी पुल ध्वस्त है. डुमरी पर बना स्टील पाइप पीपा पूल भी बंद नहीं हो रहा है, बल्कि नदी इसे अपने में समाने भी जा रही है. मतलब 17 करोड़ की लागत से बना पुल 17 दिन भी काम नहीं आया.

नव निर्मित पूर्वी तटबंधों की सुरक्षा के लिए अब इन पर घास रोपने का काम किया जा रहा है. यह घास तुरन्त इतनी सख्त नहीं होने जा रही है जो तटबंध को सुरक्षित रख सके और न ही यह तटबंधों में बारिश के समय होने वाली दरारों को रोकने में सक्षम हो पाएगी. मतलब हर स्तर पर व्याप्त है लापरवाही और सरकार कर रही है तटबंधों को पूर्ण सुरक्षित होने का दावा. आगे जो भी हो लेकिन कोसी के लाखों लोग अब कोसी मैय्या की शरण में हैं और उनके शांत रहने की पूजा अर्चना भी करते नज़र आ रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चेक पोस्ट के लिए अवैध उत्खनन

नीरज कुमार सिंह

महानंदा नदी के बालू-मिट्टी के अवैध उत्खनन से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है. यह अवैध काम चेक पोस्ट के निर्माण के लिए किया जा रहा है. बिहार में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में निर्माण सामग्री हेतु सरकार द्वारा प्राक्कलन की दर निर्धारित है और सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है. ऐसे में अगर कोई कार्यकारी एजेंसी सरकारी एवं सार्वजनिक जैसे कि वस्तुओं को बिना सरकार से या विभागीय अनुमति लिए निर्माण संबंधी कार्यों में उपयोग करती है तो यह कानून अपराध माना जाएगा. पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में महानंदा नदी के किनारे एनएच 31 पर डंगराहा में बनाये जा रहे सरकारी चेक पोस्ट में इसी तरह का मामला उजागर हुआ है. 30 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता के द्वारा निगरानी रखी गई. यह कार्य विनोद अग्रवाल की कम्पनी कोमेक प्रा. लि., सिल्लीगुड़ी को मिला. कोमेक द्वारा इस प्रोजेक्ट में विगत लगभग 4 वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है और वर्तमान में भी निर्माण संबंधी कार्य जारी है.

यहां पर निर्माण कार्य में लगी कोमेक प्रा. लि. द्वारा महानंदा नदी के बालू-मिट्टी का अवैध रूप से उत्खनन जेसीबी मशीन लगाकर किया जा रहा है. इस बालू और मिट्टी का उपयोग चेक-पोस्ट निर्माण स्थल की भूमि को भरने के लिए किया गया है. इस वजह से प्रत्येक साल बाढ़ से जान-माल की तबाही मचाने वाली इस नदी में अवैध रूप से बांध नुमा ढांचा का निर्माण हो गया है, जिससे बाढ़ का पानी का नया इलाके में फैलने का भय बना गया है और बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाये जा रहे बांध पर भी खतरा बढ़ गया है. महानंदा भयंकर बाढ़ लाने के लिए चर्चित है. मालूम हो कि प्रत्येक साल महानंदा में भयंकर बाढ़ आती है जिससे पूर्णिया जिले के वायसी अनुमंडल, किशनगंज एवं कटिहार जिले में व्यापक पैमाने पर फसल एवं जानमाल की हानि होती है. इस बाढ़ की रोकथाम के लिए बिहार सरकार स्थायी निदान खोज रही है एवं प्रत्येक साल सरकार की तरफ से टूटी बांधों की मरम्मत भी कराई जाती है. महत्वपूर्ण बात यह है कि महानन्दा बिहार एवं बंगाल की सटी सीमा से होकर बहती है और बंगाल नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने के बाद इसका सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र बिहार में पड़ता है. महानन्दा के बालू मिट्टी के अवैध उत्खनन का उपयोग निचली सतह की भूमि को भरने में किया जा रहा है क्योंकि बंगाल में उपजाऊ भूमि की मिट्टी महंगे दामों में मिलती है साथ ही उपभोक्ताओं को पर क्यू. एफ. के हिसाब से खनन रॉयल्टी भी सरकार को देनी पड़ती है. महानंदा के बालू मिट्टी के अवैध उत्खनन के बारे में पूर्णिया स्थित खनन विभाग के पदाधिकारी कपूरी तांती का कहना है कि कोमेक प्राइवेट लिमिटेड से खनन राजस्व की राशि उच्चपथ प्रमंडल के माध्यम से ली जाती है. जहां तक मिट्टी बालू नदी से काटने की बात है इसके लिए कार्य करने वाले ऐजेंसी को सरकार से इकरारनामा के बाद ही मिट्टी को काटना चाहिए. बिना सरकारी इकरारनामा के नदी से मिट्टी काटना पूर्णतः अवैध है. इस संबंध में समुचित जांच करके कार्य करने वाली एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार का कहना है कि चेक पोस्ट निर्माण में लगी कार्यकारी ऐजेंसी को निर्माण स्थल में मिट्टी भराई के लिए प्राक्कलन राशि 136 रुपया प्रति क्यू. एम. के हिसाब से दिया जा रहा है. यह मिट्टी किसी निजी व्यक्ति की भूमि को लीज पर लेकर काटना है. निर्माण कार्य में लगी ऐजेंसी के संवेदक विनोद अग्रवाल का कहना है कि मैं बिहार में विकास संबंधी कार्य हेतु चेक पोस्ट का निर्माण कर रहा हूं.

अगर महानंदा की बालू-मिट्टी का उपयोग चेक पोस्ट स्थल को भरने के लिए किया गया तो इसमें हर्ज ही क्या है. जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास महानंदा से बालू-मिट्टी काटने का प्रशासन से मिला कोई अनुमति पत्र या इकरारनामा है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. पूर्णिया के जिला पदाधिकारी डॉ. एन. सरवन कुमार का कहना है कि मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो ऐजेंसी के विरुद्ध जांच करवा कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

महानंदा के बालू मिट्टी के अवैध उत्खनन का उपयोग निचली सतह की भूमि को भरने में किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में उपजाऊ भूमि की मिट्टी महंगे दामों में मिलती है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

बरूआ से आभा सिंह ने परचम लहराया

दिघवारा सारण में इस बार पंचायत चुनाव के हुए घमासान में काफी कशमकश की स्थिति रही और इसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं. मुखिया पद के लिए हुए चुनाव में आभा सिंह बरूआ से भारी मतों से विजयी हुयी वहीं उन्होने सुनीता देवी को हराया. रामपुरआमी क्षेत्र से मुखिया पद के लिए राकेश सिंह जीते, जिन्होंने चंकी सिंह को हराया दूसरी ओर झौआ से चमेल्या देवी ने मंजू देवी को हराया. हराजी से मुखिया पद के लिए मो.शमेशर आलम ने भोला साह को भारी मतों से हराया. मानपुर से मुखिया पद के लिए संजीत कुमार सिंह ने अखिलेश कुमार सिंह को हराया. शीतलपुर से गायत्री देवी जीती, बस्तीजलाल से विपिन सिंह ने उदय सिंह को, कुरैया से राजू राम ने शकलदीप राम को, त्रिलोक चक से गुड्डेश्वर प्रसाद सिंह ने उमेश राय को हराया. दूसरी ओर बीडीसी पद के लिए हुए चुनाव में शीतलपुर से मोहम्मद कलीम विजयी हुए. रामपुरआमी से भाग 4 के लिए रितेश कुमार सिंह ने विनोद सिंह को हराया वहीं जनार्दन सिंह चौहान विजयी हुए. – *चौथी दुनिया ब्यूरो*

ऑडिट में रितेश मिश्रा पर उंगली उठी

नगर पंचायत के द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत कराए गए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम मे वित्तीय अनियमितता का ममाला अंकेक्षण (ऑडिट) के दौरान प्रकाश में आने के पश्चात पेशे से कम्प्यूटर शिक्षण व संस्थान निदेशक रितेश मिश्रा के इर्द गिर्द मामला आकर रूक चुका है. लेखा परीक्षा दल ने इसकी जांच की भी अनुशंसा की है. उधर रितेश मिश्रा ने बताया कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ठेका सर्च संस्था ने लिया तथा मेरे यहां अभ्यर्थियों ने क्लास व प्रैक्टिल किया. मुझे सर्च ने चेक प्राप्त करने को अधिकृत किया था एवं मैने चेक प्राप्त किया. अवधि कम होने या कोई अन्य मामलों में नगर पंचायत प्रशासन समझे और संस्था समझे मुझे कोई मतलब नहीं है. वॉर्ड आयुक्त संतोष राय, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्र समेत कई लोगों ने इस ऑडिट को झूठ का पुलिन्दा एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है. – *अंजुम परवेज़*

SRI TRIVENI DEVELOPERS PVT. LTD.
एक विश्वास
Upcoming Projects: Triveni Hills, Pundag (More than 1000 Flats, Duplexes, Bungalows)
Exciting Facilities: School, Garden, Grossy Shop, Playground, Marriage Hall
Shri Akhilesh Pandey, Managing Director
85% Home Loan Available on Easy Terms
Trivenipuram: A complete township of more than 900 Flats 0.5 Km from Boty more
Our Complete Projects (Recently): Trivenipuram Booty Road, Shanti Enclave, Opp. Ashok Nagar, Banwari Complex, Shardhanand Road, Brindavan Apartment, Morabadi
Our Projects Underway: Raj Keshri Enclave, Pundag, Ranchi; Triveni City, Namkum Ranchi; Triveni Enclave, Dhanbad; Keshri Tower, Jamshedpur
office : Divine House, Club Road, Ranchi-8340011
Tel No. : 0651-2331860, 3207559, 9334463783, 9334712019, 9304448872, E-mail : sritriveni@gmail.com

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण, कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें
दि कोशी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय - साहू मार्केट, गांधी पथ सहरसा
फोन - 06478-224163, मुंबई - 9709695125, राज्य - 9128668231, मोब - 9431864426

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
1 YEAR WARRANTY
NATURE
Mfd. By: CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES

BALMUKUND SUPER
TMT ही नहीं SUPER TMT
EXTRA STRONG-ECONOMICAL-CORROSION RESISTANT-FIRE RESISTANT

करियर दुनिया

फायर सेफ्टी मैनजमेंट में भी है भविष्य

ललन कुमार

रोजगार युवाओं के लिए पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फॉयर सेटी मैनजमेंट रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर सूबे में अपनी छंटा बिखेर रहा है. इंस्टीच्यूट के निदेशक ललन कुमार प्रसाद के अनुसार बोरोजगार युवा वर्ग के लिए यह एक ऐसा क्षेत्र बनकर इभर रहा है जहां पर कम खर्च में लोग जॉब पाकर अपनी जिंदगी के सुनहरे भविष्य तलाश कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि यह बिहार का नहीं बल्कि इंडिया लेबल पर एक ऐसा इंस्टीच्यूट है जहां पर छात्रों को फॉयर बिग्रेड के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपदा से निबटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. जब इनसे पूछा गया कि आपके मन में कब ऐसा महसूस हुआ कि बिहार में इस तरह के इंस्टीच्यूट की स्थापना करना आवश्यक है तो इन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहस पर चर्चा करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था अगर बिहार को कोई नाश कर सकता है तो वह आग और पानी है. इन्होंने इत्तर बिहार के मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार आदि जिलों की चर्चा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के लोग बाढ़ की समस्या से गरीब का वह दंश झेल रहे है जहां पर इनके रहने के लिए अपना एक पक्का मकान तक नहीं है और इन क्षेत्रों में फूस की झोपड़ी होने के कारण अगलगी की समस्या सबसे ज्यादा हुआ करती है. जिससे यहां पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये का नुकसान होता है. मैं इन्हीं सब कारणों से वर्ष 2000 ई.आशियाना ग्लेक्सी में पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फॉयर सेटी मनेजमेंट इंस्टीच्यूट की स्थापना की. इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में छात्राओं का भविष्य इज्जवल है और इन्हें सरकारी जॉब के साथ-साथ अच्छे-अच्छे निजी कंपनियों में भी जॉब का सुनहरा मौका मिल रहा है. ललन प्रसाद ने बताया कि आज घरों में बिजली से चलने वाले कई तरह के इपकरण लगे हुए है, यहां तक लोग खाना पकाने के लिए भी एलपीजी गैस, और हिटर का का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन घर या ऑफिस में कभी आग लग जाती हैं तो राज्य सरकार की दमकल सेवा की मदद लेनी पड़ती हैं इतना ही नहीं लोग घबराहट में में कभी-कभी अपने शरीर को भी जला लेते हैं, बहुत कम ही संस्थानों या विभाग में आपदारोधी दस्ता को तैयार किया गया है जो आपदा की घड़ी में सुरक्षित काम कर सकें. अगर आप आग पर काबू करने के तरीकों को जानते हैं आपके घर में या पड़ोस में इतना नुकसान नहीं होगा. श्री प्रसाद ने बताया कि पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फायर सेटी मैनजमेंट इंस्च्यूट में जो भी शिक्षक है वह इच्च स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त या फिर अग्निशमन सेवा से सेवानिवृत शिक्षक है. पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फॉयर सेटी मनेजमेंट इंस्टीच्यूट में कुशल और प्रशिक्षत शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है. जो छात्रों के भविष्य के लिए संजीवनी का काम करता है. ट्रेनिंग के लिए यहां के छात्रों को टाटा मोटर्स, एलएनटी, बोकारों स्टील प्लांट, बरौनी रिफायनरी आदि जगहों पर एक महीने के लिए प्रोजक्ट तैयार करने के लिए भी भेजा जाता हैं. यह देश का पहला इंस्टीच्यूट है जहां के शिक्षकों को गेस्ट के रूप में भारत के कोनेकोने में बुलाया जाता हैं. शिक्षण व्यवस्था के बारे में पूछने पर बताया कि अभी फिलहाल में दो क्लास रूम, दो लैब तथा चार शिक्षक स्थायी तौर पर काम कर रहें हैं . हमारे यहां दो बैच चलता है एक बैच में 20 से 25 लड़कों की बैठने की व्यवस्था है. यहां से एक साल का डिप्लोमा भी किया जा सकता है. इंस्टीच्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है. और हमारे संस्थान का बस एक ही लक्ष्य है हर बेरोजगार के हाथ में नौकरी हो. – *देवेंद्र दुबे*

बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें

डॉ. एम. रहमान

बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से 17 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गयी, यह पहला मौका है जब बिहार में प्रशासनिक सेवा के लिए एक साथ 507 सीटों के लिए रिक्तियां निकाली गयी. अब खबर है कि इसमें दो तीन सौ सीट और जुड़नेवाले हैं. सिविल सेवा की तैयारी करनेवाले विद्यार्थियों के लिए इससे बेतरीन अवसर शायद ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार-बार नहीं मिलते. आयोग ने इसके लिए मुख्य परीक्षा सितम्बर को संभावित तिथि निर्धारित की है. ऐसे में, सफल होने के लिए जरूरी है कि प्रतिभागी आज से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जायें.

बताते चलें कि यह परीक्षा तीन चरणों में संपादित होती है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार. बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है. सामान्य अध्यन के प्रश्न पत्र में एक सौ पचास प्रश्न पूछे जाते हैं. जिसके लिए 150 अंक निर्धारित होता है इसके लिए कटऑफ मार्क्स पर नजर डालें तो 47 वीं परीक्षा में कटऑफ मार्क्स 99 था, जबकि 48वीं से 52 वीं के लिए यह कटऑफ मार्क्स मात्र 96 हो गया था. जानकारों का अनुमान है कि इस बार रिक्तियां अधिक होने की वजह से यह कटऑफ मार्क्स 95 से 100 के बीच होगा. चूंकि आयोग ने मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितम्बर घोषित की है, इसलिए वैसे छात्र जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के प्रति आश्वस्त हैं, अभी से ही पूरी तन्मयता के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जायें. मुख्य परीक्षा के प्रथम दिन सामान्य हिन्दी की परीक्षा होती है, जिसमें सिर्फ इतीर्ण करना होता है. यह सौ अंक का होता है, जिसके लिए इतीर्णांक तीस हैं. इस पत्र में निबंध, संक्षेपण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरालोकोक्ति, पर्यायवाची, पसर्ग, प्रत्यय आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं. इस पत्र की तैयारी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की ‘आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना’ पुस्तक बेहतर माना जाता है. प्रतिभागियों को इस पत्र को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें असफल होने की स्थिति में इनके अन्य कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. इसकी तैयारी के लिए पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न पत्र काफी सहायक साबित हो सकते हैं. मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त तीन विषय की परीक्षा देनी पड़ती है, सामान्य अध्ययन 400 अंक, प्रथम वैकल्पिक विषय 400 अंक तथा द्वितीय वैकल्पिक विषय 400 अंक का होता है. इस प्रकार मुख्य परीक्षा 1200 अंक की होती है, जिसमें इतीर्ण होने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है. साक्षात्कार 150 अंक का होता है. जहां तक पिछले परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा के लिए कटऑफ का सवाल है. 46 वीं मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 715 था, 47 वीं में य 719 जबकि 48 -52वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 742 था. लेकिन साक्षात्कार में प्राप्त अंको के भारी अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि आप अंतिम रूप से अच्छे पद पर चयनित होने के लिए 750 से अधिक अंक लाने का लक्ष्य रखें, इसके लिए संतुलित रणनीति अपनाकर अध्ययन की जरूरत है.

मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के दो पत्र होते हैं-

प्रथम पत्र- 1. भारतीय इतिास एवं संस्कृति (बिहार के विशेष संदर्भ में) 75 अंक, 2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 75 अंक, तथा 3. सांख्यिकी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं.

द्वितीय प्रश्न पत्र- 1. भारतीय राज व्यवस्था से 75 अंक, 2. भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से 75 अंक तथा 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं.

मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के लिए वैकल्पिक विषयों से अलग रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है. इसका मूल कारण यह है कि इस प्रश्न पत्र में चयनात्मक होने की प्राय: वैसी सुविधा नहीं है जैसा कि वैकल्पिक विषयों में होती है. वैसे भी विगत वर्षों की मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में किए गए परिर्वतनों को देखते हुए अब विस्तृत अध्ययन पद्धति पर चलना ही श्रेयस्कर है. मुख्य परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास लेखन शैली के स्तर पर होना चाहिए. आपको कितना ज्ञान है, आपकी विश्लेषण क्षमता कैसी है- यह सब जानने के लिए परीक्षक के पास केवल एक ही आधार होता है और वह है आपके द्वारा लिखा गया उत्तर. यदि आपकी सम्प्रेषण या अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी है तो आप अपने ज्ञान के स्तर से भी अधिक अंक पा सकते हैं. मुख्य परीक्षा के लिए जो लेखन शैली चाहिए उसमें तीन गुण आवश्यक है-स्पष्टता, क्रमबद्धता और प्रमाणिकता.

एक बात और, उत्तर में पृष्ठ भरने वाला दृष्टिकोण एकदम न रखें. मुख्य परीक्षा में संक्षिप्तता को उत्तर का गुण माना जाता है, विस्तार को नहीं. सही रणनीति बनाना और इसका पालन करना मूलत: सफलता के लिए यही दो अनिवार्य शर्त है. आशा है कि उपर्युक्त कुछ बातों से आपको अपनी अगामी परीक्षा के लिए रणनीति बनाने में सरलता महसूस होगी. और अन्त में आपसे कहना चाहूंगा

ध्येय पाने को स्वंय पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को स्वंय दूर हटाना होगा.

ओ अमावस को बुरा कहके बहकने वालों, अपने ही मन का तुझे दीप जलाना होगा.

मुख्य परीक्षा के लिए अनुशंसित पुस्तकें

भारतीय इतिहास- स्पेक्ट्रम- आधुनिक भारत तथा विपिन चन्द्रा का स्वतंत्रता संघर्ष

राजव्यवस्था - सुभाष कश्यप - हमारा संविधान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - विवास पनोरमा या स्पेक्ट्रम

न्यूज पेपर - हिन्दुस्तान तथा द हिंदू

भूगोल - टीटीएल, अथवा सुल्लर अथवा संजय सिंह अथवा महेश वर्णवाल में कोई एक पुस्तक

अर्थव्यवस्था - पन्ना लाल या रमेश सिंह (दर्पण का अतिरिक्त अवश्य देखें)

समसमायकी - क्रॉनिकल योजना, न्यूजपेपर

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्विज इस हफ्ते

1) फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है - आंग सान सू की
2) वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह किस राज्य की राज्यसभा सीट से सांसद हैं - असम
3) कोपा किस खेल से संबंधित है - फुटबॉल से
4) कौन सा स्थान ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक बना - वेस्टमिन्स्टर
5) भारत में निर्माणाधीन वह परमाणु इनर्जी संयंत्र जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं. - जैतापुर परमाणु इनर्जी सयन्त्र
6) वह राष्ट्र जहां मार्च 201 मे मैक्सिमम इंडिया नाम से सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया - अमेरिका (वाशिंगटन)
7) दक्षिण भारत का वह स्थान जहां तमिल-ब्राह्मी लिपि खुदाई के दौरान इतिहासकारों को मार्च, 2011 में प्राप्त हुई है - पत्तनम (एर्नाकुलम, केरल)
8) वह हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जिन्हें इस वर्ष मदर टेरेसा अवार्ड प्रदान किया गया - प्रेम चोपड़ा
9) वह नगर जहां विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के संगठन जी-8 के विदेश मंत्रियों को सम्मेलन मार्च 2011 में सम्पन्न हुआ - पेरिस
10) भारत का वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने मार्च 2011 में अन्तर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैचों में रिकॉर्ड अठारह हजार रन पूरे किये - सचिन तेन्दुलकर

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

समस्तीपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का सच

बड़े बचे और फुटपाथी नपे

विकास कुमार

समस्तीपुर नगर को अतिक्रमणमुक्त व्यवस्थित और सुन्दर बनाने हेतु जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई से शहर के पांच हजार से अधिक फुटपाथी दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है. पिछले दिनों जिलाधिकारी कुंदन कुमार पैदल नगर भ्रमण कर अतिक्रमण की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हुए तथा संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया. जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर की मुख्य सड़कों से फुटपाथी दुकानादारों को हटाने का चरणबद्ध अभियान चलाया गया, लेकिन शुरुआत में ही ज़िला प्रशासन को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है. बता दें कि नगर परिषद् समस्तीपुर द्वारा लगभग 2700 दुकानदारों को स्थल की बंदोबस्ती की गई है और लगभग इतनी ही संख्या में बिना बंदोबस्ती कराये भी लोग हैं जिनकी अस्थायी दुकानें सड़क पर चलती है. हालांकि जिन सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां फिर से पुरानी व्यवस्था कायम हो गई है. टुनटुनिया गुमती से लेकर स्टेशन रोड होते हुए मालगोदाम चौक तक अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस को व्यवसायियों के विरोध का सामना करना पड़ा. ज़िला मुख्यालय स्थित मुख्य सड़कों पर बड़े-बड़े भूमाफिया, सफेदपोश एवं दबंगों द्वारा अक्रिमण किया गया है, जिनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन फुटपाथी दुकानदारों पर प्रशासन का डंडा चलने के बाद इनके समर्थन में विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन की दोहरी नीति की आलोचना की है. जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से फुटपाथी दुकानदार भी काफी आक्रोशित हैं. स्टेशन रोड स्थित मिल्लत एकेडमी के पास रोजी रोजगार कर परिजनों की परवरिश करने वाले कैसर खान, अनवर आलम एवं जिला फुथपाथ व्यवसायी संघ के सचिव मो. एजाज अहमद आदि का कहना है कि मानवीय आधार पर सरकार एवं प्रशासन को कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही फुटपाथी दुकानदारों पर कार्रवाई करनी चाहिये थी. इस मामले को लेकर 26 जून को फुटपाथी दुकानदार संघ की बैठक में जिला प्रशासन से अतिक्रमण मुक्ति के पूर्व पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की गई. साथ ही संघ द्वारा आवेदन देकर प्रशासन को बताया गया कि इस अभियान में केवल छोटे दुकानदारों पर ही गाज नहीं गिरनी चाहिये बल्कि नियमों को ताक पर रखकर सर्वाजनिक स्थलों का अतिक्रमण कर बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले रसूखधारियों को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए.

कुंदन कुमार मौ. फैज आलोक कुमार मेहता अख्तरूल इस्लाम शाहीन

अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित फुटकर दुकानदारों की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन पिछले 28 जून को जिलाधिकारी से मिलकर पुनर्वास एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक यथास्थिति बनाये रखने की मांग की. साथ ही उन्होंने 1998 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मार्केट कॉम्पलेक्स का निर्माण कर दुकान उपलब्ध कराने के लिए बनी कमेटी की भी जानकारी दी. वहीं राजद के प्रदेश महासचिव सह सर्वदलीय दलों को मिलाकर गठित संयुक्त मोर्चा के संयोजक फैर्जुरहमान फैज भी खुलकर फुटपाथी दुकानदारों के समर्थन में है. रहमान का कहना है कि हम अतिक्रमण हटाने का स्वागत करते हैं लेकिन यह कार्रवाई व्यवसायी संघ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर ही होनी चाहिये थी. सच्चाई यह है कि सरकार का नियंत्रण अपने तंत्र पर से खत्म हो गया है. जिला प्रशासन अपनी असफलताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई को प्राथमिकता दे रही है. समस्तीपुर के पूर्व सांसद एवं युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मेहता भी फुटपाथी दुकानदारों पर हो रही कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि सरकार की इन नीतियों से बेरोजगारी बढ़ेगी और अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि होगी. सरकार को पहले कल-कारखाने लगाकर रोजी-रोटी के लिए बिहार से हो रहे पलायन पर रोक लगानी चाहिए. नीतीश सरकार की दूसरी पाली में भी अभी तक राज्य का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है. रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री कभी भूटान तो कभी चीन की यात्रा कर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं. यह जनता की मूलभूत समस्याओं से मुंह चुराने का प्रयास है. उन्होंन अतिक्रमण हटाने में ग़रीबों एवं रसूखधारियों दोनों के साथ समान रवैया अपनाये जाने की मांग सरकार एवं प्रशासन से की है. उनौस के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ने भी प्रभावित हुए विस्थापितों के पुर्नवास की मांग की है.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार का नं. 1 Consultancy
M.S. EDUCATIONAL TRUST
ADMISSION GUIDANCE & CAREER SOLUTION (Registered) NO DONATION CONFIRM ADMISSION
MEET OUR BEST CAREER COUNSELOR IN BIHAR — More than 551 Colleges on No Donation on Direct Admission
45 प्रतिशत PCM वाले बच्चों का एडमिशन निश्चित — ADVISED OFFERED IN : Engineering, Fashion&Media, Medical, MBA, BBA, BCA, Polytechnic, PGDM & B.Ed.
Free With Every Registration
Bihar Head Office: Maa Complex Saketpuri, Bazar Samiti, Bahadurpur, Patna Ph :0612-6560169, Fax : 0612-2673939, email : sanjay1976_singh@rediffmail.com,
website : www.mset.co.in 2) Baidhianath Atta Chakkki Jai prakash Path (Near Anup Cinema Hall) Chhapra, and also in (Siwan, Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi, Aurangabad,
Katihar, Jharkhand Office Shatabdi Tower, Shop No.-1, Second Floor Jamshedpur 0657-6508664) Admission Helpline : 9308392927, 9430292927, 9572323234